ISSN 0976-528X

सामाजिक एवं मानविकी विषय के अन्तर्गत प्रकाशित

त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध जर्नल जून-सितम्बर 2011
(संयुक्तांक)

महामहिम (कुलाधिपति) राज्यपाल श्री वी. एल. जोशी जी द्वारा विमोचित

महाविशेषांक

सिद्धांत

DOCTRINE

संपादक

डॉ. विनोद मोहन मिश्रा
डॉ. राम तिवारी

Published by :

Academic Research Society (U.P.)
एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी (उ० प्र०)

इलाहाबाद हाईकोर्ट

(लखनऊ बैंच)

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना
लखनऊ हाईकोर्ट
पूर्व जिला जज
कानपुर नगर

संदेश

मुझे हर्ष है कि सामाजिक एवं मानविकी विषय पर एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध जर्नल का प्रकाशन किया जा रहा है। ऐसे महत्त्वपूर्ण व वैश्वीकृत विषयों पर सारगर्भित लेखों द्वारा ज्ञानवर्धन किये जाने हेतु आपके सकारात्मक प्रयत्न प्रशंसा के पात्र हैं। वर्तमान समय विकास की ओर अग्रसर युवाओं का है जिसमें पत्रिका अपना विशेष योगदान प्रदान कर रही है और पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी ज्ञानवर्धन करती रहेगी।

वैज्ञानिक विषयों को सरल व बोधगम्य रीति से पाठकों तक पहुँचने से निश्चित रूप से नागरिकों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और देश में वैज्ञानिक वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) द्वारा अपेक्षित है।

मैं इस शोध जर्नल पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई व उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मंगल कामना करता हूँ।

न्यायमूर्ति

सुधीर कुमार सक्सेना

MOC/K/2011-4852.

श्रीप्रकाश जायसवाल
SRIPRAKASH JAISWAL

सत्यमेव जयते

कोयला मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF COAL
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAVAN, NEW DELHI-110001

संदेश

दिनांक 29–04–2011

प्रिय महोदय,

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ए.आर.एस. परिवार द्वारा राष्ट्रीय शोध जर्नल सिद्धान्त (DOCTRINE) प्रकाशन के एक वर्ष पूर्ण होने पर महा विशेषांक का प्रकाशन एवं सभी लेखों को वेबसाइट पर आन लाईन करने जा रहा है, आपका प्रयास सभी शोधार्थियों के शोधपरक लेखों के प्रकाशन के साथ उनके ज्ञान वर्धन में भी अमूल्य योगदान देगा।

मैं आपको एवं आपकी टीम को बधाई देता हूँ।

धन्यवाद।

आपका

(श्रीप्रकाश जायसवाल)

डा0 राम तिवारी
डा0 विनोद मोहन मिश्रा
संपादक,
एकेडमिक रिसर्च सोसाएटी उ0प्र0
1/47, आर.डी. कालोनी,
बकरमण्डी चौराहा, कर्नलगंज,
कानपुर नगर।

Room No. 353, 'A' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23384498, 23385946, 23389132, Fax : 011-23386219
Camp Office : 480, Pokharpur, Lal Bangla Cantt, Kanpur (U.P.), Tel. : 0512-2450686, 2450851, Fax : 0512-2450776

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208 024
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur - 208 024

प्रो० अशोक कुमार
कुलपति

Prof. Ashok Kumar
Vice Chancellor

दूरभाष/Phone : 91-512-2570450
फैक्स/Fax : 91-512-2570006
ई-मेल/E-mail : mamsjpr@gmail.com

सीएसजेएमयू/वीसीसी/236/2011
अगस्त 27, 2011

संदेश :

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध जर्नल अपने प्रकाशन के एक वर्ष पूर्ण करने जा रहा है । प्रकाशित जर्नल सामाजिक एवं मानविकी विषयों पर ज्ञान से परिपूर्ण है ।

जर्नल शोध पत्रों के साथ–साथ बहुआयामी विकास में सहायक सिद्ध होते हैं इसकी सार्थकता को प्रमाणित करने हेतु जर्नल में प्रकाशित होने वाली सामग्री ज्ञानवर्द्धक एवं सारगर्भित होगी ।

मेरी ईश्वर से यह कामना है कि आपका यह जर्नल नित नूतन शोध विषयों से छात्रों एवं विषय विशेषज्ञों का मार्ग दर्शन करता रहेगा ।

जर्नल के सफल एवं सशक्त प्रकाशन हेतु शुभकामनायें ।

भवदीय,

अशोक कुमार

(प्रो. अशोक कुमार)
कुलपति

डा० जी० सी० तिवारी
कुलपति

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय कानपुर-208002, उ०प्र०, भारत

पत्रांकः वीसी/ 2048 /सी-५/२०११
दिनांकः 27 अगस्त, २०११

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी, उ०प्र० द्वारा सामाजिक एवं मानविकी विषय पर त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध जर्नल का प्रकाशन गत एक वर्ष से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। प्रकाशित पत्रिका में विज्ञान एवं अन्य विधाओं से सम्बन्धित लेख बहुत ही आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक हैं। मैं सम्पादक डा० विनोद मोहन मिश्रा एवं डा० राम तिवारी द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना एवं प्रशंसा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी द्वारा पत्रिका के माध्यम से भविष्य में भी मानव जीवन से जुड़े विज्ञान के विभिन्न विषयों पर उपयोगी एवं ज्ञान वर्धक सामग्री शिक्षकों, छात्रों एवं समाज सेवियों को अनवरत प्राप्त होती रहेगी।

मैं पत्रिका के एक वर्ष अनवरत सफल प्रकाशन की पुनः बधाई देता हूँ एवं पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(जी० सी० तिवारी)
कुलपति

Tel.: 0512-2534155 (O); 9198000999 (M) e-mail: gctewari@csauk.ac.in; gctewari.csau@gmail.com

University of Allahabad

Ph. : 0532-2461663 (O)
8957829816 (M)

DR. R.K. UPADHYAYA • Professor and Head

Department of Defence and Strategic Studies • Allahabad-211002 India

संदेश

सामाजिक एवं मानविकी विषय के अन्तर्गत प्रकाशित शोध जर्नल "सिद्धान्त' के अब तक प्रकाशित सभी अंक महत्त्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं, जिन पर निरन्तर चिन्तन एवं शोध होते रहना चाहिए। "सिद्धान्त" के सभी अंकों में राष्ट्रीय संरक्षा, सुरक्षा एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो सराहनीय है। बदलती परिस्थितियों में उपरोक्त तीनों विषयवस्तु अत्यन्त प्रभावी हैं अतः निरन्तर इन विषयों को केन्द्र में रखकर अलग–अलग प्रकार से यदि शोध होते रहेंगे, तो भारत देश अपने साथ–साथ सम्पूर्ण विश्व को दिशा देता रहेगा।

"सिद्धान्त" जर्नल के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारा आशीर्वाद "उत्तरोत्तर प्रगति हो।" ऐसी मेरी शुभकामना।

प्रो. (डॉ.) आर. के. उपाध्याय
Professor and Head
DEPT. OF DEFENCE & STRATEGIC STUDIES
UNIVERSITY OF ALLAHABAD

6-H, Bank Road, Allahabad

मानस संगम

कार्यालय :
मानस संगम (पंजी०)
३८/२४, प्रयाग नारायण शिवाला
कानपुर- २०८ ००१ (भारत)
फोन : २३६२६७८ (मो०) ९८३६०३०११८

OFFICE :
MANAS SANGAM (REGD.)
38/24, PRAYAG NARAIN SHIWALA
KANPUR - 208 001 (INDIA)
PHONE : 2362678, (MOB.) 9839030118

संयोजक / अध्यक्ष :
बद्री नारायण तिवारी

राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित भारत की प्रमुख साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था
A marked Literary, Cultural & Social Organisation of India Dedicated to National Integration

संदेश

राष्ट्रीय शोध जर्नल "सिद्धान्त" विशिष्ट शोध पत्रों का संग्रह होने के कारण सामान्य जन से लेकर विशिष्ट जन तक के मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है जिस कारण लोगों में प्रत्येक आगामी अंक के प्रति जिज्ञासा रहती है।

इस सफल प्रयास के दूरगामी सकारात्मक परिणाम हों। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है।

'सिद्धान्त' जर्नल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर मेरी शुभकामना एवं आशीर्वाद!

आपका

(डॉ. बद्रीनारायण तिवारी)

सत्यमेव जयते

कृष्ण कुमार यादव, भा. डा. से.
निदेशक डाक सेवा
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
पोर्ट ब्लेयर - 744 101

Krishna Kumar Yadav, IPS
Director Postal Services
Andaman & Nicobar Islands
Port Blair - 744 101

भारतीय डाक
India Post

30 मई 2011

संदेश

यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी, उ. प्र. द्वारा सामाजिक एवं मानविकी विषयों पर आधारित द्विभाषी जर्नल 'सिद्धान्त' (Doctrine) के प्रकाशन के एक वर्ष पूर्ण हो गये हैं। इस जर्नल ने अल्प समय में ही अपनी एक प्रतिष्ठित पहचान कायम की है, जिसके लिए संपादक द्वय बधाई के पात्र हैं।

इस अवसर को यादगार बनाने हेतु जर्नल 'सिद्धान्त' (Doctrine) द्वारा एक 'महा विशेषांक' अंक का प्रकाशन भी किया जा रहा है। इस 'महा विशेषांक' में ऐसे तमाम शोध–लेख व रचनाएँ प्रकाशित होंगी जो समकालीन समाज व मानवीय जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। आशा की जानी चाहिए कि यह 'महा विशेषांक' अकादमिक व बौद्धिक स्तर पर विमर्शों को बढ़ावा देने में सकारात्मक पहल करेगा।

एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी, उ0 प्र0 द्वारा प्रकाशित जर्नल 'सिद्धान्त' (Doctrine) के सोद्देश्यपूर्ण प्रकाशन के एक वर्ष पूरे होने और 'महा विशेषांक' के प्रकाशन पर शुभकामनाएँ।

भवनिष्ठ

(कृष्ण कुमार यादव)

सेवा में,

डॉ. राम तिवारी
संपादक – सिद्धान्त (Doctrine)
कानपुर (उ0 प्र0)

Phone: 03192-230485 (O) Fax: 03192-231036 ❖ e-mail: dps_an@rediffmail.com

SCIENCE & TECHNOLOGY ENTREPRENEURS' PARK
(A Govt. of India Society Funded by DST, IDBI, IFCI, ICICI, CBI and Govt. of U.P.)
HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL INSTITUTE
KANPUR - 208 002
Phone : 2560831, 2562536, 2563016 • Fax : 0512 - 2562536

संदेश

सेवा में,
सम्पादक (सिद्धान्त)
राष्ट्रीय शोध जर्नल
एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी (उ0 प्र0)

महोदय,

आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास राष्ट्रीय शोध जर्नल 'सिद्धान्त' निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपने एक वर्ष पूर्ण कर रहा है। इसमें प्रकाशित शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से सामाजिक एवं मानविकी विषय से जुड़े लोगों को एक नयी दिशा एवं दशा प्रदान कर रहे हैं जो सराहनीय है।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संरक्षक मण्डल सदस्य के रूप में आपको निरन्तर सकारात्मक सहयोग प्रदान करता रहूँगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

(प्रो0 आर0 के त्रिवेदी)
निदेशक

दिनांक : 18–07–2011

Phone & Fax : 0512-2330413
e-mail : bndkanpur@gmail.com
website : www.brahmanandcollege.org

ब्रह्मानन्द कालेज, कानपुर
Brahmanand College, Kanpur

Controlled & Managed By - THE KANYAKUBJA EDUCATION TRUST, Registered under Act XXI of 1860

संदेश

ए. आर. एस. परिवार का सदस्य होने के नाते एवं राष्ट्रीय जर्नल **''सिद्धान्त''** से सीधा जुड़ा होने के कारण मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय शोध–जर्नल ''सिद्धान्त'' राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास में भागीदार बने तथा इसमें प्रकाशित सभी शोध–पत्र शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं ऊर्जा सम्पन्न छात्र–छात्राओं के ज्ञानार्जन में सहायक हो और राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाये।

राष्ट्रीय शोध–जर्नल ''सिद्धान्त'' के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर बहुत सारी शुभकामनाएँ।

आपका

डॉ. विवेक द्विवेदी
प्राचार्य
बी. एन. डी. महाविद्यालय
कानपुर

(Recognized by U.P. Board Allahabad)
☎ :– 2537193, 3218662
Fax :– 0512–2557881
ONKARESHWAR SARASWATI VIDYA NIKETAN INTER COLLEGE
109/194, JAWAHAR NAGAR, KANPUR

संदेश

सेवा में,

सम्पादक

सिद्धान्त (राष्ट्रीय शोध जर्नल)

महोदय

एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शोध जर्नल ''सिद्धान्त'' की सफलतापूर्वक सम्पादन के एक वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं इस जर्नल के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ।

संरक्षक मण्डल से जुड़ा होने के कारण हमारा सहयोग आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा।

राम मिलन सिंह
(प्रधानाचार्य)
Principal
Onkareshwar S.V.N.I.C
Jawahar Nagar, Kan

Gram : Brahm Bank

रजि0 नं0 2735

ब्रह्मावर्त कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड आफिस :
90, एम.आई.जी.,
रतनलाल नगर, कानपुर

फोन : 2280226, 2280018
फैक्स : 0512-2283593
ई-मेल : bankbcc@vsnl.net

.....शाखा

संदेश

एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी (उ0 प्र0) द्वारा प्रकाशित शोध जर्नल ''सिद्धान्त'' में प्रकाशित विद्वानों के शोध पत्र पिछले एक वर्ष में शोध छात्रों एवं विषय विशेषज्ञों का पर्याप्त मार्गदर्शन कर रहे हैं।

ए0 आर0 एस0 परिवार की सदस्या होने के कारण मैं ''सिद्धान्त'' जर्नल की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती हूँ।

श्रीमती किरन मिश्रा
(उप महाप्रबन्धक)

BRAHMAVART COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LTD. 90 M.I.G. RATAN LAL NAGAR KANPUR

संपादकीय .....

सम्पूर्ण विश्व में सभी चीजें चलायमान हैं अगर चलायमान नहीं तो केवल दो 'सिद्धान्त' पहला 'आचार' दूसरा 'अनाचार'। यह सिर्फ अपना स्वरूप परिवर्तित करते हैं किन्तु 'सिद्धान्ततः' यही दोनो ही रहते हैं। दुनियां में जितने भी पर्व–त्योहार हैं वह सभी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित हैं। अच्छाई एवं बुराई का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कभी–कभी विद्वान् भी इसका विश्लेषण करते समय अपनी दिशा से भटक जाते हैं। किसी को अपने सुख के लिए किसी की हत्या करना पाप है अपनी सुविधा के लिए किसी के अधिकारों का अतिक्रमण पाप है, किन्तु देश एवं काल की परिस्थितियों में राज्य विस्तार एवं दासत्व की प्रथा, शूरवीरता की श्रेणी में आती थी। देश में अमीरों के लिए अलग कानून होते हैं, गरीबों के लिए अलग कानून होते हैं। दोनों की स्वतन्त्रता की सीमाएँ अलग होती हैं और शोषण का अधिकार हमेशा से अमीरों के पास, अभिजात्य वर्ग के पास सुरक्षित है। अच्छी बातों को बताने का अधिकार भी उनके पास सुरक्षित है जिसमें उनका हित हमेशा जुड़ा रहता है, किन्तु भगवान के पास जो सिद्धान्त है उसकी सीमाएँ, मर्यादाएँ और नियम एक है वह है 'जियो एवं जीने दो'। अपनी निश्चित सीमाओं का पालन ही ईश्वर की इच्छा में सदाचार है। इस सम्बन्ध में एक विद्वानजन द्वारा प्रस्तुत कथानक बडा ही प्रासंगिक प्रतीत होता है –

एक राजा एवं रानी एक राज्य में राज्य करते थे, प्रजा उनसे पूर्ण सन्तुष्ट थी उन्होंने अपने जीवन में दान को ही अपना धर्म बना लिया था। प्रातःकाल से रात्रि काल तक राजा अपने पास आने वाले प्रत्येक इच्छुक को कुछ न कुछ दान करता रहता था। दान धर्म का आचरण राजा को इतना अच्छा लगा कि वह राज्य धर्म के अन्य आचरणों से विमुख हो गया। दान में पात्र एवं कुपात्र का ध्यान भी नहीं रहा। राजा एवं रानी इतने भाव विह्वल हो गये कि मन्त्री एवं जिम्मेदार अधिकारी भी राजकोष से दान प्राप्त करने लगे। राजकोष में संकलित धन जो राज्य की 'सुरक्षा' के लिए, 'संरक्षा' के लिए एवं 'शिक्षा' के लिए आवश्यक था। वह दान में जाने लगा पड़ोसी राजा को इसकी खबर लगी उसने परिस्थितियों का लाभ उठाया और राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य में उसका कब्जा हो गया। राजा, रानी जो फूलों की सेज एवं सुख सुविधाओं के केन्द्र बिन्दु थे। अपने राज्य की काल कोठरी में डाल दिये गये। राजा, रानी बहुत चिन्तित हो गये, कुंठित हो गये। उन्हें अपने दान–पुण्य का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा था। वे रोते एवं चिल्लाते रहते थे। एक दिन बंदी गृह प्रमुख को उन पर दया आ गयी। पूर्व में वह राजा का सेवक भी था। उसने राजा, रानी को एक दिन भागने का अवसर प्रदान कर दिया। राजा, रानी दिन भर भागते रहे एवं अपने राज्य की सीमा से दूर एक स्थान पर शरण ली। भूख एवं प्यास से व्याकुल राजा, रानी ने जंगल से लकड़ी तोड़ी। पूरे दिन में केवल इतनी लकड़ी तोड़ पाये जिसके बदले में उन्हें इतनी आय मिली जिसमें चार रोटी ही बनीं। दो राजा ने लीं, दो रानी ने लीं। इतने में एक भूखा व्यक्ति सामने आ गया। राजा ने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए अपनी दोनो रोटी उसे दे दी। रानी ने पत्नी धर्म का पालन करते हुए एक रोटी राजा को दी एवं एक रोटी स्वयं खाई। दिन इसी तरह बीतने लगे। राजा को एक दिन यह ज्ञात हुआ कि सुदूरवर्ती राज्य में एक सेठ है। वह पुण्य खरीदता है। राजा को लगा कि वह पूरे जीवन पुण्य ही करता रहा है। रोज–रोज मेहनत करते रहने से क्या लाभ, अपने

जीवन का कुछ पुण्य बेच दें। वह रानी के साथ अपना पुण्य बेचने सेठ के पास पहुँच गया। सेठ को उन्हें देख कर ही उनकी स्थिति के बारे में पता लग गया, उसने तुरन्त धर्मकांटा लगवाया। राजा को आदेशित किया कि अपना पुण्य यादकर उसे तराजू के एक पलड़े में रखे। उसके बराबर अशर्फी तौल दी जायेगी। राजा ने पूरे जीवन का पुण्य तराजू में रख दिया, किन्तु काँटा जरा भी नहीं हिला। राजा रोने लगा एवं सेठ के प्रति अविश्वास व्यक्त करने लगा। सेठ ने कहा राजा मैं तुम्हारी व्यथा जानता हूँ। तुमने जो भी दान दिया, वह निष्फल हो गया है, तुम कोई एक ऐसा दान याद करो, जो तुम्हारे अपने श्रम के बाद किया गया हो, शायद तुम्हारा काम हो जाये। राजा को कारागार से भागने के बाद प्रथम दिन की दो रोटियों का दिया गया दान याद आया। राजा ने उस दान का पुण्य जैसे ही धर्म काँटे के एक पलड़े पर रखा, उसके दूसरे पलड़े में पच्चीस हजार बोरे सोने की अशर्फी चढ़ गयीं। राजा आश्चर्य में पड़ गया। सेठ से बोला, हे राज सेठ! 'पूरा जीवन दान बनाम दो रोटी विपदा में दान' अधिक उपयुक्त कैसे हो गया? सेठ ने कहा, हे राजन्, राजकोष का धन तुम्हारी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी। उस पर राज्य की सुरक्षा, शिक्षा, संरक्षा का भार था, किन्तु वह तुमने बिना समझे दान किया, जो पुण्य नहीं अपराध है, वह तुम्हारी व्यक्तिगत सम्पति नहीं हो सकती है, न ही दान के योग्य थी, किन्तु तुमने जो अपने हिस्से की श्रम की रोटी भूखे व्यक्ति को दी थी, वह तुम्हारा श्रेष्ठ दान था, अतः राजा जाओ, इससे प्राप्त धन से पुनः अपना राज्य प्राप्त करो, लेकिन ध्यान रहे राजकोष राजा की सम्पत्ति नहीं, राज्य का अपना कोष है। हर नागरिक का स्वतः उस पर अधिकार है। उसे उसके शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा पर खर्च करना।

यह प्रसंग आज इस प्रकार हमारे द्वारा इस अंक में इस कारण प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि वह इस बात का द्योतक है कि जब–जब अभिजात्य वर्ग, शासक वर्ग देश में अनाचार का आचरण करेगा तो कोई न कोई 'अन्ना हजारे' बनेगा और 'जनता' उसकी लाठी बनेगी। सत्ता से जनता की दूरी बढ़ेगी अर्थात् सत्ता इस बात की प्रतीक बनेगी, जो जनता के हितों के प्रति असंवेदनशील है। अतः देश की एकता, अखण्डता एवं विकास के लिए जनता के राजकोष का उपयोग जनता के लिए ही किया जाये, देश की सीमाएँ जनता के धन से सुरक्षित हैं, अतः देश के विकास हेतु भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण ही अत्यन्त आवश्यक है।

"सिद्धान्त" जर्नल का एक वर्ष पूर्ण हो गया है। इस हेतु आप सभी की मंगल कामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि "सिद्धान्त" जर्नल उत्तरोत्तर राष्ट्र के विकास में सहभागी बना रहेगा। इसमें विद्वानों के दिये गये महत्त्वपूर्ण शोधपत्र देश के विकास में सहभागी होंगे।

"आपके आशीष का एक दीपक
जलता रहे हमेशा सदा
इसके आलोक में चलते रहें,
भटके न दिशा हम यदा कदा।।"

प्रस्तुत अंक में विचार/शोधपूर्ण लेख लेखकों के स्वयं के हैं, उसके सम्बन्ध में जर्नल का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इस अंक के प्रति विचार एवं सुझाव हमें अवश्य भेजें, उन्हें अगले अंक में "अभिमत" कालम में प्रकाशित किया जायेगा।

आपका
-डॉ० विनोद मोहन मिश्रा
डॉ० राम तिवारी

संपादक - मण्डल

1. **डॉ० (मेजर) संतोष कुमार सिंह सेंगर**
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
वी0एस0एस0डी0 महाविद्यालय, कानपुर

2. **डॉ० गोविन्द सिंह**
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
वी0एस0एस0डी0 महाविद्यालय, कानपुर

3. **डॉ० (मेजर) इन्द्रजीत सिंह**
रीडर एवं अध्यक्ष
सैन्य अध्ययन विभाग
पी0पी0एन0 महाविद्यालय, कानपुर

4. **डॉ० अशोक कुमार तिवारी**
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
वी0एस0एस0डी0 महाविद्यालय, कानपुर

5. **डॉ० ममता दीक्षित**
असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर ग्रेड)
शिक्षाशास्त्र विभाग
महिला महाविद्यालय, कानपुर

6. **डॉ० देवेश चन्द्र कटियार**
एसोसिएट प्रोफेसर
सैन्य अध्ययन विभाग
पी0पी0एन0 महाविद्यालय, कानपुर

7. **डॉ० अजय कुमार सिंह**
वरिष्ठ प्रवक्ता
सैन्य अध्ययन विभाग
पी0पी0एन0 महाविद्यालय, कानपुर

8. **डॉ० जय शंकर पाण्डेय**
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
डी0ए–वी0 महाविद्यालय, कानपुर

9. **डॉ० अनूप सिंह**
असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर ग्रेड)
समाजशास्त्र विभाग
डी0ए–वी0 महाविद्यालय, कानपुर

10. **डॉ० मनोज अवस्थी**
एसोसिएट प्रोफेसर
वाणिज्य विभाग
वी0एस0एस0डी0 महाविद्यालय, कानपुर

11. **डॉ० नीलम त्रिवेदी**
एसोसिएट प्रोफेसर
डी0जी0 महाविद्यालय, कानपुर

12. **डॉ० पुष्पा वर्मा**
एसोसिएट प्रोफेसर
डी0सी0लॉ0 महाविद्यालय, कानपुर

संपादकीय परामर्शदाता मण्डल

1. **प्रोफेसर (डॉ०) राजकुमार उपाध्याय**
विभागाध्यक्ष
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. **डॉ० सुरेन्द्र कुमार मिश्रा**
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
सैन्य अध्ययन विभाग
गर्वनमेण्ट पी0जी0 कालेज, हिसार (हरियाणा)

3. **डॉ० रामसूरत पाण्डेय**
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा अध्ययन विभाग
लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा

4. **डॉ० विजेन्द्र सिंह**
विभागाध्यक्ष
सैन्य अध्ययन विभाग
सकलडीहा पी0जी0 कालेज सकलडीहा, चंदौली
वाराणसी

5. **डॉ० अरविन्द कुमार चतुर्वेदी**
एसोसिएट प्रोफेसर
सैन्य अध्ययन विभाग
गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुल्तानपुर

6. **डॉ० संजय कुमार**
वरिष्ठ प्रवक्ता
सैन्य अध्ययन विभाग
मेरठ कालेज, मेरठ

7. **डॉ० नर्वदेश्वर शुक्ला**
विभागाध्यक्ष
सैन्य विज्ञान विभाग
एल0एस0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पिथौरागढ़ (उ0 प्र0)

8. **डॉ० एस० एन० राय**
विभागाध्यक्ष
सैन्य अध्ययन विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

9. **डॉ० धीरेन्द्र द्विवेदी**
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
ईश्वर शरण डिग्री कालेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. **डॉ० गिरीश कांत पाण्डेय**
विभागाध्यक्ष,
रक्षा अध्ययन विभाग
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान
महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

11. **डॉ० देवदत्त शर्मा**
एसोसिएट प्रोफेसर
विधि विभाग
डी0ए–वी0 कालेज, लखनऊ

12. **डॉ० अमित सिंह**
एसोसिएट प्रोफेसर
विधि विभाग
महात्मा ज्योतिबा फूले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

13. **डॉ० दीर्घपाल सिंह भंडारी**
विभागाध्यक्ष
सैन्य विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नई टिहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

14. **डॉ० संजय राय**
एसोसिएट प्रोफेसर
समाज कार्य विभाग
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
नई दिल्ली

14. **डॉ० ध्रुवज्योति कुमार सिंह**
असिस्टेंट प्रोफेसर
मैथिली विभाग
साहबगंज कालेज (सम्बद्ध एस0के0एम0
विश्वविद्यालय) दुमका, झारखण्ड

संरक्षक - मण्डल

- **डॉ० बद्री नारायण तिवारी**
  अध्यक्ष,
  मानस संगम

- **डॉ० जे० एन० गुप्ता**
  CEO दैनिक जागरण एजूकेशन
  फाउन्डेशन एवं पूर्व चेयरमैन स्टाक
  एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश

- **डॉ० आर. के. त्रिवेदी**
  निदेशक
  एच० बी० टी० आई० (स्टेप)
  नवाबगंज, कानपुर

- **डॉ० रमेशचन्द्र शर्मा**
  पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर
  हिन्दी विभाग
  बी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर

- **श्रीमती किरन मिश्रा**
  उप–महाप्रबन्धक
  ब्रह्मवर्त कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक
  लिमिटेड, कानपुर

- **श्रीमती पुष्पलता सिंह**
  प्रधानाचार्या
  डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक
  स्कूल, कानपुर

- **ई० आर० डी० पाण्डेय**
  विशेष कार्याधिकारी
  केस्को, कानपुर

- **डॉ० नंदिनी रस्तोगी**
  प्रख्यात चिकित्सक
  कानपुर नगर

- **प्रो० (डॉ०) आर० सी० गुप्ता**
  अध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग
  कानपुर मेडिकल कालेज
  कानपुर

- **प्रो० सर्वज्ञ सिंह कटियार**
  पद्मश्री एवं पद्म विभूषण
  पूर्व कुलपति
  छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
  कानपुर

- **श्री के० के० यादव (आई० पी० एस०)**
  निदेशक, डाक सेवा
  अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर

- **डॉ० विवेक द्विवेदी**
  प्राचार्य
  बी० एन० डी० महाविद्यालय, कानपुर

- **श्री अंकुश शुक्ला**
  भाई साहब (दैनिक जागरण)
  प्रख्यात व्यंग्य कार्टूनिस्ट, कानपुर

- **डॉ० अरविन्द अरोड़ा**
  प्रख्यात लेखक एवं
  पूर्व चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक)
  कानपुर

- **श्री प्रकाश नारायण बाजपेई**
  प्रधानाचार्य
  पं० दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज
  कानपुर

- **डॉ० डी० के० सिन्हा**
  प्रख्यात चिकित्सक
  संस्थापक, कानपुर किडनी फाउन्डेशन
  कानपुर

- **प्रो० (डॉ०) एस० के० अरोड़ा**
  त्वचा रोग विशेषज्ञ
  कानपुर मेडिकल कालेज, कानपुर

- **डॉ० एस० पी० तिवारी**
  पूर्व प्रधानाचार्य
  आर० एस० जी० यू० डिग्री कालेज
  पुखरायाँ

- **श्री साहब लाल मौर्या**
  रजिस्टार
  महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
  विश्वविद्यालय, वाराणसी

- **श्री योगेन्द्र स्वरूप (एड०)**
  सचिव, पी० पी० एन० मेमोरियल सोसाइटी,
  कानपुर, वर्तमान सदस्य एवं पूर्व
  अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल

- **डॉ० रेनू निगम**
  एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
  संगीत विभाग,
  ए० एन० डी० कालेज, कानपुर

- **डॉ० अरुण कुमार दीक्षित**
  प्राचार्य
  श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज,
  अलीगढ़

- **श्री राम मिलन सिंह**
  प्रधानाचार्य
  ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन
  इण्टर कालेज, कानपुर

- **श्री रमेश कुमार पाण्डेय**
  चेयरमैन
  विजन ग्रुप ऑफ इंजीनिरिंग एण्ड
  मैनेजमैण्ट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश

- **डॉ० एम० के० खरे**
  पूर्व चिकित्सा अधिकारी
  एवं प्रबन्धक सीता पैथोलॉजी,
  स्वरूप नगर, कानपुर

- **प्रो० (डॉ०) संजय रस्तोगी**
  वरिष्ठ चिकित्सक
  सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कानपुर

- **श्री राजू सेठ**
  प्रख्यात छायाकार एवं प्रबन्धक
  वाहु कलर लैब सोमदत्त प्लाजा,
  कानपुर

संरक्षक - मण्डल

- **प्रो० सर्वज्ञ सिंह कटियार**
  पद्मश्री एवं पद्म विभूषण
  पूर्व कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज
  विश्वविद्यालय, कानपुर
- **डॉ० बद्री नारायण तिवारी**
  अध्यक्ष,
  मानस संगम
- **डॉ० जे० एन० गुप्ता**
  CEO दैनिक जागरण एजूकेशन
  फाउन्डेशन एवं पूर्व चेयरमैन स्टाक
  एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश
- **डॉ० आर. के. त्रिवेदी**
  निदेशक
  एच० बी० टी० आई० (स्टेप)
  नवाबगंज, कानपुर
- **डॉ० रमेशचन्द्र शर्मा**
  पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर
  हिन्दी विभाग
  बी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर
- **श्रीमती किरन मिश्रा**
  उप महाप्रबन्धक
  ब्रह्मवर्त कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक
  लिमिटेड, कानपुर
- **श्रीमती पुष्पलता सिंह**
  प्रधानाचार्या
  डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक
  स्कूल, कानपुर
- **ई० आर० डी० पाण्डेय**
  विशेष कार्याधिकारी
  केस्को, कानपुर
- **डॉ० नंदिनी रस्तोगी**
  प्रख्यात चिकित्सक
  कानपुर नगर
- **डॉ० विवेक द्विवेदी**
  प्राचार्य
  बी० एन० डी० महाविद्यालय, कानपुर
- **श्री के० के० यादव (आई० पी० एस०)**
  निदेशक, डाक सेवा
  अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर
- **श्री अंकुश शुक्ला**
  भाई साहब (दैनिक जागरण)
  प्रख्यात व्यंग्य कार्टूनिस्ट
- **डॉ० अरविन्द अरोड़ा**
  प्रख्यात लेखक एवं
  पूर्व चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक)
  कानपुर
- **श्री प्रकाश नारायण बाजपेई**
  प्रधानाचार्य
  पं० दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज
  कानपुर
- **डॉ० डी० के० सिन्हा**
  प्रख्यात चिकित्सक
  संस्थापक, कानपुर किडनी फाउन्डेशन
  कानपुर
- **प्रो० (डॉ०) एस० के० अरोड़ा**
  त्वचा रोग विशेषज्ञ
  कानपुर मेडिकल कालेज, कानपुर
- **डॉ० एस० पी० तिवारी**
  पूर्व प्रधानाचार्य
  आर० एस० जी० यू० डिग्री कालेज
  पुखरायाँ
- **प्रो० (डॉ०) आर० सी० गुप्ता**
  अध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग
  कानपुर मेडिकल कालेज
  कानपुर
- **श्री साहब लाल मौर्या**
  रजिस्टार
  महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
  विश्वविद्यालय, वाराणसी
- **श्री योगेन्द्र स्वरूप (एड०)**
  सचिव, पी० पी० एन० मेमोरियल सोसाइटी,
  कानपुर, वर्तमान सदस्य एवं पूर्व
  अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल
- **डॉ० रेनू निगम**
  एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
  संगीत विभाग,
  ए० एन० डी० कालेज, कानपुर
- **डॉ० अरुण कुमार दीक्षित**
  प्राचार्य
  श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज,
  अलीगढ़
- **श्री राम मिलन सिंह**
  प्रधानाचार्य
  ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन
  इण्टर कालेज, कानपुर
- **श्री रमेश कुमार पाण्डेय**
  चेयरमैन
  विजन ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड
  मैनेजमैण्ट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश
- **डॉ० एम० के० खरे**
  पूर्व चिकित्सा अधिकारी
  एवं प्रबन्धक सीता पैथोलॉजी,
  स्वरूप नगर, कानपुर
- **प्रो० (डॉ०) संजय रस्तोगी**
  वरिष्ठ चिकित्सक
  सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कानपुर
- **श्री राजू सेठ**
  प्रख्यात छायाकार एवं प्रबन्धक
  वाहु कलर लैब सोमदत्त प्लाजा,
  कानपुर

विवरणिका DOCTRINE

	लेख	पृष्ठ सं०
1-	**A CRITICAL ANALYSIS : INTERNAL SECURITY OF INDIA** Dr. S.K.S. Sengar Dr. Govind Singh	**1**
2-	**TERRORISM : CHALLEGE OF PEACE AND SECURITY** Dr. S.K. Mishra	**5**
3-	**IPR IN DEFENCE DEALS** Dr. Shri Bhagwan Singh Dr. Harsh Kumar Sinha	**11**
4-	**SINGAPORE - A ROLE MODEL OF GOOD GOVERNANCE** Dr. Manju Srivastava	**18**
5-	**INDIA AGAINST CORRUPTION** Dr. Pushpa Mishra	**23**
6-	**CONTENT'S OF CIGARETTE AND TOBACCO** Dr. Anuradha Tiwari	**25**
7-	क्या हिन्दी का विकास रुकेगा? डॉ. बद्री नारायण तिवारी	**28**
8-	वर्तमान शिक्षा : व्यवस्था का यथार्थ कृष्ण कुमार यादव,(आई.पी.एस.)	35
9-	समकालीन कविता में अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सन्दर्भ युद्ध एवं आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में डॉ0 राकेश शुक्ल	43
10-	नेपाल में आई0एस0आई0 की भूमिका और भारतीय सुरक्षा डॉ0 दीर्घपाल सिंह भण्डारी डॉ0 दीपेन्द्र सिंह तोपवाल	48

11- भूमण्डलीकरण तथा भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ 54
डॉ0 ममता दीक्षित

12- धार्मिक हठधर्मिता द्वारा आतंकवाद का पोषण 58
डॉ0 (मेजर) इन्द्रजीत सिंह
डॉ. कुलदीप भारद्वाज

13- **पाकिस्तान की आन्तरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद** 66
डॉ0 अशोक कुमार तिवारी

14- भारत चीन सम्बन्ध : अतीत एवं वर्तमान सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में 71
डॉ0 देवेश चन्द्र कटियार
कु0 कंचन राजपूत

15- वैश्विक तापवृद्धि एवं जलवायु–परिवर्तनः एक भौगोलिक विवेचन 77
डा0 आर0के0 चौरसिया
रोहित कुमार

16- परमाणु ऊर्जा और भारत की सुरक्षा 85
डॉ0 विनोद मोहन मिश्र
डॉ0 राम तिवारी

17- मादक पदार्थ आधारित आतंकवाद में अफगानिस्तान की भूमिका 89
विशाल दुबे

18- मानवाधिकार : सतत संघर्षों से प्राप्त अधिकार 95
डॉ0 शशि शेखर मिश्र

A CRITICAL ANALYSIS : INTERNAL SECURITY OF INDIA

-Dr. (Major) S. K. S. Sengar
Associate Professor & Head
Department of Defence & Strategic Studies
V.S.S.D. College, Kanpur

-Dr. Govind Singh
Associate Professor
Department of Defence & Strategic Studies
V.S.S.D. College, Kanpur

We have modern weapon and the new weapon systems. But the best use of them will always depend on how appropriate our strategies are. Over the years, defence and development, capabilities and resources, power and purpose have often been hotly debated by statesmen, policy-makers and strategic thinkers.

India's defence and security needs have to be restructured in terms of policy planning, management and strategic doctrines in the context o emerging new security concepts and strategic premises will have to be replaced by new ones. How? Let us first discuss the concept of national security and its myriad dimensions.

National Security

What is national security? What are its components? Does national security represent a coherent and composite character of social values? Let us define the very concept of security while applying it to the Indian context. It is necessary to do so because Indian social scientists and defence analysts, while ignoring the indigenous social and cultural ethos, have not only borrowed its narrow definition from the west but have also been misapplying them to the Indian situation.

The Indian society is a typical multi-cultural, multi-lingual, multi-caste, multi-faith society with unidentifiable mystical psyche, aesthetic tastes and complex traditional moorings.

The term security is multi-dimensional. Its meaning, interpretations and scope are too vast, too diffused and diversified to be precisely defined. Doubtlessly, it encompasses virtually every thing ranging from issues in physical, material, social economic and cultural security through ecological and environmental harmony to issues in gender, governance, development and human rights. In the post-Cold War scenario, the "state is being not only eroded but also fundamentally transformed with a wider structural context" And that context is the globalization process which may be defined as "a set of economic character of the goods and assets and comprise the base of the international political economy-in particular, the increasing structural differentiation of those goods and assets."

Security for Whom?

The metaphysics of security springs from each individual's innate urge to defend himself against imaginary, fanciful or real threats. The "inner necessity" and impulses of each individual are guided in undersigned destination.

In the theory of security catharsis, the conception of human behaviour, in different cultural settings, will have to be recognized. For after all, all state or non-state efforts at maximizing the security will depend upon the quality of human beings; and the quality of human beings will depend largely upon human conditions. Unless human conditions appropriate to social and cultural integration are improved, national security will continue to be jeopardized.

National Security and Domestic Milieu

India's domestic security environment is volatile, and is fraught with political and economic turmoil, In the absence of political stability, especially at the centre, internal law and order problem becomes complex. Political instability adversely order affects the functioning of our major institutions that form the bedrock of our policy. Bureaucracy often tends to become sluggish, perverse and insensitive to common man's aspirations. It is a patent fact that political instability encourages bureaucracy to be over-centralized.

Moreover, the situation in 1970s is much qualitatively different from 1980s and 1990s. No Government has been able to provide security to a common man in the face of rising terrorism or militancy that we have been witnessing in the Punjab, Jammu and Kashmir, Assam and Mizoran states. Despite inducting the services of the army, of security forces, and also turning some of the states virtually into ,military barracks, there is no respite in violence and blood shed. National security cannot be guaranteed by merely employing police or armed forces. This has to be viewed from sociological, economic and psychological stand point. Human problems do not exist in a vacuum. They are inextricably linked with socio-economic issues confronting the country. For ensuring national security, the Indian Government will have to redefine its redefine its priorities, redesign its policies and programmes, ultimately relating them to their economic conditions.

Concept of Social Security

The concept of social security has not yet germinated in bureaucratic states of South Asia. Social security programmes have not systematically been conceived, developed and articulated to give expression to social aspirations of the people. "The logic of state runs writ large contrary to the logic of society". This is primarily due to the lack of state's concern to identify social tensions breeding on account of "iniquitous distribution of the developmental cake".

Conceptual Parameters

The conceptual level of analysis deals with the abstract component of policy actors' decision-making calculus regarding the polarity of power structures and the propensity of one's rivals for taking risks in a volatile security scenario. A host of scholars have adopted different models. Garce Iusi Scarboraough has set forth a model of "incremental decision-making in crisis situation". It is a significant departure from a systemic level approach while examining the linkage between "polarization" and "conflict". Scarborough is of the view that such an approach is more an indicator of "war-proneness of the system" rather than about "decision-making by a national leader in the face of uncertainty regarding the behaviour of states in poles". Another scholar Robert E. Kuenne has chosen the concept of "autonomous uncertainty" to apply it to rivalrous environment in international politics". Both approaches are still relevant in the changed contextual parameters of power structures at global or regional level.

Rethinking National Security

In a fast changing international system, India's defence planners will have to rethink over national security both in conceptual as well as functional terms.

The NSC was established in August 1990, along with National Security Advisory Board. Ever since its first meeting (Oct. 1990), neither the Council nor the Board has met so far. This shows the lack of interest on the part of the Central government. Parry it was due to political instability in the beginning of early 1990s, and partly because the Rao- government was engaged in the economic reform programme. When the new UF government came to power at the end of May 1996, efforts were made to reactivate the NSC.

The idea of setting up of a National Security Council as an apex body to purvey necessary inputs and wide options, was mooted by the then Prime Minister V.P. Singh. The idea was actively supported by non-establishment officials, defence and foreign policy experts on a indentitical pattern of the US National Security Council. But top officials of the foreign policy establishment evinced no keen interest.

The composition of the NSC, unless its character is dramatically altered, makes it unambiguously clear that due to the upper hand of ministers of certain key departments in the final decision-making, will scarcely permit academics and defence experts to have any decisive say in evolving alternative options and strategies to deal with internal or external threats. The marginalisaton of the Policy Planning Division (PPD) of established with the basic objective of taking a broader approach to foreign policy and international issues so that it could suggest a broad range of policy options. But due to lack of interest shown by the ministry, public bureaucrats' contributions remain dormant.

Reconciliation approach can be more efficacious in dealing with the ethnic strife, religious divide, communal cancer and ever mounting insurgencies in the highly sensitive border areas of the country.

Secondly, what is now crucial is the questions of redefining our old strategic doctrines. Our traditional strategic doctrines and approaches, mainly based on defensive postures, will have to be re-examined in view of the precise, sophisticated and "overkilling" nature of modern weapons and weapon systems.

Thirdly, it is categorically necessary to relate the country's self-reliance in defence to interdependent global order. Self-reliance is as much a misconceived notion as that of absolute security. For no country however big and powerful it may be, can claim to be absolutely self-reliant in defence related maters. It has to depend on other countries' resources, expertise, technological know-how and defence experiences.

Fourthly, the political aspect of national security is also significat in the post-Cold War world. India's past strategic perceptions of sensitive regions such as the Middle East, the Indian Ocean will have to undergo a fundamental change after the collapse of the Soviet Union. Its political perceptions and "strategic vision" have to be reviewed so that it can play a purposeful role in there regions in the diffusion of tensions.

Fifthly, there is also a greater need for diversifying India's defence cooperation with the ASEAN countries such as Indonesia, Malaysia and Singapore which are willing to forge new defence links with India in an altered strategic scenario in the region.

Briefly, the re-thinking of national security should address the issues of cultural reconciliation, internal stability, peaceful borders, balanced partnership between public and private sectors in defence production.

References

1. The Times of India, July 22,1996,p.9.
2. Ibid., JANUARY 26,1996.
3. Philip G. Cerny, "Globalization and the Changing Logic of Collective Action", International Organisation, No. 49, No. 4, Autumn 1995, p. 595.
4. Will Durant, The story of Philosophy, New York : Washington Square Press, second edition, 1967, p.304.
5. See Lawrence E. Grinter, "The United States and South Asia : New Challenges and Opportunities", Asian Affairs : An American Review, Washington, Vol. 20, No. 2, Summer 1993, pp. 101-119.
6. For details, see B.M. Jain, South Asian Security : Problems and Prospects, New Delhi : Radiant, 1985.
7. The Times of India, 9 December 1996

TERRORISM : CHALLEGE OF PEACE AND SECURITY

-Dr. S. K. Mishra
Associate Professor
Government College,
Hissar, Haryana

Terrorism in the classical sense of the world means act of violence in pursuit of political aims perpetrated by individual organisation or governments in order to frighten and, at times, create panic among the population. Terrorism, generally speaking, is systemic use of terror or unpredictable violence against government, public, or individuals to attain a political objective. There is abundant evidence from recent history to show that terror has worked as a weapon for ruthless in achieving strategic goals. Terrorism and low intensity conflicts are not new in South Asia but the September 11, 2001 terror attacks on the United States suddenly gave the events a new dimension. From regional considerations, terrorism acquired global connotation and in this changed perspective, South Asian terrorism and low intensity conflicts needed to be explored afresh if only to ascertain the evolving extents.

Terrorism and incidents of terrorist violence have become the daily grist of the media today. Almost everyday television channels, radio and newspapers carry reports of dramatic suicide bombings, brutal killings of innocent civilian, hijacking of airplanes and buses carrying innocent passengers, abductions of people and demands for ransom for the release of hostages and of encounter between armed forces and suspected insurgents. Terrorist outfits have now become significant actors in the world politics. Terrorism has assumed international dimensions and that the war against international terrorism cannot be fought selectively were clearly manifested last month (Nov., 2006) in India and Iraq.

This research paper emphasise to win the war on terrorism, the world apart from rooting out today's generation of terrorists who are actively planning to take innocent lives, must also attempt at preventing the next, potentially larger generation from rising up. This will be possible if there is a concerted global attempt at removing poverty, illiteracy and authoritarian power structure (non-democratic regimes), since these three features provide the very rational for terrorism (at least for public consumption). The paper analyse the social, political and economic factors responsible for the rise and salience of terrorism; the challenges posed by terrorism and low intensity conflict on peace, stability of the nation-stakes and people. The international, regional and national regime against terrorism and perpetrators of mass violence; the motives, ideologies, strategies and activities of various

non-state armed groups in South Asia, and thereby contribute toward meaningful policy option in tackling terrorism and activities of armed groups.

Terrorism is a morbid feature in mankind's history. Most dangerous is terror elevated to the rank of state policy in our nuclear age. To expose the roots of terrorism and its true causes and put an end to it once and for all are among the urgent tasks of today. In the ultimate analysis terrorism cannot be defeated as long as the countries fighting against it do not have national solidarity. This lesson is particularly relevant for India. The way all our political parties perversely politicized the attack at Ayodhya, just to appeal to their communal vote bank, speaks poorly of our country.

Terrorism is an act that is committed by a group of well-trained, highly motivated people who have no compassion for human life; but can all rebels, insurgents, separatists, militants, guerrillas, fundamentals be categorised as terrorists? or does terrorism carve its own special niche? Terrorist organizations take birth due to any of the following three reasons. First, religious, fundamentals, which normally is without frontiers and is therefore be dealt with globally; Second, ethnic intolerance as has been appearing in Sri Lanka or what happened in the breakup of Yugoslavia, or for that matter, what happens in our own country; Third, deprivation of a segment of the society. The latter two, more often than not, are confined to a region and have a common cause of economics between them. These are best dealt with regionally on nationally what has to be kept in mind is that there are no 'good' terrorists, however just be their causes.[1]

Despite international efforts, the threat from terrorism remains are potent as ever. Advance in telecommunications and improvements in international commercial logistics have combined to increase the range and effects of terrorism activities, providing the physical means to transcend even the most secure borders and with the potential to cause serious damage to global political and economic systems. There is continuing concern over the immediate neighbourhood remaining a hub for international terrorism organisations. Terrorism is agitating the whole world as an acute problem. And most importantly it has assumed an organized form. It has created a deadly network at international level by exploiting the information technology revolution. India has witnessed an exponential rise in the acts of terror in recent years.

New terrorist groups are reportedly more violent and prone to use new types of weapons. This has thus resulted in fostering new more lethal and dangerous forms of terror which can be called super terrorism, envisaging mass casualties. Super terrorism loosely defined is projected future use of chemical, biological nuclear and radiological weapons or weapons of mass destructions (WMDs) by terrorist groups. As per and Israeli Terrorism expert, Ehud

Sprinzak supper terrorism is based on two propositions, taken in the context of an attack on America but one which may be relevant on the case of India as well, given our propensity to terror strikes.

Three terrorists echelons -

(i) Local group of terrorists : Local group of terrorists which act in well defined areas, with actions aimed at addressing the cog of internal power.

(ii) Global terrorist groups : Global terrorist groups which act everywhere in the world to produce major events that will remain in the collective imagination for a long time and will be stored such as historical events in collective consciousness of the world (9/11 attack on World Trade Centre).

(iii) Glocal terrorist groups : Which act in certain areas of the world with a strategic local action in order to spread global terror such as German Bakery Bomb blast at Pune and broadcast through the internet and media.

Finally, the US has succeeded in killing Osama bin Laden, the Al-Qaida leader on top of the American list of wanted terrorists. The US forces has been tracking him since Osama's men destroyed the World Trade Centre's twin towers in New York and attached the Pentagon complex in Washington DC on September 11, 2001. Nobody was, however, sure where the man who perfected the ideology of terror, misusing the fair name of Islam, was during these nearly 10 long years. There was also speculation that he might have been killed during the carpet bombing by the US-led allied forces in Tora Bora and other areas in Afghanistan after 9/11. The theory of Osama's demise during the Afghan operation was, perhaps, floated by Pakistan's ISI to suit its own interests. The world at large was, however, of the view that the Al-Qaida supremo was hiding somewhere in Pakistan most probably in the tribal areas bordering Afghanistan. It is stunning to learn that Osama has been killed in Abbottabad, which has a prestigious military academy.

President Obama was given an intelligence brief last August about Obama's presence in Abbottabad, but very few in the US administration were told about it. That information has ultimately proved to be true. Pakistan, which has been denying that the Al-Qaida leader was leading a comfortable life in Pakistani territory, will find it difficult to face the world today. It must have known about his whereabouts. The US admission that the success in eliminating Osama bin Laden has been achieved with cooperation from Pakistani agencies confirms the belief that the authorities in Islamabad knew where Osama was. Now Islamabad may have to pay for misleading the world.[1]

The killing of Osama will obviously boost the chances of President Obama getting a second term to occupy the US White House after the 2012 elections. It is a major foreign

policy achievement for the Obama Administration. But this does not mean that the war on terror has ended. The ideology of terror that Osama came up with is very much alive. There may be very few people who believe in it, but their number can grow if the dangerous ideology is not made ineffective with the help of Islamic experts whose words are taken with utmost seriousness by the followers of Islam.

US Secretary of State Hillary Clinton is right in declaring after the death of Al-Qaida chief Osama bin Laden that the war on terror is not over. The battle against the syndicate of terror has to be continued to ensure that the world remains free from terrorist attacks. But this is not so easy. In fact, the killing of Osama was easier than eliminating Al-Qaida and the ideology it represents. The remaining part of the anti-terrorism drive is more difficult because the most dangerous terrorist outfit of the world has been functioning through smaller outfits allied to it and its offshoots like Al-Qaida in Arabia with its headquarters in Yemen and Al-Qaida in Iraq. In the Afghanistan-Pakistan region, it has been functioning through the Taliban, the Lashkar-e-Toida, the Jaish-e-Mohammed and some other such organisations. These hardcore associates of Al-Qaida may become more active in taking revenge for Osama's killing as their key leaders like Ayman Al-Zawahri, Mullah Omar and Hafiz Saeed are very much active with a vast network of their own.

There are, no doubt, any number of Muslims who have nothing to do with what Osama has been preaching and what his terrorist ideology stands for. In the opinion of such people, both Islam and Muslims have suffered considerably because of the activities of Osama and, therefore, his end is a relieving development. But the reactions of some people in the Arab world, Pakistan and Jammu and Kashmir in India tell a different story. The followers of the Jamiat-ul-Ulema Islam in Pakistan holding a rally to condemn the killing of Osama at the hands of US forces and hardcore Hurriyat leader Syed Ali Shah Geelani describing the killed terrorist mastermind a "martyr" indicate that Al-Qaida can sustain itself unless a concerted drive is launched to destroy it ideologically.

There is the danger of anti-Americanism getting strengthened in areas where this sentiment has been there for a long time. US President Barack Obama has done well to highlight the point that America would never be against Islam and what Osama was a "mass murderer" and not a "Muslim leader". He will now have to concentrate on issues like the cause of Palestinian homeland and quick US withdrawal from Iraq and Afghanistan to prevent Al-Qaida and its affiliates from exploiting the situation.

Pakistan has been accused by Bangladesh, India, Iran, Afghanistan and other nations (including the US and Britain) of its involvement in terrorism in India and Afghanistan. Satellite imagery from the FBI and data produced by India's Research and Analysis Wing

suggest the existence of several terrorist camps in Pakistan. The JKLF, a militant outfit considered a terrorist group by India, has admitted to having more than 3,000 of its militants trained in Pakistan.

Many non-partisan sources believe that officials within Pakistan's military and the Inter-Services Intelligence sympathise with and aid Islamic terrorists, saying that the "ISI has provided covert but well-documented support to terrorist groups in Kashmir, including the al-Qaeda affiliate Jaish-e-Mohammed. Though Pakistan had denied involvement in terrorist activities, its president Asif Ali Zardari admitted in July 2010 that terrorist outfits had been "deliberately created and nurtured" by past governments "as a policy to achieve some short-term tactical objectives". In October 2010, former Pakistan president and its former army chief, Gen Pervez Musharraf revealed that Pakistani armed forces trained militant groups to fight Indian forces in Kashmir.

Many Kashmiri militant groups designated as terrorist organisations by the US still maintain their headquarters in Pakistan-administered Kashmir. This is cited by the Indian government as further proof that Pakistan supports terrorism. Many terrorist organisations are banned by the UN, but continue to operate under different names.

Even the normally reticent United Nations Organisation has publicity increased pressure on Pakistan on its inability to control its Afghanistan border and not restricting the activities of Taliban leaders who have been declared by the UN as terrorists. Both the federal and state governments in India continue to accuse Pakistan of helping several banned terrorist organisations like ULFA in Assam. Experts believe that the ISI has also been involved in training and supplying Chechen militants.

Though US Secretary of Homeland Security Janet Napolitano in New Delhi on 27 May 2011 preferred to avoid answering journalists' questions on Pakistan still using terrorism as an instrument of state policy, she did admit that after Al-Qaids, the Pakistan-based Lashkar-e-Toiba (LeT) was the most dangerous terrorist outfit in the world. There were many other terrorist organisations like the Pakistan Taliban, the Jaish-e-Mohammed and the Jamat-ud-Dawa which were well-entrenched in Pakistani society. Then there are jihadi outfits engaged in mainly Kashmir-related activities. They all contribute to terrorism from Pakistan. Islamabad is doing very little to do-radicalise Pakistani society obviously because this does not suit its terrorism-based policy for achieving its geopolitical objectives. The world community cannot afford to keep quiet as the situation is very disturbing for peace in South Asia and elsewhere.

Pakistan cannot mend its ways unless the US forcefully tells it to do so. A strong US message to Pakistan was expected after the killing of Al-Qaida chief Osama bin Laden in

Abbottabad, near Islamabad, but this did not happen. US Secretary of State Hillary Clinton in Islamabad on May 27, 2011 did not go beyond saying that Pakistan's problems could not be solved by nursing anti-Americanism or believing in conspiracy theories. Instead, she should have clearly stated that the US aid to Pakistan could not continue so long as it remained the hub of terrorism. The Pakistan government must launch a strong anti-terrorism and anti-extremism drive with a clear message to one and all that any kind of terrorist activity would not be tolerated. It must destroy all such outfits root and branch.

The Generals in Pakistan, the de facto rulers, will never take seriously any suggestions from Washington DC and other influential capitals unless they fear that their inaction may result in Pakistan not getting aid from international sources, which may lead to its economic collapse. But this requires a US policy change, which is unlikely to come about. The US scheme of things for the region today prevents it from employing strong language against Islamabad. The US wants to use Pakistan for safeguarding its interests in Afghanistan. Such a policy cannot help stamp out terrorism from South Asia.

In conclusion, it could be said that India remains challenged by terrorism in many dimensions. The state response so far has not been very effectual. However, post 26/11 a plan is in place which when fully operational will considerably enhance internal security. As has been brought out this will be an action oriented rather than rhetorical regional endeavour by building a cooperative security structure with commitment to comprehensive approach. India's commitment to adopt a plural and multi ethnic society based on equity and equality has to be supplemented by accountable and participative structures of governance at all levels from the grass roots to national level. Also, there is an urgent need to establish multi-disciplinary mechanisms for countering transnational terror. Such mechanism must be supported by efforts of the political, diplomatic, social, economic, information and security establishments.

References

1. Air Marshal Dhiraj Kukreja, 21st Century : Terrorism Comes of age, Defence Watch, Feb. 2009.
2 Editorial, The Tribune, May 3, 2011, Chandigarh.
www.wikipedia.org
1. Editorial, The Tribune, May 4, 2011, Chandigarh.
2. Editorial, The Tribune, May 29, 2011, Chandigarh.
3. USI Journal, January - April, 2011.
4. Defence and Security Alert, May 2011, New Delhi.

IPR IN DEFENCE DEALS

(With Special reference to the Indo-Russian IPR Agreement)

Dr. Shri Bhagwan Singh
Reader
Department of Defence
and Strategic Studies,
D.V.N. (PG) College, Gorakhpur

Dr. Harsh Kumar Sinha
Reader
Department of Defence
and Strategic Studies,
D.D.U., Gorakhpur University,
Gorakhpur

The issue of Intellectual Property Rights (IPR) in the area of defence has got new momentum with the signature of the much awaited agreement between India and Russia in December 2005. This can be assumed that in future India or any other developing country like India have to go through such agreement regime in procurement of defence technology and joint defence research etc.

The impact of this ongoing change will be pervasive and multidimensional. It will affect not only the defence on the developing countries but also on the basis of their economic system. It will be an interesting development to watch how the developing countries face the challenges of unipolar world system which is a result of economic diplomacy. This is an obvious inference that how these countries cope with tis challenge will decide the future course of their foreign policy.

Defence Deals and IPR :

Intellectual Property Rights are infact the result of TRIP agreement and are protected under various laws like patent act, copyright rules, trade marks rule etc. Intellectual property may be the idea, invention, technology, art work, music, literature etc, created by an individual or a firm. When created it is intangible but becomes valuable in tangible form when it gets shape of a product or process and similarly it achieves a commercial value when it is patented.[1] TRIPS agreement was aimed to protect and enforce IPRs in a manner that ensures the free flow of goods and services between the countries concerned. It binds all WTO member states to domestic IPR regulatios and non-compliance of TRIPS could face WTO mandated sactions too.

Geostrategic changes have played a pivatal role for the entry of IPR isse in the field of Defence deals. Before the establishment of the unipolar world system or before the disintegration of Soviet Union, the transaction of arms used to take place not because of the need of the nation but by the wishes of the Super Powers. In the cold war era, America and Soviet Uion used to sell or transfer the defence technology to their supporters in order to

mainain the balance of power, without giving a second thought of their misuse or further transfer. Durig this period, the recipient country was free to make the payment at its convenience. To maintain the balance of power through arms, regional military alliances or bilateral defence cooperation treaties were made.

But the situation changed drastically with the disintegration of Soviet Union with the dilution of Soviet Union as a Super Power, the power balance changed and the equations of American dominance were established. As a result the Super Power had no compulsions of distributing the arms in charity to the developing nations. Contrary to the previous situation the Super Power started to find new strategies to use sell of arms as a means to serve their National interests, IPR very handy for this. In IPR regime developed nations have two broad benefits.

1. In IPR regime developed nations can have the monopoly to sell their inventions according to their interests. And.
2. If they want, they can have an upper hand in defence deals. For example, they can put forth this condition that they will have the right to manufacture the spare parts forever with them. This condition will make the receiving country always dependent on them. Likewise, before transferring the technology they can say that the manpower for the maintenance of the arms will be theirs. In this situation also the recipient country will be compelled to be dependents on them forever.

The natural impact of IPR regime in defence deals will be on developing countries. To acquire the latest arms and arms technology they have to cough-up a huge sum of money alongwith the hostile conditions. For the development of modern arms, a huge sum of money is needed for Researd and Development. The budget of many US companies who are involved in Arms R & D is much more than the annual budget of many third world countries. The natural repurcusion is that they can not even think of modern weapon system and if no investment is made on research and development, the new technology is to be procured or required. Naturally, this acquired technology will involve royalty payment which essentially will increase the price of the product. One should also keep in mind that denial of advanced technology may further lead to high cast and may demand more funds.

As far as the developing countries are concerned weapon development programmes will have the following problems as an impact of IPR.

1. They will have to pay heavy price to maintain their National Security.
2. If a country having monopoly on any specific weapon system wishes to deprive us from obtaiing the essential weapons, it can do so.
3. There can be major problem in technology transfer.
4. If a country wishes to develop its own weapon system instead of buying it from

any developing country, it has to increase its R & D budget maniold which will have a natural fallout on its human welfare programmes.

Apparently it appears that the entry of IPR regine in defence deals will have an adverse effect on the ecoomy of the developed nations. But it is not that all is black in IPR regine for developing countries. Infact if it is a challenge to such nations, it is also an opportunity for them. They must ow understand that technology-dependency is as dangerous as the lack of it. At any decisive moment the nations having monopoly on technology can stop its supply which can pose a dangerous situation for the country. In this grim situation, it is judicious to become self-reliant and maintain a balance among the suppliers of the needed weaponary.

Indo-Russia Agreement on IPR :

Cooperation in the field of defence constitutes the most important feature of Indo-Russian bilateral ties today. A majority of the Indian military hardware is of Soviet/Russian origin.[2] Despite the fact that Indian Policy makes are engaged in diversifying the source of military equipment and technology acquisitions, because of the long established ties and ongoing projects, Russia is likely to remain for the foreseeable future the major defence partner of India.

Time Trusted Partner :

Up to 1996-97 the major part of the arms transfers from Russia or their production under license in India considered of the order given to the former Soviet Union. The fact that Russia has buckled under US pressure in 1993 on the Cryogenic deal also created doubts about the reliability of Russia as a defence supplier, although both India and Russia did see to it that the incident did not mar their friendly ties.[3] Although Moscow went alongwith the other P-5 countries in condemning India's nuclear tests in the UN Security Council, in contrast to the US and other countries policy. Moscow did not impose sanctions on India. During the Russian PM Yevgeny Primakov's New Delhi visit in December 1998, the two countries extended the long term agreement on military technical cooperation up to the year 2010. The agreement envisaged shifting the emphasis from buyer-seller relationship to the joint development of new technologies.[4]

At the time of President Vladimir Putin's visit to India in October 2000, major weapons deals worth 3 billion dollar - under negotiations for a long time - were clinched. The India-Russia Intergovernmental Commission on Military technical cooperation was uptraded from the level of defence secretaries to the Defence Minister on the India side and the Deputy Prime Minister in charge of defence export on the Russia Side.[5]

In the last five years India has acquired or contracted several major weapon systems.

Some of them are Su-30 MKI multi-role fighter aircraft, 11-78 taker aircraft to be used as platform for Airborne Warning and Control System (AWACS), Mi-17-IV military transport helicopters, R-77 air-to-air missiles, Kilo class submarines, Ka-31 Helix airbone early warning helicopters, aircraft carrier Admiral Gorshkov, Ka-27 PL and Ka-31 helicopters, T-90 tanks, fire-control radar, air and sea-surveillance radar, combat radar, anti tank and anti-ship missiles.[6] The value of projects under the current long-term defence cooperation programme upto 2010 is generally agreed to be around 9-10 billion dollar.[7]

The IPR Issue : Reasons Responsible :

For the past couple of years, Russia had been insisting that India sign the IPR agreement regarding defence-cooperation. Apprehensive of India diversifying defence equipment sources, Russia was keen to safeguard its financial and Intellectual Property Rights. This apprehension was the outcome of several reasons, Some of those were :

1. Though the Russian System are cheaper but they are tagged with the old machinary. Machinery and equipment in the Russian defence industries are becoming old and out-dated. It has been pointed out that during 1999 and 2000, less than 5 percent of the machinery was less than five years old, while over 75 percent were more than 10 years old. About one-third of the machinery was more than 20 years old.[8] There is in general a shortage of funds for R & D. Moreover, the Russian defence idustrial sector is known for its general lack of transparency.
2. Delay in the supply of equipment has been a constant problem. For example, the deadlines set for the supply of SU-30 MKI were not met. There were also delays in the upgradation of MIG-21 to the MIG-21-93 level. It has been reported that the Su-30 MKI aircraft that India has been receiving did not have all the features.
3. Besides, at times there have ben complaints of sub standard systems and spare parts. It was reported that in case of Tangushka Air defence system, old and rusted system were provided. However when the Indian Army draw the attention to this, they were replaced.[10]
4. It was felt by Indian side that soon after the collapse of the Soviet Union, Russia adopted free market philosophy and they started demanding unreasonably high prices for their hardware.[11] No wonder, Russia was not prepared to supply to India on prices and terms offered by the former Soviet Union. In April 2001, an Indian parliamentary report noted that Russia no longer grants India 'Friendship Prices.'[12] The report recommended that India should opt for global bids for all its defence procurements.

All this is cautioning Indian policy makers not to risk putting all egges in one basket and diversily the source of defence supplies. Naturally these underwater developments were making Russia worried about the future business scenario, Infact most of the weapon systems that permitted Russia to emerge as one of the two biggest arms exporters were essentially developed by the Soviet Union in 1970s and 1980s. These weapons successfully competed with their foreign equivalents. Russian experts apprehend that India and China have purchased most of what Russia can offer. But if the two look other sources for more advanced weapon systems and technology, the arms exports to India and China may decline after 2007-2008.[13] All these drove Russian policy makes to seriously think over the arrangements and provisions which can safeguard their business interests in future. It was felt that IPR have enough potential in resolving this problem.

Pressure Mounting :

Eventually, within no time the IPR issue became a sore point between both the countries. In Oct, 2005, mentioned that absence of an agreement with India on protection of military intellectual property right has become a "tangible barrier' in joint development of sophisticated weapons and cutting edge defence technology. On the eve of his four day visit to India Russia Defence Minister Sergei Ivanov told to PTI. that Indo-Russian defence cooperations began in 1960 and has been steadily growing for almost fifty years now. India's share in Russia's arms exports amounts to minimum 40 percent. We have left behind primitive schemes like buyer-seller relationship and have successfully developed BrahMos cruise missiles. Faithful negotiations are underway in naval shipbuilding, but further advance is stalled due to lack of IPR agreement. He further warned that :

"We will find it difficult to move forward in high end defence technologie without an agreement on the protection of intellectual property. We will not hand over technology for nothing. Russia is not Soviet Union."[14]

Russia also put pressure on New Delhi and India was warned that the doors of Russian defence factories would be shut to Indian military and technicias in the absence of an IPR agreement.[15] In November 2005, Russia refused to transfer technology as part of its planned sale of Igla surface to air missle system. Earlier in late September 2005, Russia said it would not give the technology along with the Smarch Multibarel Rocket Launcher system and reduced the order from 69 pieces to 46.[16]

Indian Response :

Indian reaction was very cautions and cool. It was very much clear before the policy makes and amidst numerous complaints about the delays in the supply of weapons and spare parts and at times their poor quality, the Soviet/Russia weapons have proved to be battle

worthy and reliable. In fact, during Indo-US joint air exercise in Gwalior in February 2004, the Indian pilots flying MIG-21, MIG-27, MIG - 29, Su-30 out performed the US pilots by their training and skills.[17] The bane of the Indian defence establishment is the failure to develop indigenous weapon systems of the requisite quality within the planned time. Russian equipment was purchased in bulk as a stopgap arrangement in the hope that it will be replaced by indigenous MBTs and LCAs. This did not materials and a dependency has been created on imported harware.[18]

Besides, India was not in a position to withdraw itself from several deals and ongoing projects like BrahMos. The development of Medium Transport Aircraft Development Programme (MTA) has been assigned greater urgency in India. India was very keen to get the benefits of Soviet era Global Navigational Satellite system (GLONASS), the Admiral Groskov (INS Vikramaditya, now) deal worth 1.5 billion dollar was all set to change in reality in 2008. The Nuclear propelled submarine deal was also in the pipeline and India could not forego all these major arsenals. So it was almost sure that India will have to go in the IPR agreement.

Serving National Interests :

After the successful testing of the BrahMos supersonic cruise missiles, which was a shining example of joint research, development and production of India and Russia, both the countries have decided to jointly market BrahMos to the third countries by 2007, by which time India and Russia are expected to finalise sale produres and put into space at least 18 satellites under GLONASS to track the missile's moveent.[19] So there was no case of withdrawing itself from this decisive phase.

But there were some sticky issues which India wanted to deal carefully. Russia initially wanted this agreement with retrospective effect but India rejected it diplomatically. Later it has been agreed that the accord will apply only to the new deals. However it will define principles for procuring spares for and upgrading the Soviet-made hardware still in service of the Indian armed forces. This was another a sticky issue. Russia, which has been objecting to India buying spares and modernization technologies from third countries wanted in the accord to ban India from turning to other suppliers. India agreed to give preferences to Russian suppliers but on condition that they make deliveries within reasonable time and price. In this manner India successfully maintained its national interest.

Russia conceded the Indian demand that the IPR provisions apply to future trasactions only. The accord is intended to ensure that no technoloy is transferred to third countries and royalty is paid to Russia for work performed on Russian built weapons by other countries. Report suggests that the terms of IPR agreement also mention Russia as India's preferred supplier. Some defence experts have cautioned against such a provision. However,

India, reportedly agreed to the clause as it is still "To dependent on Russian arms suppliers."[20] So the agreement was finally translated into reality. After signing the agreement Indian Foreign Secretary Shyam Saran said that "this will, in a sense, open the door for much wider cooperation as partners in the defence field." This agreement also paves the way for a host to upgrade programmes that Russia had previously refused to entertain.

Epilogue :

IPR regime should be accepted as a reality in this economy-centric world politics. This, naturally, gives an upper hand to technology saler on the technology buyer. This regime has posted a new challenge for the developing nations to countinue their defence programmes. As has been said previously in this paper, that this is not only a challenge but also an opportunity for developing nations. The diplomatic manovering of India in the IPR agreement with Russia by maintaining its national interest and paving a favurable environment in its future defence preparedness programmes is a path to follow for developing countries.

References

1. H.S. Bajpai, 'Intellectual Property Rights and a firm : A managerial concern'. Talk delivered in Academic staff college, B.H.U. January 2006.
2. Jyotsana Bakshi, 'India-Russia Defence Cooperation', Strategic Analysis, Vol. 30, No. 2 Apr.-Jun 2006, P. 449.
3. Jyotsana Bakshi, 'Russia and India : From Ideology to Geopolities', Dev Publication Delhi, 1999, P. 225-29.
4. Ibid.
5. No. 2, P. 451
6. SIPRI Yearbook 2005, P. 478-81.
7. The Hindu, Nov. 16, 2005.
8. R.G. Gidadhubli, 'Russia refurbishing the military-industrial complex', Economic and Political weekly, Aug. 23, 2003, P. 3546-47.
9. No. 2, P. 455.
10. 'From Strengh to Strength : Growing military cooperation', FORCE, Jan. 2005, P. 18.
11. R. B. Suri, 'Indo-Russian Cooperation in the Naval Field and Self Reliace', Agni, May-Aug 2003, P. 22-23.
12. V. Raghuvansi, 'Report urges India to widen contracting process', Defence News, Apr. 30, 2001.
13. Vedomosti, June 16, 2005 in Strategic Digest, July 2005, P. 895-96.
14. The Hindu, Dec. 1, 2004, also in No. 1.
15. The Hidu, Dec. 3, 2004.
16. V. Raghuvanshi, 'Russia denies Missile Technology to India', Defence News, Nov., 28, 2005.
17. C. Rajghatta, 'Ageng IAF shoots down USAF top guns', Times of India, June 18, 2004.
18. No. 1, P. 457.
19. Jane's Defence Weekly, Dec. 14, 2005, P. 16.
20. Strategic Digest, July 2005, P. 894-95.

SINGAPORE - A ROLE MODEL OF GOOD GOVERNANCE

-Dr. Manju Srivastava
Associate Professor
Deptt. of Political Science
D.A.V. College, Kanpur

In his interview at a Press Conference according to the Strait Times S'pore of August 2008, a Noble Laureate Economist Michael Spence : having studied the governance of thirteen (13) South-East Asian countries i.e. Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Hong Kong etc. at macro level concluded that Singapore stands first in good governance and gave 10/10 marks to it.

Most observers, including the World Bank have rated the Republic high, giving it their stamp of approval for the direction in which the Republic and its politics are going. Even the International community is well aware of its success. Some call it a political anomaly for its impressive stature in International Politics despite being a small Island Republic. Others have labelled Singapore an economic success due to its rapid transformation into a first world economy.

ACHIEVEMENTS:

Its rapid economic growth is well known. Its International trade is more than 3 times the size of its gross national products. It also is the regions capital of multinational corporations. Its workforce is highly educated, trained and disciplined leading to the success in having one of the highest per capital incomes in the world. Despite of paucity of natural resources including drinking water, Singapore has been able to create niches in areas such as petrochemical refinery and provision of healthcare, political and social stability are its basic characteristics. Equipped with world class modern amenities and infrastructure in communication, transportation, advanced information technology, it has become a modern banking and financial hubs along with one of the world's best airports and seaports.

Other unsung achievements are also there. Singaporeans have been largely at peace with each other. Despite the world-wide rise of ethno-nationalism, Singapore is an oasis of peace and harmony. Inspite of its mosaic pluralism comprising of Chinese, Malay, Tamilians, Eurasians as basic, multi-racialism is the bedrock of Singapore Society. It is corruption free and relatively an inexpensive place to live.

Unique and Successfully Functioning:

Contemporary observers and analysts often measure small states with the achievements of Switzerland and to some extent Israel. In fact, the success of a small state depends upon its ability to come to terms with itself and its environment and make best use of it, on all fronts. In this context the Singapore Model has exhibited many ideas worth noting. It has consequently, shown the ability of the rulers and the ruled to construct a compact to develop a functional party. The trials and tribulations that the country went through in its historical past being a British colony, then in Japanese occupation and its post-war era, merger and separation from Malaysia and lastly independent Singapore in 1965 have all greatly, impacted and influenced the politics and governance of Singapore. These historical legacies leads us to understand the issues and factors that have persisted throughout the Republic's short history and continue to dominate the political discourse, direction and the very fundamentals of politics and governance in Singapore. All this provided the base that account for the resilience of its leaders and people. They had one simple choice either act in unison or disappear. That compact remains relevant even today and this is one of the most important factors accounting for the uniqueness of Republic, its leaders, people and its politics.

The Ruling elites, from the very beginning have also been obsessed with good governance. The statements and the think tank of the PAP (People's Action Party) the ruling party of Singapore have been more concerned with doing 'What is right' rather than what is 'popular' Lee Kuan Yew the father of Modern Singapore and longest serving Parliamentarian as well as former P.M. Singapore argued-

"Political leaders must never be trapped into believing that popular government means the government must always be popular in its policies. If they want to win respect and popular endorsement before the end of the five-year term, they must be prepared, whenever necessary to take decisions, however unpopular they may temporarily be. Gradually, they will establish their credentials with the majority of singaporeans by providing leadership under crisis."[1-]

It was mainly due to beliefs of this nature that in 1979, at the 25th anniversary of the PAP Lee Kuan Yew listed six principles to be regarded as 'Good Governnance'.

1. Give clear signals, don't confuse people.
2. Be consistent : don't chop and change.
3. Stay clean : dismiss the venal.
4. Win respect, not popularity; reject soft option.
5. Spread benefits: don't deprive the people, and
6. Strive to succeed : never give up.

He has written about the transformation of Singapore from a third to the First World nation of these beliefs. In many ways, these achievements were made in the Republic within a generation, a rare feat in modern politics. Its multi-dimensional achievements on all fronts is a successful story of rapid modernisation and transformation through which, almost unexpectedly a modern beacon called Singapore emerged as an icon of what happens when a people and its leaders get their politics and governance move in the right direction. That is a vignette of modern Singapore, something that even Sir Stamford Raffles would not have anticipated when he began the process of transforming a tiny fishing village into a regional emporium.

Here, it is worth Sharing **Peh Shing Heui and Ken K'wek**[2] views. They argued that the PAP had created a political system and culture that was increasingly different and separate from its western parliamentary roots, though, initially was based on the west Minister Model of liberal democracy, a legacy adopted from the British rulers.

This is evident from the traits mentioned below:

1. PAP is all encompassing party, believing in ruling the country from strength and dominance culturally, it has a view on how citizens should live, speak and even how many children they should have.
2. Singapore has developed its unique brand of pseudo opposition. These refers to the Non-Partisan Member of Parliament (NMP)[3(a)] and Chairperson of Government Parliamentary Committees who provides 'alternative' & 'opposing' views in Parliament.
3. The existence of out of bounds markers (OBM) which regulated what is permissible for discussion and yet which are largely invisible and shifting.
4. The very 'serious' nature of politics, with the PAP (ruling party) considering politics as a highly serious matter.
5. The existence of a Political Culture where the electorate enjoys complaining but continues to vote for the ruling party.
6. The emergence of Singapore, politically speaking, as one big 'GRC'.[3(b)]
7. The common practice of 'electoral walkovers' during elections as the opposition is unable to field sufficient candidates to challenge PAP.

Though the Westminister Parliamentary system is certainly a part of its colonial legacy, inherited, rather than a conscious choice, it was not feasible to directly adopt and implement it in a newly created sovereign state that is different in its environment, political culture, needing greater participation and involvement in national politics. Hence, certain

adaptations and innovations to cater to its needs, constraints and limitations became the defining feature.

The Singaporean system of governance though retaining elements of Westminister Parliamentary system has evolved to suit its political culture and people's concern and is therefore known for its uniqueness, having decorative adaptations to the original system.

In Singapore the ceremonial head of the state is the President and P.M. is the head of the Government. It has a bi-cameral House and since, Independence in 1965, it has held regular elections to elect members of Parliament. Through, modelled after that of the British, several innovations have been introduced in the system of Government.

Schemes of NCMP[3(c)] (Non-constituency member of Parliement NMP (Nominated member of Parliament) and GRC's (Group Representation Constituencies) and the EP (Elected Presidency) as political innovations have impacted on the nature and essence of Singapore's Westminister Parliamentary system.

It is often described as authoritarian state or even an illiberal democracy due to its single party dominance since last fifty years. The PAP since late 1960's has steadily increased its hold over Parliament controlling nearly all seats in Parliament till this day. Its party-system is clearly as one party dominant system-PAP only capable of winning elections to form the Government. In Singapore's one party dominant system there is little or no possibility of a party than PAP to be in power. Opposition political parties, though, present in Parliament have little impact on the decision making process and their influence in shaping the policy agendas is manifestly miniscule. In Singapore there are 20 functioning political parties approximately and can be characterised as mass-based political parties e.g. worker's part (WP) & Singapore People's Party (SPP) etc. and the electorate has the choice of selecting.

However, PAP has had the initial success to identify with the electorate and eventually consolidated total power and used its privileges to perpetuate its hegemony pushing opposition on margins.

Due to the nature of PAP hegemony in Parliament and the constitutional constraints of the opposition voting rights, the power of decision making rests in the hands of the PAP. From the NMP's to the GRC's, these political innovations of providing very limited voting rights have further marginalised the opposition. These schemes pacify the desire of the electorate to have more non PAP members in Parliament. these innovations satisfy the electorates demand to have PAP in power with the presence of alternative voices in decision making process. Ultimately the PAP controls the entire decision making process though the opposition is present to air its views. It is observed that the typical Singaporean is highly sophisticated in the political sense, however, they are not merely spectators, apathetic or

politically withdrawn. They through education, mass media and personal experiences have come to realise the importance of politics and political decisions as these directly impact their lives and tuned them to believe that the correct politics will determine their future.

Singapore having achieved its present state of exceptionalism and all round development regarding economic outlook politics and governance, social, cultural relations, foreign and defence policies can definitely offer an acceptable model for many new Asian States, which have continued to struggle to find their identity to learn and adapt accordingly. Singapore's limited democracy may not offer an acceptable model for the wealthy industrialised countries of the west, but it certainly remains worthy of attention by many new Asian country, struggling to find their own place in the sun.

"The limited democracy of Singapore, reconciling democracy with national development has delivered an exceptional social and economic revolution. From a poor backward and ethnically divided tiny island of the third world, it has been transformed into a prosperous self confident and dynamic nation that today belongs to the first world."[4]

"So far, it has been singularly successful in procuring the national development.... It's remarkable that the PAP rulers, enjoying almost total power given to them by the political system, have administered it without succumbing to any abuse of power, arbitrary rule, corruption, mismanagement or disregard for the interests of Singaporeans. They have ruled the island state with exceptional integrity, respect and dedication for the rule of Law."[5]

References

1. Lee, Kuan Yew- 'What of the Post is Relevant to the Future?' People's Action Party, 1954-1979 (Singapore : Central Executive Committee, PAP, 1979), pg. 42.
2. Pen Shing Heui and Ken Kwek- "The Seven Highly unusual traits of Singapore Politics'- The Straight Times, dt. 23.12.2006.
3. (a) NMP-Non Partisan Members of Parliament - The outstanding Members of Public nominated as NMP with limited voting powers- contributing their individual talents and expertise in governance.

   (b) GRC- Group Representation Constituencies introduced in 1988 to enhance administration based on economy, consisting of 6 member groups in which one member at least should be a minority candidate. The electorates have no choice for a single candidate, but accept all the members of a group or reject the team entirely.

   (c) NCMP-Non-constituency Member of Parliament upto 3 of the best losers could be inducted to Parliament with limited voting powers.
4. Raj Vasil - Governing Singapore.
5. Raj Vasil - Governing Singapore.

INDIA AGAINST CORRUPTION

-Dr. Pushpa Mishra
Associate Professor and Head,
Deptt. of Political Science
D.A.V College, Kapur

A corruption free India can be dream come true if we, the Indians, want it to be. Why is it that no one goes to jail in our country despite indulging in corruption? Suresh Kalmadi, A. Raja, Neera Radia, Lalu Prasad Yadav, Sharad Pawar… the list is very long. The list comprises of the people who know how to rob Indians of their money and rights. On top of that, they can easily get away with it despite being exposed because of the age-old rotten anti corruption laws in our country. Enough…..We have had enough!

India against Corruption is a citizen's movement to demand strong anti-corruption laws. Jan Lokpal Bill has been introduced in the Parliament as many as eight times in the most diluted forms but could never get vote of confidence despite much efforts. After a fast by veteran social activist Anna Hazare and widespread protests by citizens across India the Government of India constituted a 10-member Joint Committee of ministers and civil society activists to draft an effective Jan Lokpal Bill.

Lets have a look at the existing system:

i. **No politician or senior officer ever goes to jail despite huge evidence**
   Anti Corruption Branch (ACB) and CBI directly come under the government. Before starting investigation or initiating prosecution in any case, they have to take permission from the same bosses, against whom the case has to be investigated.

ii. **No action is taken against corrupt judges**
   Permission is required from the Chief Justice of India to even register an FIR against corrupt judges.

iii. **No corrupt officer is dismissed from the job**
   Central Vigilance Commission, which is supposed to dismiss corrupt officers, is only an advisory body. Whenever it advises government to dismiss any senior corrupt officer, its advice is never implemented.

iv. Citizens face harassment in government offices. Sometimes they are forced to pay bribes. One can only complaint to senior officers. No action is taken on complaints because senior officers also get their cut.

v. **Nothing in law to recover ill gotten wealth**

A corrupt person can come out of jail and enjoy that money

vi. **Small punishment for corruption**

Punishment for corruption is minimum 6 months and maximum 7 years.

Jan Lokpal Bill is the ultimate solution for a corruption free India. Lokpal at centre and Lokayukta at state level will be independent bodies. ACB and CBI will be merged into these bodies. They will have power to initiate investigations and prosecution against any officer or politician without needing anyone's permission. Investigation should be completed within 1 year and trial to get over in next 1 year. Within two years, the corrupt should go to jail.

Lokpal and Lokayukta will have complete powers to order dismissal of a corrupt officer. CVC and all departmental vigilance will be merged into Lokpal and state vigilance will be merged into Lokayukta. Lokpal & Lokayukta shall have powers to investigate and prosecute any judge without needing anyone's permission. Lokpal & Lokayukta will have to enquire into and hear every complaint. All investigations in Lokpal & Lokayukta shall be transparent. After completion of investigation, all case records shall be open to public. Complaint against any staff of Lokpal & Lokayukta shall be enquired and punishment announced within two months.

Time has come for us to hit them and hit them really hard. Every building needs a strong foundation to stand. Let's build this foundation of a new, corruption free India. This is the way we want our country to be. Nobody else but we have to clear this clutter called corruption from our nation.

Although the latest drafty of Jan Lokpal Bill, presented by the UPA government is making mockery of the entire concept of it. The draft weakens the anti-corruption laws of the country further instead of strengthening them. A man like Anna Hazare has come forward to raise a voice for the rights of the Indians and it is our responsibility to support the man in whatever way we can.

References

1. Indian Express
2. India Today
3. The Hindu
4. Outlook

CONTENT'S OF CIGARETTE AND TOBACCO [IN THE AIR]

Dr. Anuradha Tiwari
Assistant Professor
Department of Chemistry
V.S.S.D. College, Kanpur

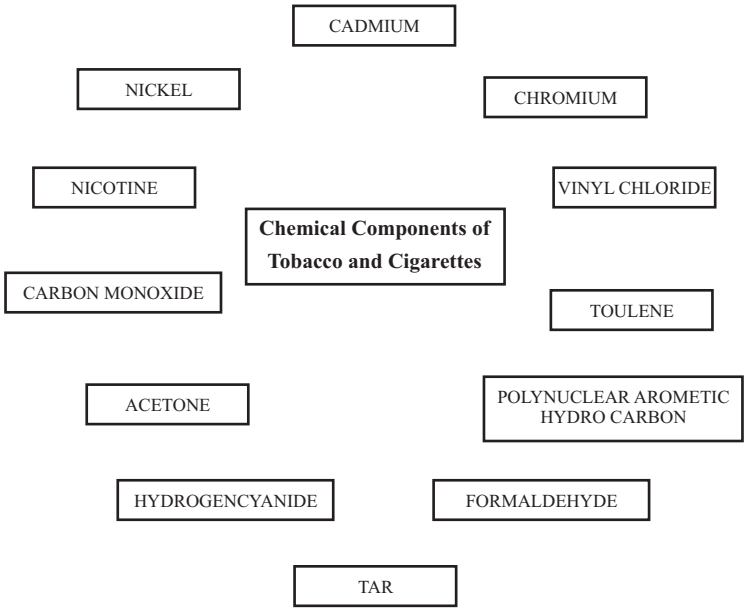

Smoking habit is the result of globalization, which is now become a status symbol. Tobacco and Cigarette is the combination of organic and inorganic components. These components are harmful proved by the IARC [International Agency for Research and Cancer]. This article is the summery of some of these components.

Presence of Cadmium (Cd) :

Tobacco leaves naturally accumulated and concentrate relatively high level of Cadmium. Smoking of tobacco is an important source of air Cadmium exposure for smokers. It has been reported that one cigarette contain about 0.5 Kg of Cadmium and about 10% of cadmium is inhaled, when cigarette is smoked. Smoker's generally higher cadmium body burdens than non-smokers. Smoking affect indoor ambient air concentration of Cadmium. Cadmium is released into the Environment when cool and tobacco is burned. These particles in air can cause toxicity in inhalation when cadmium is absorbed into the body more than 10 milligram over a long time can be fatal. Cadmium cause damage to cardiac tissue, bones, kidney through to be carcinogenic symptoms of cadmium exposure are increased loss of small proteins in urine, chowking salination, vomiting, metallic taste, loss of sense of small, joint pains etc.

Presence of Chromium (Cr) :

Cigarettes contain traces of chromium values of 1.4 Kg per Cigarettes. Some of this will be inhaled and absorbed. Small fraction of the chromium is inhaled and only one half will be deposited in the lung. Smoking 20 cigarette per day would exceed a few microgram per day. The carcinogenicity of Chromium especially with regard to lung tumors has been investigated in a number of inhalation studies. Chromium is absorbed through a respiratory tracts. Trivalent chromium is essential for human being but Hexavalent chromium which excrets by tobacco and cigarette are highly toxic. It is conclude that there is sufficient evidence of respiratory carcinogenicity in human exposed to hexavalent chromium. IARC has classified to human that [Cr(III)] is not carcinogenis while [Cr(VI)] is carcinogenis.

Presence of Nickil (Ni) :

Inhalation of air borne nickel may result in a total pulmonary exposure of 0.5 Kg/day. The Pulmonary exposure of person smoking 20 cigarette may be 4 mg/day. IARC has recently re-evaluated that epidemiological data on respiratory exposure are found sufficient human data are available to conclude that nickel (nickil sulphate) is carcinogenic to human. It is also a common skin allergen. The prevalence of nickel sensitivity is about 8-14% in human being.

Presence of Nicotine :

Nicotine is a powerful and poisonous for the nervous system. There is enough (50 mg) in four cigarettes to kill a man in just a few minutes, if it were injected directly into the blood stream. When diluted in smoke nicotine reaches into the brain just seven second. It stimulates the brain cell and the blocks the nervous impulse. This is where addiction to tobacco arises. Nicotine also causes accelerated heart rate but the same time it leads to contracting and hardening of the arteries. The heart pumps more but receives less blood. The result is twice as many coronary attacks.

Presence of Carbon monooxide (Co) :

This is the asphyxiating gas produced by cars which makes up 1.5% of exhaust fumes. But smokers inhaling cigarette smoke breathe in 3.2% carbon monoxide and directly from the source. Oxygen is mostly transported in blood by hemoglobin when we smoke, however the carbon monoxide attaches itself to the hemoglobin 203 time more quickly than oxygen does, thereby displacing the oxygen, this in turn asphyxiate the organism. This causes the following cardiovascular complaints, narrowing of the arteries, blood, clots, arteries, gangrene, heart attack etc. but also a loss of reflexes and visual and mental problems. It takes between six and 24 hour for the carbon monoxide to leans the blood system.

Presence of Tars :

The tars in the cigarette smoke are deposited and collect on the wall of respiratory tract and the lungs and cause them to turn black. So, just because a smoker is not coughing, it doesn't mean that he or she is healthy ! And the fact merely serves to pour water on one of the most common and poorest excuses given by smokers. The carcinogenic action of the tars is well known, tars is responsible for 95% of lung cancer. By smoking one packet of cigarettes every day, a smoker is pouring a cupful of these tars into his or her lungs everyday (225 grams on average).

Presence of Vinyl Chloride :

Vinyl Chloride is found in the smoke of cigarettes (1.5-1.6 mg per cigarette) and small cigars (14-27 mg). Vinyl Chloride is a narcotic agent and loss of consciousness can occur at 25 gm/m^3. There is sufficient evidence of carcinogencity of Vinyl Chloride in human according to IARC.

Presence of Toulene :

Presence of Cigarette smoke the indoor and out door concentration of toulene range is 17 to 1000 mg/m^3. All the available data relate to exposure to toulene by inhalation. The predominant effect were impartment of central nervous system and irritation of mucous membrane. Toulene is not classified as to carcinogencity in human by IARC.

Presence of Xylene :

Presence of Cigarette smoke of xylene, indoor tower air concentration is (5.2 to 29 mg/m^3) and higher is 200 Kg/m^3. in acute inhalation studies irritation of eye and throat was observed at concentration of 480 mg/m^3 and above. Xylene is not carcinogenic by IARC.

Presence of Polynuclear aromatic hydrocarbon :

Concentration in indoor air consider depending on indoor sources such as wood stoves and tobacco smoke. The environmental protection agency in U.S.A. has determine that the hydrocarbon are harmful but not carcinogenic in human.

Presence of formaldehyde :

Smokers are exposed to high level of formaldehyde. There are some evidence the formaldehyde is carcinogenic in human exposed by inhalation b IARC.

If you are not aware of the components in a Cigarette than read this article. Any sensible person who is conscious about his/her health as well as health of others will stop smoking cigarette and Tobacco because better safe than sorry.

Reference :

1. International Programme of Chemical safety by world Health organization provide book for Health Criteria and other supporting information Volu. 2.
2. Chemical Components of Cigarette Smoke : Article No. 393 created 2007-07-09.

क्या हिन्दी का विकास रुकेगा?

डॉ. बद्री नारायण तिवारी
अध्यक्ष
मानस संगम
महाराज प्रयाग नारायण मन्दिर
(शिवाला) कानपुर–208001

''अपने समाज और देश को पहचानने के लिए उस समाज या देश के साहित्य के साथ परिचित होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस साहित्य में ही प्रकट हुआ करती है।''

यह उस लेख का प्रथम वाक्य है जो भगत सिंह ने अपने अध्ययन काल नेशनल कालेज लाहौर में लिखा था। शहीद भगत सिंह ने सन् 1923–24 के मासिक ''सशर्त'' में 'पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या' शीर्षक लेख लिखा था। वस्तुतः उस समय ये प्रश्न समाज में इतने चर्चित नहीं थे। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कालेज लाहौर उन छात्रों के लिए खोला था जो स्वाधीनता की लड़ाई हेतु सरकारी शिक्षा–संस्थायें छोड़ चुके थे। प्रायः अधिकांश लोग ऐसे देश भक्तों के सम्बन्ध में यही जानते थे कि इनको भाषा या साहित्य से क्या लेना देना।

देश के स्वाधीनता संघर्ष काल में भगत सिंह सरीखे महान क्रान्तिकारी ने अपने आलेख के प्रारम्भिक वाक्यों के द्वारा दो बातों पर विशेष जोर दिया है। एक, साहित्यकार पर यह दायित्व है कि ऐसा साहित्य लिखे जो समाज के प्राणों की चेतना के निर्माण में सहायक हो। दूसरा, देश भक्त हो या राजनीतिज्ञ या वैज्ञानिक। भगत सिंह ने इस लेख में लिखा है– ''यह तो निश्चित तथ्य है कि साहित्य के अभाव में कोई देश और जाति उन्नति नही कर सकती। परन्तु साहित्य के लिए सर्वप्रथम भाषा की आवश्यकता होती है जो पंजाब में नहीं है। इसका मुख्य कारण है हमारे प्रदेश में दुर्भाग्यवश भाषा को धार्मिक समस्या बना डालना।'' यही भावना उर्दू के विषय में भी कही है– ''वे सम्पूर्ण भारतीयता के महत्व को न समझकर अरबी लिपि एवं फारसी भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। सारे भारत की एक भाषा और वह भी हिन्दी का महत्व उनकी समझ के बाहर है।'' उन्होने भारतीयता संदर्भ में बंगला के राष्ट्रीय कवि काजी नजरूल–इस्लाम का उदाहरण दिया। उनकी चर्चित रचनाओं में विश्वमित्र, दुर्वासा, धूरजटी की चर्चा अनेकों बार आई है पर हमारे हिन्दी, पंजाबी, उर्दू कवि इस ओर ध्यान नहीं देते। इसका प्रमुख कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से अपरिचय है। विगत वर्ष अमर शहीद भगत सिंह का शताब्दी वर्ष मनाया गया किन्तु उनकी समस्त देश में भाषा, देवनागरी लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र के नीतिगत भावों की चर्चा शून्य के बराबर हुई।

उन्होने स्पष्ट रूप से भारतवासियों के परस्पर भावों विचारों की जानकारी विदेशी भाषा अंग्रेजी में न होकर भारत की भाषा हिन्दी में जोर दिया। भगत सिंह के भाषा सम्बन्धी विचारों में वह राष्ट्रस्तर पर हिन्दी की बात करते थे वहीं वे प्रदेश स्तर पर मातृभाषा के भी समर्थक थे। देश की आजादी की लड़ाई में सर्वाधिक हिन्दी के प्रेरक गीतों तथा पुस्तकें प्रतिबन्धित हुईं।

आज अंग्रेजी वालों के दुष्प्रचार के बावजूद इस समय अपने देशों में चीनी 80 करोड़ हिन्दी 65 करोड़, अंग्रेजी 40 करोड, स्पेनिश 40 करोड़ अरबी 20 करोड़, रशियन 17 करोड़ फ्रेंच 9 करोड़ लोग बोलते हैं। सम्पूर्ण विश्व में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 90 करोड़ है जब कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या विश्व में लगभग 100 करोड़ है, जिसमें उर्दू बोलने वालों एवं जिन देशों में हिन्दी बोली समझी जाती है, की संख्या शामिल नहीं है। क्या इस स्थिति में भारत की राजभाषा के साथ इस अन्याय की चर्चा होती है?

विदेश में अंग्रेजी के गढ़ अमेरिका में सर्वप्रथम वांशिगटन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति के 14वें अधिवेशन के एक चर्चा सत्र में कहा गया कि समिति के रोचेस्टर अधिवेशन (सन् 1992) तत्कालीन सांसद व 'दैनिक जागरण' के संपादक श्री नरेन्द्र मोहन ने प्रवासी भारतीयों को हिन्दी में समाचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। आज ई–जागरण घर–घर में पढ़ा जा रहा है। विगत वर्ष सन् 2007 में आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयार्क में सम्पन्न हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश ने 'हिन्दी' को 21वीं सदी की भाषा ही नहीं कहा उसके भविष्य को देखते हुए 11 करोड़ 40 लाख डालर हिन्दी के विकास और अमेरिका की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक घोषणा से अंग्रेजी भक्तों को चौंका दिया। इधर कनाडा के टोरंटों शहर के भारतवंशियों ने टोरंटो विश्वविद्यालय में दम तोड़ रही हिन्दी के अध्ययन हेतु 32000 डालर की आर्थिक सहायता देकर उसे पुनर्जीवित कर एक हिन्दी प्रेम का विदेश में आदर्श प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कनाडा के मंदिरों में बच्चों को हिन्दी भाषा को रचनात्मक नवजीवन दिया जा रहा है।

अंग्रेजी के चमकते संसार एवं तकनीकीकरण के बावजूद हिन्दी के समाचार पत्रों के आंकड़े ही इसके प्रमाण हैं। अंग्रेजी अखबारों में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला 'टाइम्स ऑफ इंडिया' है लेकिन, हिन्दी समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के कारण यह पाँचवे स्थान पर पहुँच गया। सर्वेक्षण के अनुसार 'दैनिक जागरण' सर्वाधिक पाठक संख्या वाला समाचार पत्र है, इसे 5 करोड़ 36 लाख लोग पढ़ते हैं। 'दैनिक भास्कर' के पाठकों की संख्या 3 करोड़ 6 लाख 'अमर उजाला' की पाठक संख्या 2 करोड़ 82 लाख और दैनिक 'हिन्दुस्तान' के पाठकों की संख्या 2 करोड़ 35 लाख है।

अंग्रेजी पत्र–पत्रिकाओं में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के बाद 'इंडिया–टुडे' का स्थान है जिसे 71 लाख लोग पढ़ते हैं। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पाठकों की संख्या 61 लाख है जब कि 'दि हिन्दू' की 49 लाख है। दैनिक 'जागरण' और दैनिक 'भास्कर' जैसे हिन्दी दिग्गजों के

बीच 'इडिया टुडे' का हिन्दी संस्करण आज भी शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाये हुए है। इसके पाठकों की संख्या 70 लाख है, लगभग अपने अंग्रेजी संस्करण के ही बराबर। दैनिक 'राजस्थान पत्रिका' की संख्या 1 करोड़ 2 लाख है, जब कि 'पंजाब केसरी' को 1 करोड़ 9 लाख लोग पढ़ते हैं। 'सरस सलिल' के पाठकों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख और 'गृह शोभा' की पाठक संख्या 79 लाख है।

देश में विभिन्न क्षेत्रों से विज्ञान, खेल, अणु, तेल–गैस, बैंकिग, बाल शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा, विद्युत, मौसम, भू–गर्भ, उद्योग, भूगोल, समाजशास्त्र, पर्यावरण, साहित्य, धार्मिक, पुरातत्व एवं इतिहास, जल परीक्षण, भूमि संरक्षण, विधि एवं न्यायपालिका से सम्बन्धित, वास्तु शास्त्र, सैन्य विज्ञान, वन संरक्षण, पत्रकारिता, गृह विज्ञान के अन्तर्गत अनेक विषयों पर वायुयान–जलयान निर्माण पर तकनीकी पुस्तकें, ध्वनि तरंग, वाद्य यन्त्रों एवं गायन, ललित कला के सभी क्षेत्रों पर, मुद्रण, पुस्तकालय विज्ञान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के विभिन्न विषयों पर, प्राकृतिक एवं योग क्रिया विषयक, सौन्दर्य प्रसाधनों एवं घरेलू साज सज्जा (इंटीरियर डेकोरेटर) आदि पर हिन्दी में प्रचुर साहित्य प्रकाशित हो चुका है। इन सभी को नकारते हुए अंग्रेजी परस्त हिन्दी में कुछ भी नहीं लिखा जाने का झूठा ढिंढोरा पीटते रहते हैं। दक्षिण चेन्नई से 14 भाषाओं में प्रकाशित 'चन्दा मामा' का हिन्दी संस्करण 'कल्याण' 'नवनीत', 'कादम्बिनी', साहित्य अमृत', 'वीणा' आदि पत्रिकायें संसार के विभिन्न देशों में पढ़ी जाती है। विज्ञान में मोबाइल तथा हिन्दी सिनेमा के हालीवुड क्षेत्र, विश्व में अमेरिका के वालीवुड से बराबर टक्कर ले रहें हैं।

वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में देश में भी कई आयाम परिवर्तित हुए हैं। इनमें से एक प्रमुख क्षेत्र हिन्दी भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रयोगकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं। नियमतः किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसका अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से आन्तरिक सम्बन्ध हो। राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे देश की बहुसंख्यक जनता उस भाषा को बोलती–समझती हो। इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्थान दिया गया। यह भी कैसी विडम्बना है कि अंग्रेजी समर्थकों ने योजनापूर्वक प्रचार किया कि हिन्दी ज्ञान के चलते रोजगार या ऊँचे पद पाना संभव नहीं। जब कि इसके विपरीत हिन्दी में भी रोजगार का एक बड़ा बाजार है।

भारत में जनता की भाषा हिन्दी है इसकी जगह अंग्रेजी कभी नहीं ले सकती है। जो लोग अंग्रेजी की बात करते हैं वह अंग्रेजी के विभिन्न पेशे मीडिया, पीअर, टीचिंग अथवा लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इनके सम्मुख जब धन कमाने या व्यवसाय की बात आती है तो वे हिन्दी की तरफ भागते हैं। कार्पोरेट जगत भी यह जान चुका है कि यदि हिन्दी की ओर नहीं भागे तो धन कमाना कठिन हो जायेगा। अंग्रेजी कम्पनियों की बाजार की दशा को देखते हुए अपने विज्ञापन हिन्दी में दे रहें हैं। वर्तमान हिन्दी मीडिया धन कमाने की दौड़ में

भी काफी अग्रसर है। जब कि अंग्रेजी मीडिया का ग्राफ क्रमशः तेजी से नीचे जा रहा है। इसीलिए अंग्रेजी मीडिया के लोग भी हिन्दी मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस चुनौती को स्वीकार करने के हिन्दी वालों को द्विभाषी बनना होगा। हिन्दी में पकड़ बनाने के लिए 'भाषा दक्षता' अति आवश्यक है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली विश्वविद्यालय में जब स्नातक स्तर पर हिन्दी जन संचार पाठ्यक्रम का श्री गणेश हुआ तो उसमें अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी भाषी के अलावा दूसरे देशों के अहिन्दी भाषी भी सम्मिलित हुए। हिन्दी के शक्तिशाली स्वरूप को समझते हुए इसे भविष्य में अपनी ताकत बनाने व अपनाने की है जो उसे रोजगार तक ले जा सकती है।

इस समय विदेशी कंपनियों में घरेलू स्तर के 'काल सेन्टरों' में हिन्दी जानने वाले भी बड़ी संख्या में रोजगार पाने लगे हैं। एक समय ऐसा था जब मात्र अंग्रेजी जानने वालों का ही 'काल सेन्टरों' में वर्चस्व था किन्तु वर्तमान समय में सैकड़ों 'काल सेन्टरों' में हिन्दी के जरिए ग्राहकों की बात सुनने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया जा रहा है। इससे हिन्दी के प्रति रूचि की अभिवृद्धि के साथ आय भी भली भाँति हो रही है।

हिन्दी तकनीकी क्षेत्र में जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रही है उसमें अनेक वेबसाइट में प्रमुख हिन्दी वेबसाइट उल्लेखनीय है, प्रमुख हिन्दी वेबसाइट–

www.bbc.co.uk.hindi,/www.hindinest.com,/www.jagransahitya.com./
www.sanskritgde.com,/www.webduniya.com,/www.litratureword.com/
www.abhivkti.com,/www.bharatdarshan.com/www.prabhasakhi.com

पत्र पत्रिकाओं एवं चैनल्स के अलावा हिन्दी का एक वर्ग ऐसा भी है जो वेबसाइट पर अपनी जिज्ञासाओं एवं सूचना सम्बन्धी समस्याओं का समाधान चाहता है। इसके अलावा प्रत्येक सुविधा सम्पन्न व्यक्ति को ब्लॉग्स लिखने का सुरूर चढ़ा हुआ है। चाहे अमिताभ बच्चन हों, आमिर खान या अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश, हर कोई दीवाना बनता जा रहा है। यह शौक जानकारियों के आदान–प्रदान के अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से मीडिया में अधिक प्रचलित हो चुका है।

आई0आई0एम0सी0, दिल्ली के हिन्दी पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर आनन्द प्रधान के अनुसार 'जिस तेजी से हिन्दी वेबसाइट्स को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसी तीव्रता से इसमें प्रशिक्षित लोगों की मांग भी बढ़ी है। अधिकांश समाचार पत्रों एवं चैनलों ने अपना हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया है।'

वर्तमान हिन्दी की अभिवृद्धि में आधुनिक तकनीक का भी विशेष योगदान है, आज हिन्दी के प्रति जितना अनर्गल दुष्प्रचार भारत में किया जा रहा है उतना संभवतः विदेशों में भी देखने–सुनने को नहीं मिलेगा। जबकि इसमें रोजगार की संभावनाएं वृहत हैं। हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सिनेमा का भी प्रमुख स्थान रहा है। अब टेलीविजन के धारावाहिकों ने

घर–घर में सिनेमा से अधिक इस ओर आकर्षित कार्यक्रमों में टीवी चैनलों में पटकथा लेखक, अभिनय, कैमरामैन, निर्देशक, सहायक निर्देशक, वितरण सम्बन्धी मार्केटिंग के कार्य, विज्ञापन, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडीटर से लेकर कोरियोग्राफर तक के कार्यों में रोजगार के विकल्प हैं।

इसी प्रकार आकाशवाणी का एक नया स्वरूप 'एफ एम चैनल' चर्चित हुआ है। आज अनेक ऐसे एफ एम चैनल लगातार 24 घंटे चलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनमें कुछ प्रमुख चैनल– रेडियो मिर्ची 98.3/रेड एफ एम 93.5/फीवर 104/रेडियो सिटी 91 एफ एफ/ए आई आर एफ एम रेनबो 102.6/ए आई आर एफ एम गोल्ड में काम करने के रूप में संवाददाता, पटकथा लेखक, एंकर निर्देशक एवं सहायक निर्देशक पद पर काम करने वालों को वेतन भी अधिक मिलता है। टीवी के हिन्दी समाचार चैनलों का विस्तार हिन्दी की जनप्रियता का एक प्रमाण है। जब विदेशी चैनलों का देश में आगमन शुरू हुआ तब हिन्दी चैनल अपने को संकट में मानने लगे किन्तु हिन्दी के वर्चस्व ने उस भ्रम को दूर कर दिया कि हमारा अस्तित्व ये विदेशी चैनलें समाप्त कर देगें। इनकी शीघ्र ही समझ में आ गया कि हिन्दी के बिना विदेशी चैनल चलना सम्भव नहीं। आज स्थिति यह है कि 75 प्रतिशत चैनल हिन्दी भाषा के ही हैं किन्तु यह परिवर्तन अवश्य हुआ कि उसकी अधिकांश भाषा हिंगलिश काम चलाऊ हिन्दी का प्रयोग होने लगा। इसके बढ़ते प्रभाव से दक्षिण के राज्यों में भी सिनेमा से अधिक हिन्दी चैनल प्रभावी हो गये हैं। हिन्दी की लोक प्रियता के कारण समाचार चैनल हिन्दी में बी0बी0सी0 तथा सी0एन0एन0 जैसे बड़े विदेशी चैनल भी यथा शीघ्र ला रहें हैं।

तकनीकी क्षेत्र में संचार में 'नई दुनियाँ' में 'वेब दुनिया' का शुभारम्भ करने का श्रेय अजय छजलानी को है जिनको उ0प्र0 हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया था। इधर हिन्दी अनुवादकों की आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। इसमें 'गूगल' नामक वेबसाइट ने अनुवाद क्षेत्र में एक क्रान्ति ला दी है। इसमें अंग्रेजी में शब्द या वाक्य टाइप करने के बाद उसका हिन्दी में अनुवाद होता जाएगा। यह एक अनूठी खोज है वरना अनुवाद करने हेतु अनुवादकों की जरूरत पड़ती थी। अनुवादकों को भी जटिल वाक्य आ जाने से उनसे जूझना पड़ता था। इस वेब साइट का विवरण है – www.GOOGLE.IN/TRANSLATE.

2008 में बीजिंग में हुए ओलम्पिक खेलों की विश्व में सर्वाधिक चर्चा थी। क्या अंग्रेजी भाषी अमेरिका ब्रिटेन ने अधिक स्वर्ण पदक पाये हैं? सन् 1988 के दक्षिण कोरिया के 'सियोल' में रूस ने 55 स्वर्ण पदक प्राप्त किये थे, जब कि बीजिंग ओलम्पिक खेलों में चीन ने सर्वाधिक 51 स्वर्ण पदक जीतकर संसार में एक नया कीर्तिमान बनाया। रूस और चीन दोनो देशों ने क्या विश्व में खेल प्रतियोगिता में 'अंग्रेजी भाषा' की बदौलत स्वर्ण पदक हासिल किये? खेल उद्घोषकों में पंजाबी भाषी सरदार जसदेव सिंह की हिन्दी में 'आँखों देखा हाल' का वर्णन

अपने भारत के अलावा विदेशों के हिन्दी–उर्दू भाषी लोगों में भी अति लोकप्रिय रहा। उस वर्ष भारत सरकार ने श्रेष्ठ हिन्दी खेल उद्घोषक (कमेन्ट्रेटर) के रूप में उनको 'पदम् श्री' सम्मान भी प्रदान किया।

हिन्दी के प्रचार–प्रसार में पहले सिनेमा के योगदान की चर्चा होती थी, किन्तु मीडिया के प्रिन्ट तथा संचार दोनों माध्यमों ने जिस तीव्रगति से विश्वव्यापी हिन्दी की धारा की अकल्पनीय अभिवृद्धि की है, वह प्रशंसनीय है। अमेरिका, कनाडा और इंग्लैण्ड जैसे अंग्रेजी भाषी देशों में जाकर जिस शुद्ध हिन्दी में स्वामी रामदेव बोलते हैं– वहाँ कहीं भी हिन्दी विरोध की चर्चा तक नही हुई। अंग्रेजी भक्तों ने वैज्ञानिक 'देवनागरी लिपि' को रोमन लिपि में प्रसारित कर उसे समाप्त करने का षडयन्त्र काफी समय से कर रखा है।

इस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से संपादक प्रवर पं0 अच्युतानन्द मिश्र ने 'पं0 माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल' के कुलपति रूप में जिस लगन एवं कर्मठता से हिन्दी मीडिया के कुशल शिक्षण संचालक बन उसके प्रकाश स्तम्भ बने। कुलपति श्री मिश्र ने हिन्दी पत्रकारिता के गौरवशाली संघर्षपूर्ण अतीत तथा वर्तमान की आधुनिक तकनीकी जानकारी द्वारा हिन्दी मीडिया का अंग्रेजी के वर्चस्व को एक बड़ी चुनौती दी है। विगत वर्ष अमेरिका के न्यूयार्क में आयोजित 8वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में वैश्वीकरण हिन्दी मीडिया के प्रभावशाली भाषण से कुलपति मिश्र हिन्दी मीडिया के मील के पत्थर बने। श्री मिश्र का विश्व हिन्दी सम्मेलन में उनके क्रान्तिकारी कार्यों से जो हिन्दी मीडिया क्षेत्र में जानकारी तथा प्रगति हुई उस पर उनको न्यूयार्क में सम्मानित भी किया गया। हिन्दी पत्रकारिता की अति श्रेष्ठ मासिक पत्रिका–''मीडिया मीमांसा'' का वह सम्पादन भी करते हैं। भोपाल से ही माधवराव सप्रे पत्रकारिता ग्रंथालय–संग्रहालय में हिन्दी–उर्दू का श्रेष्ठतम संग्रह है। इसके अलावा विद्वान निदेशक श्री विजय दत्त श्री धर ''आँचलिक पत्रकार'' का सम्पादन भी करते हैं।

देश के स्वाधीनता संग्राम में भी हिन्दी का विशेष योगदान रहा है। राष्ट्रीय प्रेरक हिन्दी गीतों ने देशभर में शंखनाद किया। स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा में अधिकांश अहिन्दीभाषी सदस्यों श्री गोपाला स्वामी आयंगार, श्री के0एम0 मुंशी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रभृति ने भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। विदेशों में लगभग 2 करोड़ प्रवासी भारतीयों में विश्व कवि तुलसी के रामचरित मानस और हनुमान चालीसा ने देश की संस्कृति और भाषा को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। विदेशी में विश्व विद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन के अलावा वहाँ के मन्दिरों में भी हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है। हिन्दी का सर्वप्रथम शोध इटली के फ्लोरेन्स विश्वविद्यालय में सन् 1911 में 'तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्यन' इतावली भाषा में डा0 एल0पी0 टेसीटरी ने किया। दूसरा शोध भी लंदन विश्वविद्यालय में सन् 1918 में डा0

जे0एन0 कारपेन्टर ने 'थियोलाजी ऑफ तुलसीदास' पर किया। अब तक तुलसी पर एक हजार से अधिक शोध प्रबन्ध देश–विदेश के विश्वविद्यालयों में होने का कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। इसके पूर्व सन् 1871 में फोर्ट विलियम कालेज कोलकाता के मुंशी अदालत खाँ की राय से भारतीय समाज की आचार संहिता के रूप में तुलसी कृत मानस के एक काण्ड का अंग्रेजी में अनुवाद करके उच्च प्रशासनिक शिक्षा–आई0सी0एस0 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। मारीशस में 'तुलसी जयन्ती' को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है जिसके समारोह में वहाँ की सरकार ने आयोजन में आमन्त्रित करने पर भाग भी लिया था। इस हिन्दी दिवस पर मारीशस के प्रख्यात साहित्यिक श्री सोमदत्त बुखारी की रेखांकित पंक्तियों से अनुभव कर सकेगें–

.....हिन्दी जन सके मध्य में/तुलसी जयंती के आलोक में/हिन्दी दिवस के प्रभात में /सरस्वती माँ के गोद में/अपनी लाडली हिन्दी के लिए/इस लम्बी यात्रा में/अबला पद यात्री को/जहॉ दुष्टों की फटकार मिली/.....सहृदय भक्तों के हाथों से/फूलों का हार भी मिला/नही तो भगवान जाने/हिन्दी दिवस के प्रकाश में/मुँह दिखाती कौन सा ?.....

..... कहाँ–कहाँ आश्रय मिला/पद दलित पद यात्री को/कभी मजदूरों की झोपड़ियों में/तो कभी गाँवों की बैठकों में/कभी कथा वाचकों के पंडालों में/तो कभी समाज के मन्दिरों में/मारीशस के लब्ध प्रतिष्ठित कवि श्री ब्रजेन्द्र भगत ''मधुकर'' की प्रस्तुत पंक्तियाँ उनकी मित्रों हिन्दी सुमन खिलाएं/'' उनकी दूसरी कविता श्रद्धांजलि में कहते हैं– ''तुलसी ने रामायण लिखकर/रक्षा की है हिन्दी की/.....'' हिन्दी के भीष्म पितामह पद्मविभूषण पं0 श्री नारायण चतुर्वेदी ने हिन्दी के विकास हेतु मात्र कविता–कहानियों से ही नही वरन् सभी क्षेत्रों में कार्य करने पर जोर दिया। न्यायपालिका क्षेत्र में भी हिन्दी में कई न्यायमूर्तियों ने उच्च न्यायालय में हिन्दी में निर्णय देकर अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त किया। सर्वाधिक हिन्दी में निर्णय देने वाले न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्ता को न्यूयार्क के 8वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में सम्मानित भी किया गया। न्यायमूर्ति श्री गुप्त ने चार हजार से अधिक हिन्दी में निर्णय दिये। इस समय प्रवासी भारतीयों ने भी सभी क्षेत्रों में हिन्दी सृजन की विकास यात्रा तीव्र गति से अग्रसारित की है किन्तु अंग्रेजी भक्तों का वही पुराने दुष्प्रचार की रट कि बिना अंग्रेजी के उन्नति सम्भव नहीं। इसका क्या उत्तर है कि रूस, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी आदि ने भी विज्ञान–औद्योगिक आदि सभी क्षेत्रों में जो उन्नति की है– वह अपनी भाषाओं में किया अथवा अंग्रेजी भाषा से हम विदेशी मानसिक दासता से कब मुक्त होकर अपनी माँ को ही माता का दर्जा दें न कि 'आया' को माँ समझ बैठें ?

वर्तमान शिक्षा : व्यवस्था का यथार्थ

–कृष्ण कुमार यादव, (आई.पी.एस.)
निदेशक डाक सेवा
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर–744101
kkyadav.y@rediffmail.com,
http://kkyadav.blogspot.com

भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य है – 'तमसो मा ज्योतिर्गमय।' अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की इस प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय परम्परा में शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा के विकास द्वारा मुक्ति का साधन माना गया है। शिक्षा का मानव को उस सोपान पर ले जाती है जहाँ वह अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इस समग्र व्यक्तित्व विकास में सिर्फ भौतिक परिलब्धियाँ ही नहीं बल्कि शारीरिक व मानसिक विकास के साथ–साथ बौद्धिक परिमार्जन, सांस्कृतिक चेतना एवं नैतिक व सामाजिक मूल्यों का उन्नयन भी महत्त्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानन्द के शब्द यहाँ याद आते हैं – ''वास्तव में सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य 'मनुष्य निर्माण' ही होना चाहिए। सारे प्रशिक्षणों का अन्तिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छाशक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है षिक्षा।''

स्पष्ट है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली मनुष्य के परिष्कार का साधन है। वेदांतों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि – ''समस्त ज्ञान हमारे अन्दर ही विद्यमान है। एक शिशु में भी है, केवल उसे जागृत करना है। शिशु में 'ज्ञान' का जागत होना ही शिक्षा कहलाती है।'' 'शिक्षा' शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्षाविद्योपादाने' से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है – 'विद्या का उपादान।' 'उप' माने 'समीप' एवं 'आदान' माने 'ग्रहण' अर्थात् किसी के समीप जाकर विद्या ग्रहण करना। इसी परिभाषा के अनुसार प्राचीन काल में गुरुकुल परम्परा थी, जहाँ राजा व रंक दोनों एक साथ गुरु के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। इस शिक्षा से जहाँ घर एवं परिवार के प्रति आसक्ति दूर होती थी, वहीं समभाव भी पैदा होता था। यह शिक्षा मात्र किताबी नहीं थी बल्कि इसमें आचरण, नैतिक मूल्य, संस्कर, बौद्धिक परिमार्जन, भावनात्मक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य एवं प्रकृति व अन् प्राणियों का साहचर्य शामिल था। हमारी प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था अनमोल और शाश्वत है। यह हमें आज भी सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को चहरदीवारियों में कैद नहीं रखती, बल्कि उनमें अन्तर्निहित सम्भावनाओं को अनन्त विस्तार देती है। पाश्चात्य दार्शनिक काण्ट के शब्द गौरतलब हैं – ''शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, जिस पर वह पहुँच

सकता है।''

शिक्षा का यह परम्परागत रूप लम्बे समय तक चला पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने इसमें अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु आमूल–चूल परिवर्तन किये। शिक्षा की मैकाले नीति ने पूरा ढर्रा ही बदल दिया। वर्तमान दौर में देखें तो वाकई चीजें काफी हद तक परिवर्तित हो चुकी हैं। यथार्थ के धरातल पर आज शिक्षा की कसौटी ही बदल गयी है। सतत् चलने वाली प्रक्रिया की बजाय शिक्षा को स्कूल–कालेजों की चहरदीवारियों में कैद कर दिया गया है। शिक्षा का एक मात्र उद्देष्य अच्छा कैरियर बनाना हो गया है। पढ़ाई में कोई कितना भी निपुण हो, परन्तु बिना अच्छे कैरियर के उसका कोई मोल नहीं रह गया। कभी साहचर्य और समन्वय शिक्षा के अभिन्न अंग थे, पर अब तो इसने विद्यार्थियों को आपस में ही प्रतिस्पर्धी बना दिया है। किताबी कीड़े बनाती शिक्षा की कसौटी पास या फेल होने तक रह गयी है। कभी कोई फेल होने की आशंका में आत्महत्या कर रहा है तो कोई कम अंक पाने पर। आई0 आई0 टी0 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हर साल बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं तनाव न झेल पाने के कारण न जाने कितने विद्यार्थी मौत को गले लगा लेते हैं। आत्मोन्नति पर भौतिक उपलब्धियाँ और पदोन्नति हावी है। बहुत पहले इस ओर इंगित करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि – ''हम देखते हैं कि सर्वोच्च बौद्धिक शिक्षा प्राप्त किये हुए लोगों में कई अधार्मिक पुरुष हुए हैं। पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों में से यह भी एक है कि यहाँ हृदय की परवाह न करते हुए केवल बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा मनुष्य को दस गुना अधिक स्वार्थी बना देती है।'' ऐसे में इस शिक्षा की व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा–व्यवस्था का मूलाधार है, पर अपने देश में सबसे ज्यादा संसाधनों का अभाव एवं अकर्मण्यता इसी स्तर पर देखी जाती है। हाल ही में स्वयं सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक मामले में जानकारी दी है कि देश भर में करीब 1700 स्कूल तंबुओं में चल रहे हैं, लगभग 24,000 स्कूलों में पक्के भवन नहीं हैं। यही नहीं, एक लाख स्कूलों में पीने के पानी और करीब पैंतालीस फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 49 फीसदी स्कूलों में खेल के मैदान की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में अन्य आवश्यक संसाधनों के बारे में मात्र कल्पना ही की जा सकती है। वर्तमान स्थिति में अभी भी देश में 5 लाख से अधिक अतिरिक्त शिक्षक, 3 लाख से अधिक प्रशिक्षक व 14 लाख से अधिक अतिरिक्त क्लास रूमों की जरूरत है। सरकार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना एवं छह से चौदह साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जैसी तमाम योजनाएँ लागू कर रही है, पर जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन उस भावना से कोसों दूर है। स्वयं मई 2002 में लागू 6–14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा

के अधिकार को कानून बनाने में संसद को पूरे सात साल लग गये और यह वर्ष 2009 में जाकर पारित हुआ। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को लागू हुए एक साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक देश में 15 राज्यों ने ही इस कानून को अधिसूचित किया है। सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009–10 में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.46 फीसदी और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.12 फीसदी रहा। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का नामांकन दर 19.81 फीसदी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों का नामांकन दर महज 10.93 फीसदी दर्ज किया गया। इसी से सरकारों की इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की छियासी प्रतिशत बेटियाँ प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देती हैं और चौंसठ फीसदी माध्यमिक कक्षाओं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पातीं। जनगणना 2011 (प्रोविजनल) के आंकड़ानुसार देश में महिला साक्षरता 65.46 है और मात्र तेईस प्रतिशत को रोजगार मिल पाता है। प्राथमिक स्तर पर प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर विभेद, तमाम प्रावधानों के बावजूद स्कूलों में दलित छात्र–छात्राओं के साथ विभेद, बालिकाओं का घर से बाहर न निकलना, मिड–डे मील के नाम पर खानापूर्ति के लिए बच्चों का नामांकन जैसे तमाम कारण प्राथमिक शिक्षा में बाधक हैं। देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कम नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में दाखिल छात्रों की संख्या 13,34,05,581 है जबकि उच्च प्राथमिक स्कलों में नामांकन प्राप्त 5,44,67,415 है। साल 2020 तक सकल नामांकन दर को वर्तमान 12 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के 2009–10 के आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लक्ष्य के बीच देश में अभी कुल 44,77,429 शिक्षक ही हैं। देश का शायद ही ऐसा कोई प्रांत हो, जहाँ विद्यार्थियों के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति हो, फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे? अभी भी देश में छात्र शिक्षक अनुपात 32 : 1 है, जबकि 324 ऐसे जिले है जिनमें छात्र शिक्षक अनुपात 3 : 1 से कम है। देश में नौ फीसदी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है तो 21 फीसदी ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास पेशेवर डिग्री तक नहीं है। उस पर से ग्रामीण स्कूलों में एक चौथाई शिक्षक खुद ही गैरहाजिर रहते हैं और अपने व्यक्तिगत कार्यों को तरजीह देते हैं। मतगणना–जनगणना से लेकर अन्य तमाम कार्यों में प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी भी उन्हें मूल शिक्षण कार्य से विरत रखती है। ऐसे में जब शिक्षा की नींव ही कमजोर होगी, तो विद्यार्थियों का उन्नयन कैसे होगा, यह एक गम्भीर समस्या है।

महात्मा गाँधी ने कहा था कि – ''जिस शिक्षा का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता, वह

कुछ काम की नहीं होती।'' पर उच्च शिक्षा का सीधा सम्बन्ध आज रोजगार से जुड़ गया है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा बढ़ना लाजिमी भी है। इस प्रतिस्पर्धा की आड़ में उच्च शिक्षा में कुकरमुत्तों की तरह फैलते कालेजों एवं कोचिंग संस्थाओं ने अच्छा–खासा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। यहाँ शिक्षा की बाकायदा कीमत वसूल की जाती है, ऐसे में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों पर दवाब पड़ना स्वाभाविक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की मानें तो विश्व के करीब 25 फीसदी स्कूली छात्र मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। जाहिर है भूमण्डलीकरण के दौर में उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण छात्र–छात्राओं में कई तरह की कुंठाएँ भी उत्पन्न हो गयी हैं। किताबों का बढ़ता बोझ, शिक्षकों एवं अभिभावकों की बढ़ती अपेक्षाएँ व तदनुरूप विद्यार्थियों का विकास समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बच्चे अपने आप में सिमटते व सिकुड़ते जा रहे हैं और उनकी दुनिया टी0 वी0 व इंटरनेट तक बँध कर रह गयी है। इस हालत में उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है एवं अन्ततः एकाकीपन व दबावों के बीच उनमें आत्महत्या एवं हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में तो यह स्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में 12.4 फीसदी लोग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जबकि 1950 में यह आंकड़ा एक फीसदी से भी कम था। जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं की कमी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक यथार्थ बन गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो आजादी के समय 1947 के 20 विश्वविद्यालयों और 500 महाविद्यालयों की तुलना में आज 504 विश्वविद्यालय एवं 25,951 कालेज (2,565 महिला कालेज सहित) हैं, जहाँ एक करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो भारत की एक अरब से ज्यादा जनसंख्या का महज 12.4 फीसदी हैं, जबकि विकसित देशों में यह सकल भर्ती दर 58 फीसदी के करीब है।

ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब बातों से बेफिक्र है। स्वयं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का मानना है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 12.4 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना होगा और इसके लिए अगले 12 वर्षों में अतिरिक्त 600 विश्वविद्यालयों एवं 35,000 महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी। पर वाकई यह उतना आसान नहीं दिखता। शिक्षाविदों की मानें तो 2020 तक सकल भर्ती दर को 20 फीसदी पहुँचाने के लिए ही मौजूदा उच्च शिक्षण संस्थाओं की क्षमता दोगुनी करनी होगी, जो कि दुःसाध्य कार्य दिखता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा पर जी0 डी0 पी0 का एक प्रतिशत भी नहीं खर्च किया जा रहा है, जिसे अच्छा–खासा बढ़ाने की जरूरत है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज हम व्यापक भूमण्डलीकरण तथा गहन प्रतिस्पर्धा के

कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। यह क्षेत्र लगातार अंतर आयामी, बहुआयामी और बहुद्देशीय होता जा रहा है। भारत के पास उन बड़ी शक्तियों में शामिल होने की पूरी क्षमता है, जिनकी 21वीं सदी में प्रमुख भूमिका होगी। ऐसे में सारी दुनिया भारत की युवा शक्ति पर टकटकी लगाये हुए है। अगर इन युवाओं को सही ढंग से तराशा और संवारा जाये तो वे राष्ट्रीय गौरव का एक नया इतिहास रच सकते हैं। युवा वर्ग अपनी मेधा, परिश्रम और लगन से सबको चमत्कृत कर सकते हैं और युवा शक्ति भारत को विश्व का मुकुटमणि बना सकती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण हमारी प्राथमिकता में शामिल हो। ऐसे में शिक्षण संस्थाएँ, युवाओं के मस्तिष्क के लिए नये क्षितिजों के द्वार खोलने और उन्हें आज के जीवन सन्दर्भों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए तैयार करती हैं। पर हमारे यहाँ तो अधिकतर विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान यहाँ तक कि मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेज भी भारी डोनेशन लेकर विद्यार्थियों का प्रवेश ले रहे हैं और बदले में डिग्रियाँ बाँटने के केन्द्र बन गये हैं। प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को दरकिनार कर शिक्षा बिकाऊ हो चुकी है। भौतिक शोधों की बजाय विदेशी विद्वानों के शोधों की नकल और इंटरनेट से कट–पेस्ट करने की जुगाड़ी प्रवत्ति के चलते नये विचारों व नई प्रवृत्तियों का उद्‌भव नहीं हो पा रहा है।

कोई भी राष्ट्र जब शिक्षा पर खर्च करता है तो उसके पीछे सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान की अपेक्षा भी रखता है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की बेहतरी के उद्‌देश्य से केन्द्र सरकार हर साल लाखों–करोड़ों के बजट वाली योजनाएँ बनाती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी0 डी0 पी0) में उच्च शिक्षा के लिए छह फीसदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन जी0 डी0 पी0 का 3.8 फीसदी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2010–11 में शिक्षा क्षेत्र का कुल बजट 16 फीसदी बढ़ाते हुए 42,036 करोड़ कर दिया। 2011–12 के लिए पेश किये गये केन्द्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 52,057 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जो वित्त वर्ष 2010–11 से 24 फीसदी अधिक है। इतना ही नहीं 13वें वित्त आयोग से भी राज्यों को 3,675 करोड़ रुपये मिलेंगे। उच्च शिक्षा के खाते में 13,100 हजार करोड़ रुपये डाले गये हैं। केन्द्रीय धन की निगरानी के लिए आयोगों और समितियों की लम्बी फेहरिस्त है, फिर भी शिक्षा क्षेत्र के हालात बहुत अच्छे नहीं है।

भारतीय सन्दर्भ में बात करें तो यहाँ ब्रेन–ड्रेन अर्थात् प्रतिभा पलायन एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत से अमेरिका जाने वाली प्रतिभाओं के कारण भारत को 700 मिलियन डालर की राजस्व हानि होती है, जो कि भारत की कुल आय का 12 फीसदी

बनता है। स्पष्ट है कि सारी क्रीम विदेशों की तरफ जा रही है। प्रत्येक 10 में से 4 साफ्टवेयर विशेषज्ञ अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। यही नहीं आज अमेरिका में 38 फीसदी डॉक्टर और 12 फीसदी वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी 'नासा' में 36 फीसदी वैज्ञानिक और इंजीनियर भारतीय हैं तो 'माइक्रोसॉफ्ट' कम्पनी के 34 फीसदी तकनीकी विशेषज्ञ और 'इंटेल' कम्पनी में 20 फीसदी इंजीनियर भारतीय हैं। अकेले 1998 में आई0 आई0 टी0 से निकले 30 प्रतिशत कम्प्यूटर इंजीनियरों ने अमेरिका में नौकरी कर ली। इसके विपरीत आज भी देश में 60,000 से अधिक इंजीनियर बेरोजगार हैं, जो कि शिक्षा–प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में टेक्नॉलाजी व वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कम्पनियों की शिकायत है कि उनके पास 10 स्नातक नौकरी के लिए आते हैं, तो मात्र 3 ही अनिवार्य कुशलता पूरी करने योग्य होते हैं। प्रमुख उद्योग संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट की मानें तो देश में हर वर्ष दो लाख एमबीए, छह लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग स्नातक निकलते हैं, लेकिन इनमें से एक चौथाई ही नौकरी के योग्य होते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90 फीसदी स्नातक नौकरी पाने योग्य नहीं होते। इसका कारण है कि जहाँ आई टी, सेवा, मानव संसाधन, बीमा जैसे क्षेत्रों में 90 फीसदी नौकरियाँ व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय रूप से दक्ष लोगों के लिए है, वहीं देश की कार्यशील आबादी के महज छह फीसदी को ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो पाती है। इसके विपरीत दक्षिण कोरिया के 96 फीसदी, जापान के 80 फीसदी व जर्मनी के 75 फीसदी कामगारों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे में उच्च शिक्षा के आयाम बढ़ाने के साथ–साथ प्रतिभा–पलायन रोकना भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

भारत में उच्च शिक्षा पर व्यय की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विदेशों में शिक्षा ले रहे भारतीय छात्रों का खर्च हमारे उच्च शिक्षा बजट से दोगुना है। वर्ष 2011–12 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए 13,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के एक आकलन के मुताबिक विदेशी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र करीब 5.5 अरब डालर यानी करीब 24.750 करोड़ रुपये चुकाते हैं। ऐसा असन्तुलन भी कहीं–न–कहीं व्यवस्था को प्रभावित करता है, इस ओर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। अभी लगभग 2.64 लाख भारतीय छात्र विभिन्न देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए प्रति छात्र औसतन 10 लाख रुपये विदेशी और ब्रिटेन में 20 हजार छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैण्ड, नीदरलैण्ड आदि देशों में भी काफी संख्या में भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा पर गठित समिति के अध्यक्ष शिक्षाविद् प्रो. यशपाल

की मानें तो देश में तकरीबन 20,000 कॉलेज हैं जिनमें से 1,500 कॉलेज काफी अच्छे हैं और उनमें बेहतर आधारभूत सुविधाएँ हैं। ऐसे कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है।

बदलाव प्रकृति का नियम है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही। आज शिक्षा अपने परम्परागत स्वरूप से हटकर 'ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था' की ओर अग्रसर है। शिक्षा और रोजगार में अनन्य सम्बन्ध एवं तदनुसार उन्नत मानव संसाधनों के साथ विकास दर की ऊँचाइयों को छूना इसका ध्येय है। जैसे–जैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, वैसे–वैसे तमाम नये उद्यम भी सामने आ रहे हैं। इनके लिए दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता है और साथ ही इस काम के लिए इन्हें विशेष कौशल प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र होने के साथ–साथ सबसे बड़ा बाजार भी मुहैया कराता है। ऐसे में शिक्षा को उत्पादन से जोड़ वांछित, सार्थक और लाभदायक योगदान की अपेक्षा की जा रही है। एक तरफ शिक्षा संस्थाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता बनाने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों को बुलाने की योजना चल रही है, वहीं इग्नू जैसी संस्थाएँ देश के कोने–कोने में दूरस्थ शिक्षा को आसान कर रही हैं। ई–शिक्षा ने भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमारे पास वर्चुअल लैब और प्रौद्योगिकी सम्पन्न केन्द्र हैं जिनके जरिये न केवल शिक्षा पहुँचाई जा सकती है बल्कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया की जा सकती है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज खोलना और इनके लिए बुनियादी संरचना का विकास करना सम्भव नहीं है।

गौरतलब है कि शिक्षा–साहित्य–संस्कृति की त्रिवेणी ही किसी राष्ट्र को उन्नत बनाती है। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़कर देखना गलत नहीं है बशर्ते परिवार, परिवेश, पर्यावरण और संस्कृति से इसे विरत् न किया जाये। पारिवारिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी, पर्यावरण के प्रति संचेतना, आध्यात्मिक पुरुषों, स्वतन्त्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय वीर पुरुषों के जीवन व आदर्शों के बारे में प्रेरणात्मक पहलू जैसे तमाम तत्त्वों के बिना शिक्षा का उद्देश्य अधूरा है। 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ने बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा है – ''जब हदय में शुद्धता हो/तो चरित्र में सुन्दरता आ जाती है/यदि चरित्र सुन्दर हो तो/परिवार में समरसता होती है।'' राज्यसभा की शिक्षा सम्बन्धी याचिका समिति द्वारा वर्ष

2009 में प्रस्तुत वक्तव्य गौरतलब है – "विज्ञान–सम्मत स्वास्थ्य–शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु उचित एवं आयु विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किया जाये।

शिक्षा का स्वरूप कुछ भी हो, पर सब के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। सामाजिक व आर्थिक विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका है। शिक्षा व्यक्ति के भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार के विकास का आधार तैयार करती है। यह हमारी संवेदनाओं और अवधारणाओं को परिष्कृत बनाती है, जिससे मन–मस्तिष्क को स्वतन्त्रता और उनके बीच तालमेल स्थापित करती है और वैज्ञानिक दृष्टि के विकास में सहाता मिलती है। शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और कौशल को समद्ध बनाती है। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में संसाधनों व अध्यापकों की सुनिश्चितता, उच्च स्तर पर ज्ञान में प्रवीणता हासिल करने के साथ–साथ नये विचारों व सिद्धान्तों का उद्भव एवं व्यावहारिक जीवन में उनका समसामयिक प्रयोग भी अपेक्षित है। तमाम नियम–कानूनों के बावजूद परीक्षाओं में धाँधली, विद्यार्थियों का शोषण एवं जातिवादी राजनीति से शैक्षणिक परिसरों की मुक्ति ही अन्ततः भारत को एक सुखी–समृद्ध–शिक्षित राष्ट्र बना सकेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के शब्द आज भी प्रासंगिक हैं – "भारत को अपने लिए ऐसी संस्कृति तथा शिक्षा का चयन करना होगा जो कि प्राचीन संस्कृति की उत्तमता से प्रेरित हो एवं इसके साथ ही साथ वर्तमान माँगों की भी उपेक्षा न कर सके।"

आपका आत्मविश्वास वह सोमरस है जिसको ग्रहण करके आप मदान्ध हाथी को भी वश में करने का चमत्कार कर सकते हैं, अर्थात् असम्भव को भी सम्भव कर दूसरों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।

समकालीन कविता में अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सन्दर्भ : युद्ध एवं आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में

—डॉ0 राकेश शुक्ल
एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
वी0एस0एस0डी0 कालेज,
कानपुर

शुद्ध साहित्य में राजनीति का प्रवेश भले ही अवांछित माना गया हो पर प्रत्येक युग का साहित्य अपने राजनैतिक परिदृश्य से अप्रभावित नहीं रह सका है। राजदरबारों में कवियों का सम्मान और संरक्षण होने के कारण प्राचीन साहित्य में एक ओर यदि राजाओं की यश कीर्ति का गायन हुआ तो दूसरी ओर 'संतन को कहा सीकरी सों काम' वाले कवियों ने तत्कालीन राजनीति और राजाओं का मार्गदर्शन भी किया।

आधुनिक साहित्य विशेषकर समकालीन साहित्य के केन्द्र में मनुष्य है इसलिए समकालीन कवियों ने अपने समाज या देश ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व के राजनैतिक परिदृश्य को अपनी लेखनी का अनिवार्य हिस्सा बनाया। समाज की राजनैतिक स्थिति की अभिव्यक्ति में भी यह नये तेवर का काव्य है। जनतंत्र और गणतंत्र का जैसा मजाक आज की राजनीति में हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके साथ जनसाधारण की आशाएं और उमंगे जुड़ी हुई हैं किन्तु आज यह लोकतंत्र कितना खोखला, निराशाजनक और निरर्थक साबित हुआ है। समकालीन राजनीति मात्र चुनाव, कुर्सी और वोट की राजनीति तक सिमट कर रह गई है। राजनीति के इस विद्रूप को कविता का विषय बनाया गया है। देश के भीतर अलगाववाद, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद सहित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आपराधिक कृत्यों पर तो इन कवियों ने गहरी चिन्ता प्रकट की ही है, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अनेक देशों के बीच होने वाले युद्धों की विभीषिका, वैश्विक स्तर पर फासीवादी, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकतों की भी आलोचना की है। दो—दो विश्वयुद्धों की विभीषिका से सारा विश्व आज तक उबर नहीं सका है बावजूद इसके विश्व के अनेक देश किसी न किसी रूप में युद्धरत हैं। जनसंचार के अत्याधुनिक और तीव्रगामी माध्यमों के बीच वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण के युग में विश्व के किसी भी कोने में घटित छोटी सी घटना से भी हम अप्रभावित नहीं रह सकते। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटना प्रत्येक व्यक्ति को आन्दोलित कर देती है। समकालीन कवियों के काव्य में अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ अनकेशः व्यक्त होते रहते हैं। वियतनाम, चेकोस्लोवाकिया, बांग्लादेश, द0 अफ्रीका, ईराक,

फलस्तीन, इजराइल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोरिया, ईराक, भारत आदि देशों की घटनाओं ने भारतीय जनमानस को गहराई तक प्रभावित किया है। विगत पचास वर्षों में इन देशों में अनेक नरसंहार हुए हैं, चाहे वे युद्ध के माध्यम से हुए हों, तानाशाही शासन के द्वारा अथवा आतंकवादी घटनाओं द्वारा। वियतनाम पर अमेरिकी आक्रमण ने वहाँ की जनता पर जो कहर बरपाया उससे सम्पूर्ण विश्व आतंकित और आन्दोलित हुआ। फलस्तीन और इजराइल के बीच निरन्तर युद्ध की झड़पें होती रहीं, जिनमें हजारों निरीह व्यक्ति मारे गये। कुवैत पर वर्चस्व को लेकर अमेरिका ने ईराक पर आक्रमण किया, जिसने ईराक को लगभग तबाह कर दिया। चीन और रूस में समय–समय पर साम्यवादी तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र समर्थकों पर भारी अत्याचार किये गये। चीन के त्येनमिन चौक पर लाखों युवा लोकतंत्र समर्थकों पर गोलियां बरसाई गईं। दक्षिण अफ्रीका में लम्बे संघर्ष के बाद लोकतंत्र का उदय हुआ, वहाँ के मूल निवासियों को रंगभेद के कारण अनेक अत्याचार सहने पड़े। कश्मीर को लेकर भारत–पाक के बीच अनेक युद्ध हुए जिनमें दोनों देशों को जन, धन की भारी हानि उठानी पड़ी तथा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हजारों निर्दोष जाने गईं। अफगानिस्तान में लम्बे समय तक गृह युद्ध की स्थिति रही। रूस और अमेरिका के दखल ने वहाँ की स्थिति को भयावह बनाया। बाद में अलकायदा (ओसामा बिन लादेन) का उदय, वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर की घटना और अलकायदा पर अमेरिकी हमला आदि आतंक और युद्ध के विमर्श चर्चा में प्रमुख रहे। श्रीलंका ने गृह युद्ध की विभीषिका को लम्बे समय तक झेला। इन विभीषिकाओं के अनेक संदर्भों ने जिस समकालीन कवि को सबसे ज्यादा उद्वेलित किया उस कवि श्रीकांत वर्मा की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं–

फौज के अंधेरे में
लुटी हुई
बीसवीं शताब्दी का
सिर
गिरता है
चेकोस्लोवाकिया में
धड़
वियतनाम में
शेष ढाका, चटगांव में
शुक्रिया चंगेज खाँ
तुम्ही को पाया है हर मोड़ पर।''[1]

एक ओर आज विश्व का कोई भी देश आतंकवादी घटनाओं से निरापद नहीं है तो दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा तानाशाही शक्तियों से है। ये शक्तियां कहीं धर्म के नाम पर, कहीं परम्परा के नाम पर तो कहीं झूठी शान या प्रतिष्ठा के नाम पर लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों का गला घोंटने में लगी हुई हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं–

.....पूछता हूँ
जिसके पैर में तुम जूते नहीं दे सकते
उसके हाथ में तुम्हें
बन्दूकें देने का क्या अधिकार है?''[2]

एक ओर सम्पूर्ण विश्व ज्ञान–विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, आदि के नवीन आयामों से अपने को आप्लावित करता जा रहा है, तो दूसरी ओर मनुष्य की आदिम अशिव वृत्तियां उसे आज भी स्वस्थ और सुखद जीवन जीने नहीं दे रही हैं। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि आदिम युग से लेकर आज तक मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। युद्ध किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए सबसे बड़ी विभीषिका होती है किन्तु अपने राजनैतिक अस्तित्व की सुरक्षा एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व या कर्तव्य भी होता है पर विश्व के अधिकांश युद्धों का लक्ष्य था, लालच। दूसरों के राज्य हड़पने का लालच, राजकोष लूटने का लालच, सुन्दर राजकुमारियों से विवाह करने का लालच और अनेक राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाने का लालच। इतिहास में अपने निहित स्वार्थ के लिए अथवा अहं की तुष्टि के लिए अपनी सम्पूर्ण प्रजा और सेना को दांव पर लगाने वाले सनकी राजाओं के युद्ध विवरण भी कम नहीं हैं। आज राजतंत्र नहीं है और लगभग विश्व के हर देश में लोकतंत्र विद्यमान है, बावजूद इसके अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अहं के चलते अपने देश को युद्ध की आग में झोंकने का कार्य किया है। जबकि आतंकवादी शक्तियों का सबसे बड़ा औजार उनका पंथ है, जिसे वे जेहाद के रूप में जब तब इस्तेमाल करते रहते हैं। वरिष्ठ कवि रामदरश मिश्र के शब्दों में–

और हर सुबह लाकर पटक देती है
वियतनाम का एक युद्ध
एक नीग्रो की लाश के नीचे दबा हुआ संगीत
दक्षिण अफ्रीका की काली–काली नदियों में
घुलता हुआ गोरा–गोरा जहर
बसन्त की हवाओं में पीठ पर लदा हुआ रेगिस्तान

और झुलसती हुई छोटी–छोटी पत्तियां

लाल–लाल पेड़ों में पलते हुए बारूद के गुब्बारे।[3]

युद्ध और आतंकवाद पूरी मानव जाति के माथे पर कलंक है। युद्ध और आतंक का शिकार सबसे ज्यादा निर्धन, निर्दोष, निरीह मनुष्य और खासकर महिलाएं, बच्चे ही होते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पंक्तियां द्रष्टव्य हैं–

छितरा गई लिबर्टी की प्रतिमा खण्ड–खण्ड

ढाका में, वियतनाम में

सारी जवान लड़कियां बन्द फौजी बैरकों में

कैसे गाऊं पद्मा किनारे

कौन सा गीत।''[4]

समकालीन कवियों ने विगत में हुए अनेक युद्धों के भयानक हादसों पर गम्भीर चिन्तन किया है। इन कवियों की रचनाओं में युद्ध और शान्ति, न्याय और अन्याय, बर्बरता, जिजीविषा, हत्या, बलात्कार, लूटपाट सहित युद्ध कौशल आदि के वर्णन भरे पड़े हैं। श्रीकांत वर्मा की कृति 'जलसाघर' की कतिपय पंक्तियां कितना कुछ कह जाती हैं –

''इसके पहले मैं चीख कर कहता

'हिरोशिमा अमर है' मैं मारा जा चुका था

दबी की दबी रह गई चीख।''

x x x x

''छीन–झपट–दमन, युद्ध चूसकर

मारी गई जनता के

रक्त को बर्बर उधर देखो वह चला जा रहा है।''

x x x x

मोहन जोदड़ो से अब तक का

सिलसिला है

युद्ध की एक अटूट श्रृंखला है।

x x x x

मोरपंख की तरह किताबों के बीच रखी हुई है

युद्ध दस्तक दे रहा है

पृथ्वी की एक–एक सड़क पर

भाग रहा है मनुष्य
युद्ध पीछा कर रहा है।''[5]

आतंकवाद के खिलाफ भी इन कवियों ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी कविताएं लिखी हैं। देश की लहुलुहान स्थिति के स्वयं भुक्तभोगी, आतंकवाद के शिकार तथा कश्मीर से निर्वासित जीवन बिता रहे कवि अग्निशेखर के शब्दों में–

''दोस्तो मुझे दरकार है
कीड़े मारने की दवा
अब देखा नहीं जाता कमरे में टंगा
देश का नक्शा छलनी हो रहा है।''[6]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समकालीन कवियों ने युद्ध एवं आतंकवाद की विभीषिका को न सिर्फ भारतीय जनमानस के परिप्रेक्ष्य में वरन् वैश्विक परिदृश्य में रेखांकित करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया है।

संदर्भ

1. जलसाघर– श्रीकान्त वर्मा, पृ0 27
2. कविताएं–दो– सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पृ0 61
3. कन्धे पर सूरज– रामदरश मिश्र, पृ0 56
4. साथ चलते हुए– विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पृ0 42
5. जलसाघर– श्रीकान्त वर्मा, पृ0 68 से 71 तक
6. किसी भी समय– अग्निशेखर, पृ0 48

अपने लक्ष्य के सामने और सब बातों को भूल जाना ही मन की एकाग्रता है।

नेपाल में आई0एस0आई0 की भूमिका और भारतीय सुरक्षा

डॉ0 दीर्घपाल सिंह भण्डारी
विभागाध्यक्ष,
सैन्य विज्ञान विभाग
रा0 स्नात0 महाविद्यालय,
नई टिहरी,(उत्तराखण्ड)

डॉ0 दीपेन्द्र सिंह तोपवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर
सैन्य विज्ञान विभाग
रा0 स्नात0 महाविद्यालय,
नई टिहरी,(उत्तराखण्ड)

नेपाल हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलान पर बसा हुआ है जिसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत है। भारत, नेपाल का निकटतम पड़ोसी राष्ट्र है जिसकी भौगोलिक सीमायें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निकटतम पड़ोसी होने के कारण नेपाल का भारत के लिए स्त्रातेजिक महत्व रखना स्वाभाविक है। भारत के स्वतन्त्र होने पर नयी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसने नेपाल की स्थिति को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भले ही नेपाल अपनी भौगोलिक अवस्थिति, धर्म और आर्थिक प्रणाली के कारण सदैव भारत से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा रहा है। वैसे भी देखा जाय तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जिनमें जाति, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सम्बन्धों में दो देश आपस में इस अभियोज्य प्रकार से बधे हुए हैं, जैसा कि महाराजा पृथ्वीनारायण शाह, जिन्हे नेपाल का जनक माना जाता है[1] ने 1742 ई0 में कहा था कि नेपाल, भारत और चीन दो बड़े चट्टानों के बीचएक तरूल की तरह है और हमें अपने इन दोनो बड़े पड़ोसियों से मधुर सम्बन्ध बनाए रखना होगा। नेपाल स्थलवध होने के कारण यह नेपाल की भू–राजनीतिक आवश्यकता है कि वह भारत से सम्बन्ध बनाए रखे, क्योंकि नेपाल का भूगोल उसे भारत के साथ सम्बन्ध को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। दूसरी ओर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेपाल के महत्व को समझता है और नेपाल का चीन की ओर झुकाव को कम करने के लिए वह हर सम्भव प्रयास करता है। इतना ही नहीं नेपाल को सभी प्रकार के साजो–सामान की पूर्ति के साथ–साथ वहां की राजनीतिक और कूटनीतिक हालातों पर भी अपनी पैनी नजर रखता है, क्योंकि वहां राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उथल–पुथल का भारत की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

भारत की चिन्ता आखिर क्या ?

वर्तमान में भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा सुरक्षा से सम्बन्धित है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 पिछले काफी दिनों से नेपाल की भूमि का प्रयोग अपने भारत विरोधी कार्यों के लिए कर रही है। नेपाल के साथ भारत की 1751 किमी0 लम्बी सीमा रेखा है जिसमें 851 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड तथा 391

किमी पूर्वांचल का हिस्सा है जो अति संवदेनशील माना जाता है।[2] भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़, चम्पावत, जिला उधमसिंह नगर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, व जिला महाराजगंज बिहार के पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, मधुबनी सुपौल, अररिया व जिला किशनगंज, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग तथा सिक्किम के उत्तर जिला मंगर और पश्चिम जिला ग्वालशिंग नेपाल सीमा पर स्थित है। इस सीमा से नेपाल में प्रवेश के चार अधिकृत रास्ते हैं जहां पुलिस चौकियां और सुरक्षा बलों की जांच पड़ताल का प्रबन्ध है, जबकि पन्द्रह ऐसे अनाधिकृत रास्ते हैं जहां से नेपाल में बेखौफ आवागमन जारी है।[3] भारत और नेपाल के बीच खटास पैदा करने के लिए पाक खुफिया एजेंसी आई0एस0आई0 की लगातार बढ़ती कोशिश के चलते भारत में आतंकवाद भी फल–फूल रहा है।

नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई0एस0आई0 की घुसपैठ की शुरूआत 1996 ई0 से मानी जा सकती है जब तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पाकिस्तान की यात्रा पर गये। किसी भी नेपाली प्रधानमंत्री की वह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। यही नहीं तत्कालीन समय में ही एक उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन भी गया। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूख अहमद लेघारी और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों से तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री श्री देउबा की बंद कमरे में अहम बातचीत हुई। फलस्वरूप आई0एस0आई0 एजेंटों ने अपने जाल फैलाने शुरू किये और वर्तमान में नेपाल के भारत से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों के चप्पे–चप्पे पर पाकिस्तान जासूस भारत व नेपाल को अन्दर से कमजोर करने का अभियान चला रहे हैं। भारतीय सुरक्षा सूत्रों के अनुसार प्रदेश के सोनौली, महराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़ और बिहार के रक्सौल, मधुबनी वाल्मीकी नगर, पश्चिमी चंपारण, इलाकों में जगह–जगह आई0एस0आई0 के ठिकाने बने हुए हैं।[4] यहां पर दिलचस्प पहलू ही कहा जा सकता है, कि एक महिला पत्रकार रूचि सिंह को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा जो कुछ सैनिक अधिकारियों के जरिए आई0एस0आई0 के लिए नेपाल गुप्त सूचनाएं भेजती थी।[5]

स्मरणीय है कि दिसम्बर 1999 ई0 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपहरण किया गया। इस बात के पक्के सबूत तब मिले थे कि जब नेपाली सुरक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से पाकिस्तान व अफगानी उग्रवादियों ने इण्डियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया। यहां इस ओर ध्यान देना होगा कि भारत को अपने यात्रियों की जान बचाने के लिए जेल में बन्द पाकिस्तानी कट्रपंथी मौलाना मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा जो इन दिनों फिर से जेहादियों का नया जत्था कश्मीर भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने नेपाल जाने वाले इंडियन एयरलांइस की उडानों पर रोक लगा दी थी। विमान अपहरण के बाद नेपाली प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला ने भारत और नेपाल के बीच सद्भावना और विश्वास फिर से कायम करने तथा आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से एक सप्ताह (31 जुलाई से 6 अगस्त 2000) के लिए भारत आये लेकिन अपनी भारत यात्रा के बाद जैसे ही कोईराला नेपाल पहुँचे

तो हिन्दुस्तान के अन्दर जाली नोटों का बाजार गरमाया और जगह–जगह जाली नोट पकड में आने लगे। दिलचस्प बात यह है कि जाली नोट पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में आने शुरू हो गये। पाकिस्तान ने एक बार फिर नेपाल भूमि का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया, इससे दोनों राष्ट्रों के बीच दूरी गहराती गई। और पाकिस्तान बराबर नेपाल की आड़ में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा करने की पूरी कोशिश करता रहा।

भारत और नेपाल के बीच दरार पैदा करने के लिए पाक खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 की लगातार बढ़ती कोशिशों का एक उदाहरण भारतीय हिन्दी फिल्मी जगत के बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन का मामला भी है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका का पता बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने पर चलता है। क्योंकि बडे ही नियोजित ढंग से रितिक रोशन द्वारा नेपाल के बारे में की गई कथित टिप्पणी में कहा गया कि रितिक रोशन ने एक टी0वी इंटरव्यू में कहा कि वे नेपाल और वहां के लोगों से नफरत करते हैं।[6] इस टिप्पणी को मुद्दा बनाकर नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को सुलगाने की कोशिश ऐसे समय में की गयी जब भारत नेपाल सम्बन्ध सुधरने के आसार बन रहे थे। ऐसे समय में नेपाल के अन्दर भारत विरोधी भावनायें भड़कने लगी। यहां तक कि वहां की छात्र राजनीति ने जमकर भारत विरोधी प्रचार–प्रसार प्रारम्भ किया। नेपाल में भारतीय टी0वी0 प्रसारण को हटा दिया गया तथा नेपाल में प्रवासी भारतीयों को भी वहां खतरा महसूस होने लगा। स्मरणीय है कि जिस टी0वी0 यूनिट ने पहली बार रितिक का मामला उछाला उसका संचालक आई0एस0आई0 का ही आदमी था। पांच दिनों तक लगातार भारत विरोधी दंगों के दौरान पूरे नेपाल में भारतीय टेलीविजन का प्रसारण बंद रहा। इस कारण रितिक रोशन द्वारा किया गया खण्डन वहां के दर्शकों तक नहीं पहुंच पाया। इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत–विरोधी भावनायें भड़काने में लिप्त लोगों और दलों की पहुंच तथा उनका प्रभाव केवल निचले स्तर के प्रशासन, समाचार पत्रों, प्रचार–प्रसार माध्यमों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि उनकी पैठ राजदरबार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों तक भी है। बड़े–बड़े पांचसितारा होटलों के मालिक आदि के माध्यम से राजदरबार के उच्च पदस्थ व्यक्तियों का दाउद इब्राहीम जैसों से पहुंच बताई जाती है।[7]

भारत–नेपाल के मध्य आई0एस0आई0 की भूमिका :

उल्लेखनीय है कि इण्टर सर्विसेज इटेंलीजेंस (आई0एस0आई0) भारत और नेपाल के मध्य कटुता की दीवार खड़ी करने के लिए लगातार सक्रिय रहती हैं। बिहार के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में बैठे चीन तथा पाकिस्तान के दूतावासों के अधिकारी भारत में नक्सलवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। समाचार पत्र के माध्यम से यह भी बताया गया कि काठमांडू की जामा मस्जिद में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें चीनी अधिकारियों के अतिरिक्त पाकिस्तानी दूतावास के एक उच्चाधिकारी मुहम्मद शाहिद रहमान, मस्जिद इमान मौलाना, जमाल खान, पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई0एस0आई0 के सहयोग से चलने वाले मीडिया ग्रुप स्पेस टाइम्स के प्रमुख जमील शाह

लश्कर–ए–तोइबा के प्रतिनिधि मौलाना जमाल गाजी के अतिरिक्त बिहार में सक्रिय नक्सलवादी संगठन पीपुल्सवारग्रुप के विनोद झा और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के नागेन्द्र झा व पश्चिमी बंगाल के आशीष मुखर्जी आदि ने भी भाग लिया ।[8] कहा जाता है कि इस बैठक में नक्सलवादियों और भारत में सक्रिय इस्लामी जेहादी गुटों के बीच तालमेल बढ़ाने पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया तथा यह भी तय हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोही संगठनों को आश्वासित किया गया कि चीनी तथा पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा थाईलैण्ड से होकर बांग्लादेश के रास्ते आधुनिक हथियारों की सप्लाई की जायेगी।

सीमा पर बाहरी देशों की निगरानी :

ज्ञातव्य है कि भारत नेपाल सीमा पर मदरसों और मस्जिद के निर्माण में पाकिस्तान और बांग्लादेश सीधे तौर पर सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सउदी अरब, ईरान तथा कुवैत भी इस मामले में आर्थिक मददगार साबित हो रहे है, यही वजह है कि इन देशों ने अपने राष्ट्रीय बैंको को भी मदरसों के लिए आर्थिक सहायता देने की बात की है। बैकों के जरिए इन मदरसों को वित्तीय सहायता पहुंचाने में साउदी अरब का ''इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक'' और पाकिस्तान का ''हबीब बैंक'' ज्यादा सक्रिय है। वैसे भी पाकिस्तान का हबीब बैंक नेपाल के हिमालयन बैंक का साझेदार बन गया है। यद्यपि इन दोनों देशों ने इसे एक व्यावसायिक करार माना, परन्तु भारत इस करार को अन्य दृष्टि से देखता है। नेपाल बिहार सीमा के कई गांवों में जो मदरसे बन रहे हैं। उनमें बिहार के कई सांसदों और विधायकों का सीधा हाथ भी माना जा रहा है, जो नेपाल के जरिए आई0एस0आई0 इन मदरसों को भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर मदरसों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। आई0एस0आई0 ने राज्य के 9 जनपदों की 800 किमी लम्बी सीमा पर भारी संख्या में मदरसों का निर्माण करवाया जो देश मे घृणा और आतंक फैलाने का कार्य कर रहे है। वर्तमान में राज्य के इन सीमान्त जनपदों में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि 32.76 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है कुछ जिलों मे मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 50 प्रतिशत से भी अधिक है। भारत–नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में 343 मस्जिदें, 330 मदरसे और 17 मस्जिद–मदरसे स्थापित हो चुके हैं, जबकि नेपाल क्षेत्र में 283 मस्जिदें, 181 मदरसें और 8 मस्जिद मदरसे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है[9] गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार मदरसों के लिए जो धन आ रहा है वह दान के रूप में कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से निर्यात होने वाले सामानों के बदले में आ रहा है। खाड़ी देश के शेख और आतंकी संगठन 50 रू0 का सामान 500 रूपये में खरीदकर इन मदरसों की सहायता करते हैं। इन मदरसों का काम केवल तालीम देना नहीं बल्कि मदरसें जेहाद पैदा कर आतंकवादी बनाने की पाठशाला बन कर रह गई है। जो आई0 एस0 आई0 की रीढ भी बनती जा रही है। इसी सन्दर्भ में पाकिस्तान की लाल मस्जिद जीता जागता उदाहरण है, आई0एस0आई0 को मालूम है कि रोजगार की कमी और प्रशासन की उदासीनता के चलते आतंकवाद एक आकर्षक विकल्प बन चुका है, इसीलिए युवाओं की भर्ती के लिए अब वह स्कूलों, कॉलेजों व मदरसों में अपनी पैठ बनाने लगी है।

स्मरणीय है कि पाकिस्तान सरकार ने इण्टर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई0एस0आई0) को पूरी छूट प्रदान की है कि वह भारत के अन्दर दंगा कराने अर्थव्यवस्था कमजोर करने और उग्रवादी तत्वों की अलगाववादी भावना भड़काने में कोई कमी न रखे। इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए मस्जिद एवं मदरसें सबसे सुरक्षित स्थान होते हैं। भारतीय खुफिया एजेन्सियों का मानना है कि भारतीय सीमा पर मस्जिदों एवं मदरसों के निर्माण के पीछे पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई0 एस0 आई0 का हाथ है। पिछले एक दशक में नेपाल में मुसलमानों की जनसंख्या तीन गुनी बढकर बीस लाख से अधिक हो गई है। यह जनसंख्या क्यों और कैसे बढ़ी इसका जवाब नेपाल सरकार के पास भी नहीं है। 13 जनवरी 2002 को ''एशियन ऐज'' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आई0 एस0 आई0 नेपाल में इस्लामिक उग्रपंथी संगठनों की मदद कर रहा है आज भारत में उत्पात मचा रहे अनेक नक्सलवादी संगठन अलकायदा, लिट्टे और आई0एस0आई0 का माओवादियों से सम्बन्ध जगजाहिर है। इसके साथ ही आई0 एस0 आई0 का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के बिहार और उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी कुछ राजनीतिज्ञों, अलगावादी संगठनों तथा अपराधी गिरोहों से भी है, जिनके सहयोग से अन्य सामान के साथ–साथ हथियारों की तश्करी के अलावा आई0 ए0 आई0 को बल मिल रहा है।

दक्षिण एशिया के लिए नेपाल का महत्व :–

नेपाल दुनिया के अल्पविकसित देशों में से एक है। 141577 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला नेपाल दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक होने के बावजूद भी दक्षिण एशिया में इसका भू–राजनीतिक महत्व है क्योंकि इसकी सीमाएँ एशिया के दो सबसे बडे राष्ट्र चीन और भारत के साथ लगती है। चीन के साथ इसकी लगभग 1236 किमी तथा भारत के साथ 1751 किमी0 लम्बी सीमा रेखा है यही वजह है कि नेपाल, चीन एवं भारत दोनों के मध्य अपना एक विशेष स्थान रखता है। यद्यपि आज भी नेपाल में 53 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से 2008 की अवधि का वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्लोबल बूम ईयर माना जाता है। क्योंकि उस दौरान विकासशील देशों की औसत आर्थिक विकास दर सात फीसदी और यहां तक कि सब सहारा अफ्रीकी देशों की विकास दर 6 फीसदी रही जबकि इससे पहले के दो दशकों में इन देशों की विकास दर 2.4 फीसदी थी।[10] ग्लोबल बूम ईयर के दौरान इन देशों की आर्थिक विकास दर में गुणात्मक बढोत्तरी हुई लेकिन इस दौरान नेपाल की विकास दर कम रह गयी। वर्ष 2003 सें 2008 के दौरान नेपाल दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जिसकी आर्थिक विकास दर मे गिरावट दर्ज की गयी थी। इसकी वजह राजनीतिक अस्थिरता है जिससे उद्योग, व्यापार आदि में गिरावट आई लेकिन नेपाल की इस आर्थिक दुर्दशा की एक बड़ी वजह कृषि क्षेत्र में उसकी बदहाली भी रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था कृषि पर बेहतर निर्भर है। हाल के वर्षो में वहां कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहद चिंताजनक रहीं है। वर्ष 2007–08 के दौरान सरकार का अनुमान था कि कृषि उत्पादन में 3.3 फीसदी बढोतरी होगी लेकिन यह बढोतरी महज 1.1 फीसदी ही रही है। अमेरिका की

प्रतिष्ठित फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में 177 नाकारा देशों की सूची में नेपाल 25वें पायदान पर है, इस सूची में सोमालिया सबसे उपर है और पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। इस सूची में भारत का 87वां स्थान है।[11] जहां तक नेपाल की बात है तो पिछले एक दशक से नेपाल की राजनीति काफी गरम और अस्थिर रही है। आज भी नेपाल में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान की आई0 एस0 आई0 उठा रही है। पाकिस्तान जहां एक ओर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को हवा दे रहा है वहीं दूसरी ओर नेपाल में आई0 एस0 आई0 को पूरी मदद प्रदान कर रहा है। भारत के सामने इस बात की चिन्ता है कि कहीं आई0 एस0 आई0 नेपाल की गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी का फायदा उठाकर अपने माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों, विशेषकर माओवादियों को जिनकों की अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है को भारत विरोधी कार्यवाहियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पाकिस्तानी आई0 एस0 आई0 जिस तरह विश्व में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। तथा नेपाल एवं बांग्लादेश से खुली चुनौती भारत को दे रही है यह चुनौती केवल आई0 एस0 आई0 द्वारा बाह्य देश से नहीं दे रही है बल्कि हमारे देश में भी उसने गहरी जडे जमा रखी है जिसमें नक्सलियों के अलावा कई भारतीय मुस्लिम संगठनों से इनके तार जुडे हुए हैं। नेपाल में यदि आई0 एस0 आई0 का अड्डा बना रहा तो भारती सुरक्षा पूर्ण रूप से खतरे में पड सकती है। ऐसे में नेपाल को अपनी भूमि पर आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उसे अपनी भूमि से खदेड़ कर नेपाल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि नेपाल कभी भी ऐसी आन्तरिक और बाह्य नीतियां अपना सकता है जो भारत की सुरक्षा हितों के लिए घातक हो सकता है।

सन्दर्भ

1. इण्डियन जनरल ऑफ नेपालीज स्टडीज, वॉल्यूम 3, 1992 पेज 32.
2. सुशीला त्यागी इण्डोनेपालीज रिलेशन पेज 18.
3. दैनिक जागरण 7 मार्च 2001.
4. इण्डियन जनरल ऑफ नेपालीज स्टडीज, 2009 पेज 27.
5. रक्षार्थ जून 2003 पेज 83.
6. गौरी शंकर राजहंस – हिन्दुस्तान, 16 दिसम्बर 2001.
7. रक्षा अनुसंधान 26 जनवरी 2010 पेज 35.
8. .....वही.....
9. सम्पूर्ण समाचार पाक्षिक प्रथम प्रवक्ता 1 मार्च 2002 पेज 11.
10. कूमार विजय– अमर उजाला 19 जुलाई 2010.
11. .....वही..... ।

भूमण्डलीकरण तथा भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ

–डॉ0 ममता दीक्षित
असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर ग्रेड)
शिक्षाशास्त्र विभाग
महिला महाविद्यालय, कानपुर

सम्पूर्ण पृथ्वी को स्थलमण्डल, जलमण्डल एवं वायुमण्डल में विभक्त कर सकते हैं। स्थलमण्डल को ही भूमण्डल कहा जाता है और इसी से भूमण्डलीकरण बना है जिसे अंग्रेजी में 'ग्लोबलाइजेशन' कहते हैं। यद्यपि हिन्दी के भूमण्डलीकरण में जलमण्डल एवं वायुमण्डल सम्मिलित नहीं है तथापि अंग्रेजी का ग्लोबलाइजेशन इन्हें सम्मिलित कर लेता है क्योंकि ग्लोब सम्पूर्ण पृथ्वी का प्रतीक है। मेरे मत में इन दोनो में अर्थ वैभिन्य है लेकिन इनकी भावना समान है। भूमण्डलीकरण की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है – ''भूमण्डलीकरण एक सापेक्ष तथा औपचारिक शब्द है जो प्रचलित दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रगति एवं उपलब्धियों के पुंज को मानव एवं उसके सहजीवियों के लिए सुलभ कराने हेतु कृत संकल्पित है।''

शिक्षा और भूमण्डलीकरण दोनों व्यापक आधार वाले शब्द हैं जिनकी सापेक्ष तुलना कर पाना कठिन है। ''सम्पूर्ण पृथ्वी पर मानवजाति की समस्त उपलब्धियाँ शिक्षा का प्रसाद है, जिनका प्रसार उत्तम भूमण्डलीकरण का आधार है'' शैक्षिक भूमण्डलीकरण वर्तमान अथवा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित है। स्पष्टतः शिक्षा और भूमण्डलीकरण सहजीवी हे और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा को वैश्विक विकास का साधन बनाने के लिए राष्ट्र की प्राथमिकताओं को तय किया जाना आवश्यक है, क्योंकि विकसित, विकासशील तथा अविकसित देशों की प्राथमिकता में अन्तर होता है परन्तु निर्विवाद रूप से कहा जाये तो शिक्षा के द्वारा प्रेरित एवं प्राप्त विकास सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। शिक्षा और भूमण्डलीकरण मिलकर वैश्विक विकास को जन्म देते हैं।

आज जिस शिक्षा की बात की जाती है वह विज्ञान तथा वास्तविकताओं के अधिक निकट है। यह अनुभव एवं सूचनाओं का बन्डल बनती जा रही है। जो भूमण्डलीकरण की देन है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में विशिष्ट ज्ञान एवं तथ्य ही वैश्विक प्रतियोगता में बने रह सकते हैं। यदि एक राष्ट्र द्वारा विकसित तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी दूसरे राष्ट्र की तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी से श्रेष्ठ हैं, तभी उसकी अन्य राष्ट्रों, में माँग होगी अन्यथा उसका भूमण्डलीकरण संभव नहीं हो सकेगा।

1991 से ही प्रमुख रूप से देश में भूमण्डलीकरण की नीतियां लागू की गयी हैं। इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप आज स्थितियां ऐसी हैं कि देश के हर तबके में यह महसूस किया जा रहा है कि हमारी उच्च शिक्षा हमारी आकांक्षा के अनुरूप नहीं है।

भारत में उच्च शिक्षा अंगद के पैर की तरह जम गयी है – ठोस, भारी और अचल। उसका समसामयिक जीवन के बदले हुए संदर्भों से बहुत कम सरोकार है। वह आज आने वाले कल की चुनौतियां स्वीकार नहीं करती, बल्कि अपने ढांचे को सुरक्षित रखने में तल्लीन है। यह जिस रोग से ग्रस्त है उसकी छानबीन अनेक आयोगों, समितियों, कार्य समूहों और अध्ययन दलों ने की है और उन्होंने कई भारी भरकम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। पर अमल नाममात्र को हुआ। यदि आज किसी विश्वविद्यालय में वर्ष भर में अस्सी या नब्बे दिन शांतिपूर्वक पढ़ाई हो जाए तो उसे भाग्यशाली समझना चाहिए। इस अल्पावधि में कुछ नहीं होता। इस बात का संगठित प्रयास किया जाताहै कि श्रांत–क्लांत विद्यार्थियों केा ज्ञान की पुड़िया दे दी जाए, ताकि वे किसी तरह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। उच्च शिक्षा आज एक अनुष्ठान मात्र बन कर रह गयी जिसका न कोई अर्थ न प्रयोजन।

हमारे विश्वविद्यालयों में अंसतोष इतना व्यापक है और हिंसा के ऐसे आवधिक विस्फोट होते रहते हैं कि हम उन संकटों की ओर ध्यान नहीं दे पाते जो उच्च शिक्षा की आत्मा का हनन कर रहे हैं उदाहरण के लिए लक्ष्यों का ही संकट ले। राष्ट्र निर्माण और विकास में उसकी भूमिका के साथ केवल शाब्दिक खेल किया जा रहा है, और यदि उसे कहीं बढ़ावा मिलता भी है तो दबे स्वर में। यदि हम शिक्षा के लक्ष्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति विकसित कर सकें और उनकी ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक शक्ति जुटा लें, तो हम विश्वास के संकट और सर्वत्र फैल रही विघटनकारी दोषदर्शिता का सामना करने में सफल हो सकेंगे।

प्रासंगिकता के प्रश्न की जितनी सूक्ष्म, जाँच होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और शायद इसी क्षेत्र में यह संकट सबसे अधिक गहरा है। प्रो0 दौलत सिंह कोठारी ने कहा है, ''विज्ञानाश्रित विश्व में किसी भी देश की समस्त विकासात्मक प्रक्रिया, उसके कल्याण प्रगति और सुरक्षा के लिए शिक्षा और अनुसंधान का भारी महत्व होता है'' आज यह समझना आवश्यक है कि संसार कितनी तेजी से बदल रहा है, किन्तु विश्वविद्यालयीन प्रणाली इस प्रकार की समझ विकसित करने में कोई सक्रिय सहयोग नहीं देती। हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य की पुरानी संकल्पनाओं से बंधे रहकर ही काम करते आ रहे हैं। हम यत्र तत्र किए गए कठिन परिश्रम या ठोस उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर रहे। यदि हम शिक्षा की समग्र उपलब्धि की प्रासंगिकता के नाते छान–बीन न करें, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ज्यों–ज्यों हमारा समाज तकनीकी दृष्टि से अधिक जटिल बनता जाएगा, हमारी प्रशिक्षित जनशक्ति

संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ती जायेंगी और हमें अधिक उच्च शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता होगी, परन्तु हमारी असल आवश्यकता ऐसी प्रशिक्षित योग्यताओं की है जिनमें समस्याओं का समाधान करने की सशक्त क्षमताएँ हों। हमें ऐसे डिग्रीधारी समूहों की जरूरत नहीं है जिनका शिक्षा के एक या अधिक क्षेत्रों से अस्पष्ट और अपर्याप्त परिचय भर हो। उच्च शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को लेकर हमारे यहाँ काफी भ्रान्तियाँ है। उच्च शिक्षा प्राप्ति का ''अधिकार'' जैसी कोई चीज नही है, यह तो एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसे कठोर उपलब्धि–संबंद्ध मानदंड पर पूरा उतरने पर ही अर्जित किया जा सकता है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेना सामान्यतः हमारे देश और विशेषतः हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए हितकर होगा।

हमारी सर्वाधिक स्पष्ट असफलताएँ शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं ने पूर्व स्थापित पद्धति में साहसपूर्ण परिवर्तन किए और उनसे यह आशा की कि वे रूढ़ पद्धतियों पर चल रहे विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्धारक सिद्ध होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये संस्थान भी कष्टग्रस्त हैं और ऐसा लगता है कि वही पुरानी परिपाटी अपनाने की दिशा में अग्रसर हैं जो अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है। स्वायत्त कालेजों के बारे में कई समितियों में चर्चा की गई लेकिन उन पर अमल नाम मात्र को ही हुआ। अब तक बहुत थोड़े कालेजों को यह दर्जा मिला है। पाठ्यचर्चा में नम्यता की आवश्यकता है लेकिन हमारे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एक विशिष्ट पद्धति के बंदी बने हुए हैं, उनमें केवल समिति और रूढ़िगत विकल्प ही सम्भव हैं। सेमेस्टर पद्धति जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली की सभी बुराईयों को दूर करने के लिए रामबाण समझा जाता है, सर्वथा निष्फल सिद्ध हुई हैं। परीक्षा पद्धति में सुधार को लेकर खासी बहसें हुई हैं लेकिन सुधार आज तक नहीं हो पाया। मूल्यों और प्रतिबद्धता जैसे संवेदनशील विषयों पर भी विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है भारत में उच्च शिक्षा के लोकतंत्र, समता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सम्बन्धी मूल्यों को अपनाना और उन्हें आगे बढ़ाना होगा।

इस प्रकार भूमण्डलीकरण के दौर में हमें गम्भीरता से विचार करना है कि उच्च शिक्षा का आयोजन किस तरह किया जाए। हमें उच्च शिक्षा को और अधिक गिरावट से रोकना है, तो उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया का नियोजन करना है जिसके द्वारा नई पीढ़ी में मानवीय विशिष्टताओं का प्रस्फुटन हो, वैज्ञानिक चिंतन प्रणाली का विकास हो तथा प्रबुद्ध वैज्ञानिक, समर्पित नागरिक और संवेदनशील मानव का निर्माण कर सकना शिक्षा की महान उपलब्धि होगी। इस प्रकार उच्च शिक्षा नियोजन में बहुत सारे कारगार तत्व ठोस सार भाग का निर्माण करते दिखायी देते हैं। इनमें प्रमुख है – शैक्षणिक नियोजन, जनशक्ति, नियोजन, शिक्षा का सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रसार, जनचेतना उत्पन्न करे पढ़े लिखे समाज का निर्माण करना, रोजगार की पर्याप्तता, शिक्षकों को उचित सम्मान व मानवीय मूल्यों का विकास, नौकरी को डिग्री से मुक्त करना, प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

व अभिप्रेरणा की जाँच करना, शैक्षणिक प्रणाली का विकेन्द्रीकरण अधिकाधिक कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करना आदि।

अंत में यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की व्यवस्था ने उच्च शिक्षा को जिस स्वरूप में लाने की कोशिश की है, वह अत्यंत ही विचित्र स्थिति पैदा करती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के विकास करने के लिए शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसमें भी बुनियादी और मूल्यपरक शिक्षा का होना नितान्त आवश्यक है। इन अवधारणाओं की स्पष्टता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि शिक्षा भूमण्डलीकरण के तमाम नियमों से बाधित न हो।

संदर्भ

1. Challenges of Education : A Policy Perspectives, Ministry of Education, 1985, New Delhi.
2. Kochhar, S.K. Pivotal Issues in Indian Education, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1981
3. Mohanty, J., Dynamics of Higher Education in India, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1993.
4. Mohanty, J., Modern Trends in Indian Education, Deep and Deep Pyublications, New Delhi. 1989.
5. UGC Annual Report, 2000-2001
6. Philip G Altabach, Higher Education and WTO : Globalization Run Amok, Chronicle of High Education.
7. Open Doors 2004, Report on International Educational Exchange, Institute of International Education.
8. Guy Neave, "The Dark side", Globalization : Threat, Opportunity or Both Report presented to the IAU Administrative Board Meeting at its Mexico City meeting in November, 2001.

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घड़ियाँ आती हैं, जिन पर भाग्य का बनना और बिगड़ना, निर्भर रहता है। यदि मन में जरा भी हिचकिचाता अथवा आलस्य आया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।

धार्मिक हठधर्मिता द्वारा आतंकवाद का पोषण

(भारत की आन्तरिक सुरक्षा के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 (मेजर) इन्द्रजीत सिंह
रीडर एवं अध्यक्ष
सैन्य अध्ययन विभाग
पी.पी.एन. महाविद्यालय, कानपुर

डॉ. कुलदीप भारद्वाज
सैन्य अध्ययन विभाग
पी.पी.एन. महाविद्यालय
कानपुर

स्वहित की कामना प्रत्येक काल में प्रत्येक व्यक्ति की ही नहीं वरन् प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र की कार्यशैली की प्रेरणा स्रोत रही है, यही कारण है कि एक राष्ट्र अपने प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र को सदैव असुरक्षित करने, उसके विकास की गति तथा शान्तिपूर्ण जीवन के आधार को छिन्न–भिन्न करने का प्रयास विभिन्न माध्यमों से करता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र के अन्दर 'आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति' एक कारगर माध्यम के रूप में अपनायी जा रही है। फलतः विश्व के सभी राष्ट्र न्यूनाधिक्य रूप में आतंकवाद की समस्या से ग्रसित हैं।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए आतंकवाद का दंश झेलना मानो तकदीर ही बन गया है। पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य विश्व में तीव्रगति से बढ़ती हुई भारतीय शक्ति को क्षीण करना ही है, ताकि वह अपना सम्पूर्ण ध्यान विकास की तरफ न लगा सके और अपने आपसी संघर्षों से ही जूझता रहे। जहाँ विश्व के अधिकाशं राष्ट्र आतंकवाद की गतिशीलता के कारण भयग्रस्त है, वही भारत भी इससे अछूता नही है। ''भारत ने आतंकवाद के कारण वाह्य सुरक्षा की ही चिन्ता नही की है, बल्कि अपने बहुआयामी चरित्र के कारण उसको सबसे अधिक चिन्ता आन्तरिक सुरक्षा की है।''[1] आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण ही भारत को अपनी आन्तरिक सुरक्षा के लिए 'धार्मिक हठधर्मिता' की प्रबल चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहता है, जिसके कारण भारत की आन्तरिक सामाजिक समरसता खतरे में पड़ गयी हैं जो भारतीय आन्तरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है।

आतंकवाद क्या है? इस पर प्रकाश डालना यहाँ समीचीन प्रतीत होता है। आतंकवाद कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है, यह एक साधन है, जिसमें दिखाने के लिये किसी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन की मनोवृत्ति का प्रसार तथा प्रचार किया जाता है। यह एक हिंसक नीति है, जिसमें अव्याख्येय हिंसा के माध्यम से समाज में आतंक फैलाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनय की शब्दावली में आतंकवाद सम्भवतः वह नवीन शब्द है जिसने विश्व

धरातल पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। विश्व भर के बहुतायत राष्ट्रों के नीति नियामक और राजनीतिक व्यक्तित्व आये दिन आतंकवादी खतरे की ओर तथा इसके विरूद्ध कठोरतम कदम उठाने की चर्चा करते रहते हैं फिर भी आतंकवाद की सर्वव्यापी और सर्वस्वीकृत परिभाषा आज तक नहीं ढूँढी जा सकी, क्योंकि विश्लेषक इस विषय में अपनी अवधारणा में अपने मूल्यों एवं हितों से प्रभावित होते हैं।

विषय के विश्लेषकों और अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों द्वारा आतंकवाद की अवधारणा को व्याख्यायित करने के जो प्रयास किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं – चैम्बर्स के अनुसार – ''आतंकवाद भय का एक संगठित तरीका है।'' प्रो. आर.पी. साहनी के अनुसार – ''आतंकवाद वह हिंसापूर्ण नाटक है, जो ऐसी मांग या उद्देश्य के प्रति लोगों या जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिये रचा जाता है जो पूरे न हो रहे हों अथवा जिन्हें पूरा करने में दिक्कत हो रही हो, इसका उद्देश्य प्रचार करना ही होता है।'' आक्सफोर्ड के अनुसार – ''राजनैतिक उद्देश्य के लिये हिंसा व भय का प्रयोग ही आतंकवाद है। निष्कर्ष यह है कि आतंकवाद को चाहे जिन शब्दों की सीमाओं में बांध कर परिभाषित किया जाये परन्तु इसके मूल में भय, असुरक्षा तथा विनाश ही निहित है। आतंकवाद के लक्ष्य के अन्तर्गत सत्ता के उच्च केन्द्र में आसीन शासकों से लेकर जन सामान्य तक होते हैं तथा राष्ट्र की सार्वजनिक सम्पत्ति से लेकर निजी सम्पत्ति तक इसके विनाश की बलिवेदी पर भेंट चढ़ती है। निःसन्देह इससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के साथ–साथ उसकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। आज विश्व के बहुत से देशों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले गये हैं ताकि सम्भावित दुश्मन से एक कदम आगे रहा जाय। दुर्भाग्य से इस देश में यह सोच अभी भी विकसित होनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा वर्दीधारी सैनिकों और गैर–सैनिकों की कोई सामान्य सी नौकरशाही प्रबन्ध की क्रिया नहीं है, बल्कि आज इसके लिये उच्चस्तरीय बुद्धिजीवी योगदान की भी जरूरत है।''[2]

यह सर्वविदित है कि मानव–कल्याण शांति और सद्भाव में ही निहित है। यदि इन भावनाओं का नाश और अनादर कर हम विपरीत दिशा में बढ़ेंगे तो मानव–कल्याण की बजाय विनाश होगा। किसी भी धर्म या पंथ से संबंधित ज्ञानी, संत, ऋषि, सूफी, धर्मगुरू आदि हों, उन्होंने ईश्वरीय संदेश तो दिए पर उसके साथ–साथ मानव कल्याण की भावनाओं को केन्द्र में रखकर सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ भी पढ़ाया। यह सत्य ही है कि, ''विभिन्न धर्मों में हिंसा को अच्छा नहीं माना गया है। अगर कहीं–कहीं हिंसा की वकालत की भी गयी है तो वह बुराई पर अच्छाई को विजय दिलाने हेतु, कमजोर का साथ देने के लिए या फिर धर्म के बचाव के लिए।''[3]

आज सम्पूर्ण विश्व बढती हुई धार्मिक हठधर्मिता की प्रवृत्ति एवं भावनाओं को रोकने के

लिए चिंतित है। जिन धर्मों और पंथों को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए, वहीं धर्म और धर्म के ठेकेदार इस काम में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। यह बड़ा भारी प्रश्न है – आखिर ऐसा क्यों? धर्म को तो रक्षक होना चाहिए, न कि भक्षक। धर्मों की तह में जायें तो वह रक्षक ही हैं, परन्तु कतिपय फिरकापरस्त ताकतों के द्वारा जान–बूझकर ऐसा जामा पहनाया जा रहा है ताकि लोगों में आपस में प्रेम की बजाय घृणा का संचार हो।

आज विभिन्न धर्मों में एक तीखी स्पर्द्धा प्रारम्भ हो चुकी हे, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वे चंद लोग जो अपने को धर्म–विशेष का मसीहा बताकर दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने से कतराते हैं। साथ ही आम नागरिक को गुमराह करते हैं जिनके पास धर्म–पीठों का स्वामित्व है, वो इसे छोड़कर अपनी स्थिति ओर स्थान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, फलतः आम आदमी को बेवकूफ बनाना आवश्यक है।

''आम धर्मावलम्बी और कट्टरपंथी में हम जब तक भेद नहीं कर पाते, तब तक आतंकवाद से धर्म के रिश्तों की व्याख्या मुश्किल है। आम आदमी चाहे वह किसी देश, जाति, धर्म से सम्बन्ध रखता हो और कितना ही आधुनिक, प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच रखता हो, वह किसी ने किसी रूप में ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति को अवश्य स्वीकार करता है। वह अनैतिक और गलत काम से डरता है और मुश्किल समय में उस शक्ति की शरण में जाना चाहता है जिसे उसने कभी नहीं देखा और इन मामलों में वह संवेदनशील होता है। वह मृत्यु और उसके उपरान्त के समय की कल्पना करता है और डरता भी है। अपने से ज्यादा किसी अदृश्य शक्ति को वह स्वीकार करता है तथा अपने–अपने ढंग से उसकी पूजा–अर्चना, नमाज, प्रेयर आदि करता है। आम आदमी का धर्म इन्हीं अदृश्य शक्तियों और मानव–निर्मित विधि–विधानों एवं पूजा–पाठ तक सीमित है। वह पुराने धर्म–ग्रन्थों पर भी अपना विश्वास रखता है।'' [4]

इन सबके विपरीत एक वह वर्ग है जो स्वयं का घोषित किया हुआ (स्वयंभू) धर्मों का संचालक और ठेकेदार है। यह वर्ग पहले बहुसंख्यक वर्ग की तुलना में हर धर्म में अल्पमत में मिल जायेगा पर वह बहुसंख्यक अनुयायियों का मार्गदर्शक होता है। यह वर्ग आम तौर पर आम आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टपंथी होता है। इस वर्ग का व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानता है, दूसरे धर्मों की खामियाँ निकालता है, अपने धर्म के प्रचार के लिए नैतिक–अनैतिक सभी तरीके अपनाता है। यह किसी तंत्र विशेष में विश्वास न कर सारी दुनिया को अपने धार्मिक रंग में देखना चाहता है। राजनैतिक मामले हों या आर्थिक, सामाजिक समस्याएँ हों या धार्मिक वह उनसे अपने आपको जोड़कर जनहित की परवाह किए बगैर धर्म–हित की गुहार लगाता है। जब ऊपर के सभी क्षेत्रों मे वह पिछड़ता हुआ महसूस

करने लगता है तो धर्मयुद्ध और जिहाद की बातें करता है।'' [5]

धार्मिक हठधर्मिता एवं आतंकवाद का सहसम्बन्ध :

पॉल ए. जुर्राडिनी के अनुसार "Fundamentalist terrorism is a by Product of both reaction and resurgence".[6]

धार्मिक हठधर्मिता विश्व समुदाय के लिए कोई नयी बात नहीं है। जिहाद, क्रुसेड्स और धर्मयुद्ध हजारों वर्ष पहले भी लड़े गये। धर्म एक ऐसे चुम्बक की तरह है जिससे कोई भी व्यक्ति चाहे वह पढ़ा–लिखा हो या अनपढ़, गाँव का हो या शहर का, जवान या बूढ़ा, अनायास ही जुड़ जाता है। यह बात एक ऐसा सच है जिसे किसी क्षेत्र या राष्ट्र विशेष की सीमाओं में बाँधना बेमानी होगी।

आज की आतंकवादी हिंसा को जो नये आयाम मिले हैं, वे धार्मिक हठधर्मिता से मिले हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के आतंकवादी का स्वरूप सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक इसी कारण से है। कुछ धर्म ऐसे हैं – जिनका फैलाव सम्पूर्ण विश्व में कायम है। उनके अनुयायियों में कुछ–न–कुछ ऐसा प्रतिशत निकल ही आता है जो सक्रिय रूप से इस तरह के आतंकवाद को मदद भले ही न दे रहा हो, पर उसकी सहानुभूति इसके साथ होती है। ऐसे लोगों को मूल समस्या से कुछ लेना–देना नहीं होता और वह धर्म के नाम पर आतंकवादियों के भ्रामक प्रचार से कुप्रभावित हो जाते हैं और उन्हें हर सम्भव मदद भी देने लगते हैं।

आतंकवाद की उत्पत्ति और इतिहास में ही हम देख चुके हैं कि वास्तव में आतंकवाद पैदा ही धार्मिक कारणों से हुआ है। इतिहास गवाह है कि आतंकवाद की नींव में धर्म की ही ईंटें लगी हैं। आतंकवाद जब अपने बाल रूप में था तो उसका सम्बन्ध धर्म से स्थापित हो चुका था, तब से आज तक कई हजार युद्ध धर्म के नाम पर ही हो चुके हैं। ''कट्टरपंथ ऐसा धार्मिक जुनून है जिसमें सारी तार्किक शक्तियों को ताक में रखकर चंद कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और षडयन्त्र में पिस रहा है। आम आदमी और इसका खामियाजा उठा रही है पूरी मानव जाति।''[7]

भारत में धार्मिक हठधर्मिता का उदय :

संविधान द्वारा भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया हैं धर्म निरपेक्षता का आशय है सर्वधर्म सम्भाव और नागरिकों का सभी धर्मों के प्रति सद्भाव। धर्म निरपेक्षता व्यक्तियों को अपने विश्वास के अनुसार धार्मिक आचरण की स्वतन्त्रता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति न केवल अपने धर्म वरन् अन्य धर्मों के

प्रति भी सम्मान का भाव बनाये रखे, अपना धार्मिक आचरण इस प्रकार सम्पन्न करे कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के धार्मिक आचरण अथवा उनकी धार्मिक मान्यताओं को कोई आघात न पहुँचे। लेकिन पिछले लगभग डेढ़ दशक में भारत के सभी धर्मों ने धर्मनिरपेक्षता के भाव को दरकिनार कर कुछ कम या अधिक मात्रा में धार्मिक हठधर्मिता के भाव को अपना लिया है, अन्तर केवल यह है कि किसी धर्म के अनुयायियों ने कम अंशों में और किसी धर्म के अनुयायियों ने अधिक अंशों में इस भाव को अपनाया हैं ''एक दूसरा अन्तर यह है कि किसी धर्म के अनुयायियों के एक बड़े भाग ने और किसी धर्म के अनुयायियों के छोटे भाग ने हठधर्मिता के भाव को अपनाया है। व्यवहार में देखा गया है कि जो धार्मिक समुदाय जितनी अधिक सीमा तक अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित है, उतनी ही अधिक सीमा तक वह धार्मिक हठधर्मिता से ग्रसित है। हठधर्मिता का यह भाव क्रिया–प्रतिक्रिया के रूप में अपनाया गया है।''[8]

भारत में धार्मिक हठधर्मिता की दिशा में किस धर्म के अनुयायियों ने सबसे पहले यात्रा प्रारम्भ की, कुछ कह पाना कठिन हो जाता है। इस प्रश्न पर वैचारिक मतभेद होना नितान्त होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तथ्य भी सत्य है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी अन्य किसी भी धर्म की तुलना में अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन से अधिक पीड़ित है और मस्जिदों की मीनारों पर से आदेश देने वाले कट्टरपंथी नेतृत्व उन पर हावी है। यह नेतृत्व मुसलमानों को आधुनिकता और उदार धार्मिक भावों को अपनाने से रोकता है। कुरान की आयतें अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन यह कट्टरपंथी नेतृत्व सामान्यतया इस विचार पर बदल देता है कि कुरान की आयतें और 'मदरसी शिक्षा' के दो पाठ ही शिक्षा की इतिश्री हैं। भारत में इस्लामी कट्टरपंथी ऐसे भयंकर खतरे में रूप में उभरे हैं, जो देश के विघटन और अलगाव के लिए लगातार प्रयत्नशील है जिसका फायदा हमारा पड़ोसी राष्ट्र शुरू से उठाता चला आ रहा है।

''भारतीय गृह मंत्रालय की जनवरी 2000 की एक रिपोर्ट – जो यू.एन.आई. के माध्यम से समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुई – के अनुसार पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (I.S.I.) ने भारत में घोर अस्थिरता पैदा करने हेतु आतंकवादी संगठनों एवं भाड़े के आतंकवादियों के ऐसे स्वयंसेवी तैयार किए हैं जो बिना प्रश्न पूछे धर्म के नाम पर आत्मघाती हमला करते हैं जिनका उद्देश्य भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं आन्तरिक सुरक्षा को छिन्न–भिन्न करना ही है।''[9] यह स्पष्ट है कि ज्यों–ज्यों कट्टरपंथी किसी भी प्रांत में बहुसंख्यक होंगे, वे स्वायत्ता अथवा 'आजादी' की मांग करेंगे जैसा कि कश्मीर से स्पष्ट है। ''कट्टरपंथी पिछड़े और गरीब सामाजिक वर्ग में सहज ही इस्लाम का नाम लेकर आतंकियों को प्रविष्ट कराते हैं। गुजरात का गोधरा कांड कुछ ऐसे ही हुआ, जिसमें आतंकवादी स्थानीय

धर्मानुयायियों से जा मिले। इसी प्रकार भारतीय संसद पर हुए हमले में भाग लेने वाले आतंकवादी बाहर के थे, लेकिन दिल्ली के कट्टरपंथियों ने उन्हें अपने घरों में आश्रय दिया। कट्टरपंथी भारत में धार्मिक वैमनस्य का जहर फैला रहे हैं। प्रतिक्रियास्वरूप बहुसंख्यकों के भी कट्टरपंथी संगठन बने हैं और उनके तेवर भी उग्र हुए।''[10]

इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्कीसवीं सदी में भी इस देश की स्थिति यह है कि मुसलमान, हिन्दू, सिक्ख और ईसाई इनमें से कोई भी समुदाय धार्मिक हठधर्मिता से अछूता नहीं रहा है। जिस कारण इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आन्तरिक खतरा सदैव बढ़ता जा रहा है। अतः इस गम्भीर समस्या का समाधान ढूँढ कर उसे खत्म कर काफी हद तक भारत में आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। धार्मिक हठधर्मिता को दूर करने की दिशा में सुझाव निम्नवत् है :–

धार्मिक हठधर्मिता को नियंत्रित करने के प्रभावी सुझाव :–

धार्मिक हठधर्मिता मानवता के लिए गम्भीर अभिशाप है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में तो यह और भी घातक है। धार्मिक हठधर्मिता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं :–

1. देश की सरकार को सदैव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो और उसको मानने मे किसी को कोई कठिनाई न हो।
2. सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न होने पाये, जिसके कारण देश में धार्मिक हठधर्मिता को प्रोत्साहन मिले।
3. सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाय। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भान ही न रहे।
4. भारत में विभिन्न समयों पर अनेक सम्प्रदाय सरकार में अपनी विशेष भागीदारी की माँग करते हैं। सरकार द्वारा इन सबके इस प्रस्ताव को केवल साम्प्रदायिकता के आधार पर ठुकरा देना चाहिए और उन्हें 'एक राष्ट्र' का सबक देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की हरकत से धार्मिक हठधर्मिता को बढ़ावा प्राप्त होगा।
5. देश में सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाय कि सब धर्मों के लोगों को मिल जुलकर रोज सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर सर्वधर्म प्रार्थना कर राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने हेतु वातावरण बनाया जाना चाहिए।

6. शिक्षा में नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस कारण किसी धर्म–विशेष से जुड़ी हुई शिक्षा को अनुचित समझा जा सकता है, लेकिन नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुत अधिक आवश्यक है। अतः इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई भारत के चार प्रमुख सम्प्रदाय हैं। धार्मिक कट्टरता तथा आतंकवाद को देश में नियन्त्रित करने का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि इन सम्प्रदायों में राष्ट्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर उदारवादी नेतृत्व को विकसित किया जाय। सभी स्तरों पर नये नेता युवा व आधुनिक होने चाहिए 'जो कि नयी सोच, नयी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय एकता को नयी दिशा प्रदान करें।

8. हठधर्मिता का एक बहुत प्रमुख कारण दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति है। आवश्कता इस बात की है कि राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनावें और चुनावी राजनीति को एक साधन के रूप में धार्मिक दृष्टिकोण न अपनाया जाये। साथ ही उन राजनीतिक दलों पर तत्काल प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए जो साम्प्रदायिकता एवं कट्टरता की बैसाखी पर अपनी राजनीति कर रहे हैं।

9. धार्मिक हठधर्मिता और आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में प्रेस और जन संचार के अन्य साधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विविध सम्प्रदायों को एक–दूसरे के साथ जोड़ने वाले तत्वों को उभारा जाय। अनेक परिस्थितियों में इतिहास की गलत व्याख्याओं से उपजी संकीर्ण सामूहिक मानसिकता ही धार्मिक हठधर्मिता का रूप ले लेती है। अतः हमें इतिहास की उन कड़ी स्मृतियों को भुला देना होगा, जो विविध सम्प्रदायों को एक–दूसरे का विरोध करने के लिए प्रेरित करती हैं। धार्मिक हठधर्मिता को नियन्त्रित करने का एक प्रभावी उपाय यह भी हो सकता है, कि सभी धर्मों के बीच समानताओं की खोज की जाय।

10. राष्ट्र की विडम्बना यह है कि देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे या समीप रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन देश पूरी शक्ति के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय धार्मिक हठधर्मिता साम्प्रदायिकता और आतंकवाद का शिकार हो रहा है। इन तीनों पर नियन्त्रण का उपाय यही हो सकता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के वांछित मार्ग तैयार करने पर राष्ट्रीय बहस छिड़े जिससे आर्थिक विकास के प्रश्न भारतीय जनमानस के मन–मस्तिष्क पर ऐसे घने रूप में छा जायें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और सम्प्रदाय को लगभग भुला बैठे जिससे राष्ट्र प्रगति के पथ पर शान्तिपूर्ण अग्रसर हो सके।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत की आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद की स्थिति बहुत ही भयावह है, जो मानव–मूल्यों, मानव–अधिकारों और कानून–व्यवस्था के शासन में आस्था रखता है। अतः हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, यहाँ किसी भी धर्म का नागरिक विकास की चरम सीमाओं को छू सकता है, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है और किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। ऐसी धर्मनिपरेक्षता विश्व के शायद ही किसी देश में हो। ये सारी खासियत इसकी विविधतायें ही हैं। अतः आवश्यकता है कि हम धार्मिक हठधर्मिता को त्यागें, विदेशों की नकल न करें और षडयन्त्र के शिकार न बनें। आतंकवाद अपने आप में मानव शांति का दुश्मन है। हम धार्मिक हठधर्मिता को सहयोगी बनाकर ऐसे उन्मादी दानव को शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसका संहार करने के लिए हमें सारी मानव जाति को ही न्योछावर करना पड़ेगा। आज धार्मिक अस्मिता से ज्यादा ऐसी साझी अस्मिता की आवश्यकता है जिसमें मानव–मूल्य, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि हो और बाकी सब बाद में।

सन्दर्भ सूची

1. आतंकवाद और भारतीय समाज, डॉ0 अम्बरीश राय, परयिता, शोधपत्रिका, जुलाई 2008 पृ0–41
2. के. सुब्रमणियम, सैनिक समाचार 1–15 फरवरी 2001, पृ.सं. 10
3. दैनिक जागरण, 1 अगस्त 2007
4. मनोहर लाल बाथम/शिवचरण विश्वकर्मा, आतंकवाद चुनौती और संघर्श, पृ0 सं. 132
5. वही, पृ0 सं. 133
6. वही, पृ.सं. 103
7. अमर उजाला, साप्ताहिकी, धार्मिक आतंकवाद
8. डॉ. पुखराज जैन, राजनीति विज्ञान, पृ.सं. 344
9. वीरेन्द्र कुमार गौड़, विश्व में आतंकवाद, पृ.सं. 220
10. वही, पृ.सं. 293

पाकिस्तान की आन्तरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद

–डॉ0 अशोक कुमार तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
वी.एस.एस.डी. कालेज, कानुपर

भारत–पाकिस्तान दो अलग–अलग विचार धाराओ के राष्ट्र है, एक ओर भारत जहाँ **सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुम्बकम** की आदर्श भावना को अपनाकर धर्म निरपेक्षता की नीति का अनुगामी है वही दूसरी ओर पाकिस्तान मजहबी कट्टरवादी कोख से जन्म लेकर एक इस्लामिक राज्य हैं।

पाकिस्तान विभिन्न समुदायों के करीब 17 करोड़ लोगों का देश है। इसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या पंजाब देश के चार प्रांतों से एक से एक में रहती हैं। इस असंतुलन का क्षेत्रीय रोजगार कोटा व विकास पद्वतियों पर काफी गहरा प्रभाव है और यही कारण है कि पाकिस्तान में सामुदायिक हिसा या संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है।''[1] इस संघर्ष को और गहरा करने का कार्य देश के राजनैतिक तंत्र पर अपना प्रभुत्व रखने वाली सेना कर रही है।

पाकिस्तान मे 95 प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान है। ''1947 ई0 से पहले यहाँ हिन्दू व सिख भी बहुत संख्या में थे लेकिन बँटवारे के समय अधिकतर ने पाकिस्तान छोड़ दिया, जो बच गए उन्हे मार दिया गया।''[2] आज यहाँ बहुत ही कम संख्या में इन समुदाय के लोग है।

पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व सैन्य सरकारें एक के बाद एक सत्ता में रही है हालांकि जब सेना सत्ता से बाहर रही तो भी सरकार पर उसका प्रभाव रहा।

6,00,000 सैनिको सें ज्यादा के साथ पाकिस्तान के पास विश्व की 7 वीं सबसे बड़ी सेना है और इसके पास परमाणु क्षमता भी है। पाकिस्तान मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान देश है जिसकी करीब 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं इसके मुख्य उद्योगों में वस्त्र, चमड़ा व खाद्य प्रसंस्करण शामिल है ''पाकिस्तान की मुद्रा विनिमय दर 60.35 अमेरिकी डॉलर प्रति रूपया तथा जी0डी0 पी0(क्रय शक्ति) 437.5 विलियन डालर तथा जी0डी0पी0 (प्रति व्यक्ति) 2600 डॉलर है। जी0डी0पी0 (क्षेत्रवार) सेवा –53.4 प्रतिशत, उद्योग–27.2 प्रतिशत, कृषि – 19.4 प्रतिशत है।''[3]

पाकिस्तान को विश्व में आतंकवाद का स्रोत समझा जाता हैं मजहबी फिरको के आतंकवादी गुटों से लेकर, सर्व इस्लामी जिहादियों, आई0 एस0 आई0 और वहाँ की राज्य

सरकार की नीति आतंकवाद रूपी हथियार का प्रयोग करना है।

इस्लामी देश पाकिस्तान 1947 ई0 से ही जिहादी आतंकवाद का केन्द्र बना हुआ हैं इसका उद्देश्य न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी गैर इस्लामी राज्यों को इस्लाम के नियंत्रण में लाना हैं

जानसेन के अनुसार–''धर्म और राजनीति इस्लामी सिक्के के दो पहलू है''[4] इसलिए पाकिस्तान की सभी राजनैतिक जिहादी, तबलीगी एवं मदरसों की गतिविधियाँ विभिन्न मजहबी संगठनों की आड़ में चलती है। सन् 1970 ई0 तक पाकिस्तान में केवल तीस धार्मिक संगठन थे,जो कि ज्यादा सक्रिय नहीं थें इनमें सात देवबन्दी, पाँच बरेलवी, चार अहले–हदीस और तीन शिया – वर्ग के थे। जमाते इस्लामी को गैर मजहबी समझा जाता था। 1979 ई0 में 'ईरानी क्रान्ति' और अफगानिस्तान युद्ध के बाद मजहबी सक्रियता बढ़ी तथा लगभग सभी मजहबी संगठन 1979–1990 ई0 के बीच तेजी से बढ़े।

जिहादियों की भरती के दो मुख्य स्रोत हैं–(1) मदरसे और स्कूल, (2) कालेज एवं विश्वद्यिालय, साठ प्रतिशत जिहादी युवक पढ़ाई में फेल होने व अन्य कारणों से स्कूल छोड़ने तथा परिवार में अनबन के फलस्वरूप घर से भागने वाले होते है। इसके अलावा पाकिस्तान युवक गरीबी, बेकारी जीवन से निराश तथा शान शौकत की जिन्दगी जीने की चाह, धार्मिक कट्टरता व जन्नत के प्रलोभनों के कारण जिहादी बन जाते है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार– ''युवक बेकारी और गरीबी के कारण जिहादी बनते हैं। जिहाद के लिए करोड़ो का बजट रहता है।''[5] हालांकि हदीसो में युवतियों के लिए सक्रिय जिहादी की मनाही है मगर पाकिस्तान में युवतियाँ भी जिहाद मे भाग लेती हैं। पाकिस्तान में विभिन्न जेहादी संगठन युवकों को जिहाद के लिये भरती करने के लिये विभिन्न तरीके अपनाते है जैसे मस्जिदो मे जिहाद भड़काऊ भाषण देकर, मदरसों में तालिबानों को जिहाद के लिए उकसाना, जीवित रहने पर शान–शौकत की जिन्दगी और मर जाने पर जन्नत के प्रलोभनों को देकर, स्कूल, कालेज में विद्यार्थियों को जिहादी, पैम्फलेट, पत्र–पत्रिकाएँ छोटी पुस्तिकाएँ, मैग्जीन देकर जिहादी मेलों को आयोजित करके आदि।

जिहादियों को जिहाद के लिए भेजने से पहले विधिवत् विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनमें सबसे पहले धार्मिक कट्टरता एवं जिहाद के लिए समर्पण मुख्य है। इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध, बम बनाना सभी प्रकार के वाहन एवं सैनिक–अस्त्र शस्त्रादि चलाना, गुप्तचरी करना आदि सिखाया जाता है। इनमें कम से कम छह माह तक की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान अपने ही नहीं बल्कि विश्व भर के जिहादियों का प्रशिक्षण केन्द्र बन गया है जो उसके स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है।

पाकिस्तान में सत्ता के कई बिन्दु बन गये हैं प्रथम बिन्दु सेना है, दूसरा बिन्दु आई0 एस0 आई0 है तथा तीसरा बिन्दु आतंकी जेहादी दी संगठन हैं आज पाकिस्तान की प्रमुख

विशेषता यह है कि वह आतंकवादी कार्यवाही का केन्द्र बन गया है। वह न केवल भारत में वरन् विश्व के कई देशों में घटित होने वाले आतंकवाद को पूर्णतः प्रोत्साहन देता चला आ रहा है। आज विश्व के देशों में जब भी आतंकवाद की कोई घटना घटित होती है और आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है तो उनका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान से जरूर जुड़ा होता है।

विश्व भर में आतंकवाद का निर्यात करने वाला राष्ट्र पाकिस्तान वर्तमान में, स्वयं आतंकवाद की समस्या से पीड़ित है।

पाकिस्तान की सुरक्षा को इस समय सबसे अधिक खतरा स्वयं द्वारा पोषित आतंकवाद से हो गया है सन् 2002 से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी। पाकिस्तानियों ने 2002 से पहले बृहत रूप में आत्मघाती बमों का ताण्डव नहीं दिखा था।

''विश्व के विफल राष्ट्रों की श्रेणी में सन् 2007 में 34 वें स्थान पर रहने वाला पाकिस्तान वर्तमान में 9वें स्थान पर आ गया है।''[6]

''अप्रैल 2009 के प्रथम सप्ताह में पंजाब प्रान्त के चकवाल की एक शिया मस्जिद में हुई सांप्रदायिक आतंकी हिंसा के दौरान आत्मघाती बम बिस्फोट में 24 लोग मारे गये।''[7]

''30 मार्च 2009 को लाहौर में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए दुस्साहसी आतंकवादी कृत्य में आतंकवादियों ने 800 जवानों को बन्दी बना लिया था।''[8] हालांकि सुरक्षा बलों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया था। और तीन आतंकवादियों को बन्दी बना लिया था। लेकिन इस आतंकवादी कृत्य में बहुत से जवान भी मारे गये थे। इस आतंकवादी हमले ने यह दिखा दिया था कि आतंकवादी चाहे जहाँ घुसकर हमला कर सकते है।

इस घटना के कुछ दिन पूर्व आतंकियों के एक गुट ने श्री लंका की क्रिकेट टीम पर आतंकी हमलाकर पूरी दुनियां को सकते मे डाल दिया था। इस हमले में कुछ क्रिकेटरों को घायल कर व 8 पुलिस वालों को मारकर सभी आतंकी सुरक्षित भागने में सफल हो गये थे। पाकिस्तान में घटित होने वाली आतंकी घटनाएं आतंकियों के दुस्साहस की पराकाष्ठा कही जा सकती है, और यदि कहे कि पाकिस्तान अपने बनाए जाल में फंसकर दम तोड़ता दिखाई पड़ रहा हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ''पाकिस्तान मे जुलाई 2007 से अब तक आतंकी हमले में 1,700 से ज्यादा लोग मृत्यु का ग्रास बन गये है।''9

पाकिस्तान ने जिस तालिबान और अलकायदा को पल्लवित होने मे योगदान दिया था वो ही पाकिस्तान को नष्ट करने पर तुले है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत है कि पाकिस्तानी में अब तालिबान व्यवस्था पूरी तरह से हावी हो चुकी है स्वात घाटी में लागू हुआ शरीया कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्तमान में पाकिस्तान सरकार इन कट्टरपंथी तालिबान नेताओं के सामने इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि उसे इस इलाके में उनके साथ शांति समझौता करना पड़ा और शरिया कानून लगाने के उनके फैसले को संसद

में मंजूरी भी देनी पड़ी।

एक अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार– अगले 6 माह मे पाकिस्तान आंतरिक रूप से टूटकर बिखर सकता हैं अमेरिकी राष्ट्रपति 'बराक ओबामा' ने पाक–अफगान बार्डर को विश्व की सबसे खतरनाक जगह की उपाधि दी हैं हालांकि। अमेरिका अब भी पाकिस्तान को सभी तरह की मदद दे रहा हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को 1.5 विलियन डालर की आर्थिक सहायता दी है।

पाकिस्तान के आतंकग्रस्त प्रमुख क्षेत्र– 9/11 के बाद के वर्षो में अफगानिस्तान से लगी पाक सीमा के इलाके काबुल के साथ पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का स्रोत बन गए है। ''सन् 2007 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी 1,600 मील लम्बी सीमा रेखा जिसे डूरंड लाइन के नाम सें जाना जाता है। के क्षेत्रों में बाड़ लगाने के काम शुरू किया है लेकिन पाकिस्तान द्वारा 1949 ई0 में खीची गई इस सीमा रेखा को अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी है।''[10] और इस क्षेत्र के कबायली गुटों द्वारा भी लम्बे समय से इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

पाकिस्तान के कबाइली क्षेत्र भी अशांत क्षेत्रों में तब्दील हो गये है। पाकिस्तानी सरकार ने कबाइली नेताओं के साथ समझौता कर लिया हैं। पाकिस्तान का उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रान्त भी पाकिस्तान के आतंक की आग में जल रहा है। सन् 2002 के चुनाव में यहाँ धार्मिक कट्टरपंथियों को राजनैतिक स्थापना मिली। यह क्षेत्र पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रान्त हैं इस प्रान्त में पश्तून (पठान) सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय हैं जो किसी भी तरह की आज्ञा के अधीन काम न करके स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था संचालित करता हैं। अफगानिस्तान में निवास करने वाले पठानों का इन्हे पूर्ण समर्थन मिलता रहता है इसी क्रम में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का सबसे अशांत क्षेत्र है यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पूर्णतः समृद्ध है परन्तु पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र का विकास न के बराबर हुआ है इसके अलावा सन् 1998 ई0 के परमाणु परीक्षण के बाद फैले विकरण ने इस क्षेत्र को त्रस्त सा कर दिया है।

पाकिस्तान में कितने आतंकी गुट अपने गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन सा है परन्तु इनकी गतिविधियों के आधार पर इन्हे वर्गीकरण किया जाय तो हम पाते है कि प्रथमतः अलकायदा और इसके सहयोगी है। इस संगठन की संचालन की कमान फाटा (Federally ADMINISTERED Tribal Areas-FATA) क्षेत्र मे छिपे ''अलकायदा के ओसामा बिन लादेन व दूसरे गैर दक्षिण एशियाई आतंकियो के हाथ मे है। अलकायदा के साथ इस क्षेत्र में इस्लामिक फाइटर्स ग्रुप,व इस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे विदेशी आतंकी संगठन है।''[11] द्वितीय पाकिस्तानी तालिबान है। इस समूह में फाटा में स्थित चरमपंथी ग्रुप भी शामिल है जिनकी कमान अलग–अलग स्थानीय कबायली नेताओं के हाथों में है। इनमें दक्षिण वजीरिस्तान में महसूद जनजाति के नेता बैतुल्लामहसूद

तरीक–ए–नफज–शरियत–ए–मोहम्मदी के नेता मौलाना 'फकीर अहमद' व 'मौलाना काजी फैजुल्लाह' तथा लश्कर–ए–इस्लामी के नेता 'मंगलबाद अफरीदी' शामिल है। तृतीय क्रम में भारत विरोधी गुट हैं इनमें भारत के खिलाफ गविधियों कां अंजाम देने में लगे वे आतंकी सुगठन है जिन्हे पाकिस्तानी सेना व पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी आई0एस0आई0 का पूर्ण सहयोग मिल रहा हैं ऐसे संगठनों में लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मुहम्मद, हरकत–एल–मुजाहिदीन आदि शामिल हैं इसके अलावा पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले सुन्नीगुट सिपाह–ए–शहाबा व शियागुट तहरीका–ए–जाफरिया भी है मुल्ला मोहम्मद उमर के चारों ओर केंद्रित इसका कंधार नेतृत्व अब क्वेटा से अपनी गतिविधियों को चला रहा हैं

वर्तमान मे पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने उसके अंदर व्याप्त आतंकवादी समस्या को गंभीर बना दिया हैं आई0 एम0 एफ0 द्वारा दिये गए 7.6 बिलियन डॉलर के लोन ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया लेकिन देश में मुद्रास्फीति की दर 25 प्रतिशत तक पंहुच चुकी हैं जो स्थिति की गम्भीरता को दर्शाती हैं सारी बुनियादी वस्तुओ के दाम लगभग दुगुने हो चुके है यह स्थिति शायद पाकिस्तान के बिखराव का एक बड़ा कारण बनेगी।

पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्व में सहभागी बनने की सहमति से आतंकवादी संगठनों ने अब इस देश की व्यवस्था को नष्ट–भ्रष्ट करने का कार्य वृहत स्तर पर प्रारम्भ कर दिया हैं अगर वर्तमान गम्भीर स्थिति में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों का सफाया निष्ठापूर्वक नहीं किया तो पाकिस्तान का बिखरना तय है।

संदर्भ सूची

1. पाकिस्तान जिन्ना से जेहाद तक – एस0के0 दत्ता, राजीव शर्मा – पृ0 सं0 50
2. India & Pakistan – Raj Kumar Singh – पृ0 सं058
3. www. satp.org बेवसाइट – 28 Dec 2009
4. मिलिटैण्ट एण्ड इस्लाम – डॉ0 अल्बर्ट जानसन – पृ0 सं0 68
5. दि जिहाद फैक्ट्री – डॉ0 नसरूल्लाह बाबर – पृ0 सं0 70
6. www.satp.org. बेवसाइट – 12 Jan 2010
7. इंडिया टुडे – 30 अप्रैल 2009 – पृ0 सं0 45
8. दि टाइम्स आफ इंडिया – 31 Jan 2010 – पृ0 सं06
9. इंडिया न्यूज – 28 Jan 2010 – पृ0 सं0 15
10. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद – मेजर विनोद सहगल – पृ0 सं0 60
11. भारत की आन्तरिक समस्या – डॉ0 विजेन्द्र सिंह – पृ0 सं0 75

भारत चीन सम्बन्ध : अतीत एवं वर्तमान सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 देवेश चन्द्र कटियार
एसोसिएट प्रोफेसर
सैन्य अध्ययन विभाग
पी0पी0एन0 कालेज, कानपुर

कु0 कंचन राजपूत
शोध छात्रा
सैन्य अध्ययन विभाग
पी0पी0एन0 कालेज, कानपुर

प्राचीन काल से ही चीन एक बौद्ध देश रहा है जबकि भारत 'बुद्ध भूमि'। भारत से ही बौद्ध धर्म हिन्द चीन होते हुये चीन पहुँचा। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पौराणिक काल से ही भारत से अनेक बौध भिक्षु चीन पहुँचे। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओं ने सन् 2005 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाण्डीज से मुलाकात में कहा था कि भारत–चीन सम्बन्धों का लगभग 2200 वर्षों का एक लम्बा इतिहास है जिसमें 99.9 प्रतिशत हिस्सा सुखद बीता है वैसे यदि इतिहास को बारीकी से परखा जाय तो हमारे सम्बन्धों का इतिहास 2200 वर्षों से भी पुराना है। महाभारत और उपनिषदों के रचना काल से ही दुनिया की इन दो सबसे प्राचीन सभ्याताओं के बीच वैचारिक आदान–प्रदान चल रहा था। पर्वतराज हिमालय को पूर्व या पश्चिम किसी दिशा से पार करना एक सार्थक अभियान है। चीनी मान्यताओं के अनुसार– हिमालय के पार का देश भारत ''ज्ञानभूमि'' है।

सम्प्रति भारत–चीन सम्बन्धों को लेकर काफी तनाव पूर्ण वातावरण बना हुआ है। जैसे सीमा विवाद पड़ोसी राष्ट्र को कूटनीतिक सहयोग प्रदान कर अपने पक्ष में मिलाना–पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का सहयेाग हिन्दमहासागर में अपनी दखलंदाजी तेज करना म्यांमार के रास्ते दक्षिण एशिया को चुनौती भारतीय बाजारों पर चीनी वस्तुओं का कब्जा, आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन का उभरना, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करना आदि मुद्दे वर्तमान में भारत–चीन सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा कर रहे है। उपरोक्त समस्याओं का भारत को समय रहते आत्म चिंतन, मंथन करना होगा।

किसी भी देश की सुरक्षा में उसके पड़ोसी देशों की सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं राजनयिक विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ सामरिक रूप से सुरक्षित राजनीतिक रूप से स्थिर व शांतिपूर्ण तथा आर्थिक रूप से सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाये रखना है तथा दूसरी ओर हमारा पड़ोसी चीन दोस्त होने का दावा करते हुये दगा देता रहा है। यदि चीन की विदेशनीति के आधारभूत चरित्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जायेगा। चीन की

विदेशनीति शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व की बजाय विस्तारवाद व साम्राज्यवाद के कपटपूर्ण तरीकों से सम्पन्न थी। किन्तु नेहरू जी उसे पंचशील के शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के चश्मे से देखते रहे।[1] आज भी चीन के साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्धों की बात की जाती है। आज चीन पहले से अधिक घातक और शक्तिशाली हो चुका है, जिस प्रकार चीन भारत के पड़ोसी राज्यों में अपना संजाल बिछा रहा है वह उसकी दूरगामी योजना को स्पष्ट करता है।

भारत के पड़ोस में विगत कई दशकों से राजनीतिक अशान्ति एवं अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। चीन से भारत को निश्चित रूप से सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय शांति एवं सुरक्षा के लिए हमारा पड़ोसी देश चीन चारो ओर से अपना सामरिक जाल फैलाते हुए घातक गतिविधियाँ अपनाता जा रहा है लेकिन हमेशा से ही चीनियों के प्रति यह धारणा रही है कि चीनियों को समझना टेढी खीर है यह हू जिनताओं की यात्रा से भी स्पष्ट हुआ, क्योंकि उनकी इस यात्रा से कुछ ही दिन पूर्व चीनी राजदूत ने तवांग (अरुणाचल) पर चीनी दावा कर अरुणाचल को चीन का हिस्सा माना, लेकिन हू जिनताओ विवादित मुद्दों पर जवाब देने से बचते रहे।[2] इससे तो यही स्पष्ट होता है कि चीन की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क साफ है। भारत को समझ जाना चाहिए कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल म्यांमार, बांग्लादेश में ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है कि भारत को चारो तरफ से घेर सके।

यद्यपि भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक समझौता हुआ है उससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफी अन्तर आ सकता है, क्योंकि 26 वर्ष पूर्व भारत और चीन की प्रति व्यक्ति की आय समान थी। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले ढाई से तीन गुनी ज्यादा है। आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता स्वाभाविक है, किन्तु चीन के साथ नजदीकियाँ बढाते समय हमें उनके हाथों ऐतिहासिक अनुभवों को नही भूलना चाहिए। भारत की सीमाओं पर दो कट्टरवादी इस्लामी देश पहले से ही भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। इन दोनों के साथ चीन के अच्छे सम्बन्ध है इसलिए चीन रणनीतिक दृष्टि से भारत को चारो ओर से कसने के प्रयास में है।

चीन द्वारा उल्लघंन तथा भारत विरोधी कार्यवाही–

चीनी सेना ने भारत के साथ 1962 में गतिरोध उत्पन्न के बाद से पहली बार लद्दाख सेक्टर की काराकोरम रेंज से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्माण शुरू कर दिया है। सरकार के अनुसार इसका प्रयोग भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कैमरा लगाने के लिए किया जा सकता है। कराकोरम दर्रा वास्तविक नियंत्रण रेखा के तौर पर जाना जाता है। इस दर्रे के पश्चिम में स्थित सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद में यह क्षेत्र बड़ी भौगोलिक भूमिका भी अदा करता है।

ज्ञातव्य है कि यह स्थिति 1972 में भारत–पाक शिमला समझौते के बाद उत्पन्न हुई थी, जब संधि में नियंत्रण रेखा के अन्तिम छोर और काराकोरम दर्रे के बीच संघर्ष विराम रेखा के अंतिम एक सौ कि0मी0 के क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया जा सका था।

पीओके में विवादास्पद नीलम–झेलम प्रोजक्ट तथा बुंजीडैम प्रोजेक्ट में चीन सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त चीन ने इस क्षेत्र में काराकोरम हाईवे एवं 16 सैन्य हवाई पट्टियों का निर्माण भी किया है इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत के विरोध करने पर चीन पीओके में पाकिस्तान की मदद जारी रखने की बात भी दुहराता है। उधर चीन नेपाल में भी ल्हासा से काठमांडू तक राजमार्ग बनाने की तैयारी कर रहा है।[3]

भारत के साथ चीन का सीमा विवाद एक ऐतिहासिक देन है। पूर्व के भारतीय नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण यह विवाद अत्यन्त विषाक्त स्थिति में पहुंच चुका है। इस विवाद के कारण सन् 1962 में युद्ध भी हुआ; परन्तु उसके बाद से आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लगभग 95 वर्ष पूर्व मैकमोहन सीमा रेखा तय की गई थी, परन्तु चीन आरम्भ से ही इससे असहमत रहा है। इधर भारत का मानना है कि चीन ने जम्मू कश्मीर के 38 हजार वर्ग कि0मी0 के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान ने भी 1955 में उसकी 5 हजार वर्ग कि0मी0 जमीन पर अवैध कब्जा करके चीन को सौंप दिया है। जबकि चीन का कहना है कि भारत ने अरूणाचल प्रदेश में उसके 90 हजार वर्ग कि0मी0 इलाके पर कब्जा कर रखा है। भारत–चीन सम्बन्धों को लेकर मामला तब अटक सा जाता है जब सीमा विवाद सामने आ जाता है। पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से बातचीत होने के बावजूद सीमा विवाद लगभग जस का तस है।[5]

चीन–पाक के मध्य पनपते सामरिक सम्बन्ध भारतीय सुरक्षा के लिए संकट–

भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बडा खतरा चीन–पाक गठजोड़ रहा है। पाक चीन के मध्य सामरिक सम्बन्धों को नजर अंदाज नही करना चाहिए। चीन द्वारा पाक के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के पीछे भारत को कमजोर करने की साजिश रही है। चीन–पाक गठबंधन के मुख्य पहलू रहे है : विश्व परिदृश्य में भारत की छवि धूमिल करना, हथियारों के व्यापार हेतु नया बाजार प्राप्त करना, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना।

चीन भारत के विरुद्ध बिना हथियार चलाये ही, हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से भारत के साथ युद्ध छेड़े हुए है। चीन ने अपनी एशियाई नीति में परिवर्तन कर भारत को घेरने के लिए राजनयिक चालें चलनी शुरू कर दी और भारत के आसपास के छोटे राष्ट्रों का सहायक बन गया तत्पश्चात् चीन के लिए भारत विरोधी अभियान चलाना कठिन कार्य नहीं रहा। चीन, पाकिस्तान की हर नीति का समर्थन करने लगा है।

चीन ने ''मोती की डोर'' की नीति पर चलते हुए भारत को घेरने का प्रयास किया है।[6]

वर्तमान समय में सम्बन्धों में सुधार के लिए राजनेताओं की वार्ताओं और यात्राओं का दौर भले ही शुरू हो गया हो। परन्तु क्या चीन ने अपनी सामरिक नीति को परिवर्तित किया है या यह चीन की कोई नयी रणनीति है? भारत को इन सभी पहलुओं पर गम्भीर मंथन की आवश्यकता है; क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जुलाई 2005 में अमेरिका की यात्रा पर थे, तब उन्होंने असैनिक नाभिकीय ऊर्जा समझौते किये।[7] इस ऐतिहासिक समझौते के बाद जब भारत को परमाणु ईधन और तकनीकी उपलब्ध कराने के बारे में सितम्बर 2008 में 45 देशों वाले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (N.S.G.) की बैठक हुई तो उसमें चीन ने फिर अपना घृणित रंग दिखा दिया। उसने एक तरफ बैठक में व्यवधान डाला, ताकि भारत को छूट न मिल सके। दूसरी ओर यह कोशिश भी करता रहा कि यदि यह सुविधा भारत को प्राप्त हो रही है, तो अन्य देशों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिये। उसका इशारा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर था; क्योंकि अपनी दूरगामी योजना के तहत वह एशिया में भारत के बराबर पाकिस्तान को खड़ा करना चाहता है। हालांकि उसे इसमें सफलता नही मिल सकी। परमाणु व्यापार के लिये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (N.S.G.) से मिली 'खुली छूट' भारत की ऐतिहासिक जीत है।

जनवरी 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीन यात्रा के दौरान एक बार फिर चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता पर समर्थन करने का आश्वासन दिया है।[8] यह समय ही तय करेगा कि चीन द्वारा दिया गया आश्वासन सही है या एक कूटनीतिक चाल।

चीन ने 1998 के बाद से तिब्बत में अपनी सामरिक स्थिति काफी मजबूत बना ली है।

चीन के म्यांमार से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। म्यांमार सैन्य शक्ति के मामले में पूर्णतः चीन पर ही निर्भर है। चीन, म्यांमार के निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।[9] चीन म्यांमार की हर स्तर से सहायता प्रदान करके उसे अपना सामरिक सहयोग बनाना चाहता है। हाल ही में चीन ने म्यांमार को डीप वाटर पोर्ट बना कर दिया है।[10]

चीन के द्वारा दिये गये हथियारों पर बांग्लादेश की पूरी सैन्य शक्ति टिकी हुयी है। चीन बांग्लादेश की नौसेना को 1500 टन का जिआंग्लू क्लास का युद्धपोत पहले ही दे चुका है। हाल ही में उसने बांग्लादेश के मिसाइल कार्यक्रम को भी हवा दे दी है। चीन द्वारा दी गयी मिंग जी–802 मिसाइल का बाग्लादेश की नौसेना ने कुतुबदीआ द्वीप के पास सी–802 ए के तौर पर परीक्षण किया है। चटगाँव पोर्ट पर मिसाइल लांच करने की क्षमता चीन पहले ही तैयार कर चुका है।[11] बांग्लादेश की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा चीन, अब उसे सतह से हवा में 200 कि0मी0 तक मार करने वाली मिसाइल देने पर भी बातचीत कर रहा है।[12] चीन ने बांग्लादेश में उसकी नौसेना और व्यापार के लिये आधुनिक बंदरगाह बनाये है; लेकिन

सच तो यह है कि इन नौसेनिक अड्डों पर चीनी सेना का अधिकार है, जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से गम्भीर खतरा है।

दक्षिण एशिया में चीन का सबसे अभिन्न मित्र पाकिस्तान है। चीन उसका इस्तेमाल भारत को दक्षिण एशिया में उलझाये रखने के लिये करता है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के निर्माण में चीन की अहम भूमिका रही है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की तकनीक और प्रक्षेपास्त्र दिये है। हालांकि इस सम्बन्ध में गोपनीयता रखते हुए लेन–देन किये गये थे, फिर भी चीन पर यह आरोप लगाया गया है कि वह परमाणु डिजाइन, परीक्षण डाटा, भारी पानी तथा ज्ञात एवं गोपनीय संवर्धन सुविधाओं से सम्बन्धित सहायता पाकिस्तान को दे रहा है।[13] हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को चौंतीस एस–11 मिसाइलें और लांचर्स भेजे हैं। जो सरगोधा अड्डे में रखे गये हैं। इस समय चीन पाकिस्तान को अल–खालिद टैंक और लड़ाकू हवाई जहाज बनाने में मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान के मध्य प्रान्त पंजाब के चश्मा में 325 मेगावाट का परमाणु संयंत्र पहले ही स्थापित कर चुका है इसके अलावा वह इतनी ही क्षमता का एक और संयन्त्र अब पाकिस्तान में लगाने की दिशा में कार्य कर रहा है।[14]

चीनी कार्यवाई के प्रति भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम–

भारत सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 23 कि0मी0 दूर 'नायोगा एडवांस लैडिंग ग्राउण्ड' पर तृतीय हवाई पट्टी खोल दी है। इससे दूरदराज की चौकियों तक रसद पहुंचाना आसान हो जाएगा। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में परियोजनाओं के निर्माण में पाकिस्तान की मदद करने के चीन के आश्वासन पर कड़ी आपत्ति जतायी है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भारत में कार्यरत हजारों चीनी नागरिकों को बीजा देने की नीति में भी बदलाव किया जाएगा। यहाँ पर कार्यरत चीनी नागरिकों को लेकर कई बार असंतोष भी व्यक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ में चीनी कम्पनी सेप्को द्वारा निर्मित चिमनी के गिर जाने से 40 से ज्यादा मजदूर मारे गये थे। इससे चीनी काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे है। अब दक्ष चीनी कामगारों को कारोबार बीजा के बजाय रोजगार बीजा दिया जाएगा।[15]

उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चीन भारत के चारो ओर सामरिक व्यूहन की अपनी रणनीति पर आज भी कायम है। भारतीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील सीमावर्ती चीन के विकास को देखते हुए भारत को सर्तक रहने की आवश्यकता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें चीन के साथ सम्बन्धों के गाँठ–जोड़ में सोच–समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है; क्योंकि चीन भारत के समस्त पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ कर रहा है, जो कि भारत के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। "अभी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रमुखता से यह छापा कि चीन गुलाम कश्मीर को हड़पना चाहता है। चीन की

बढ़ती दखलंदाजी के कारण यह आशंका निरर्थक नही है कि, बीजिंग वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा सकता है।''[16]

अतः भारत को कूटनीतिक प्रयासों से पड़ोसी राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध सुधारने होंगे, साथ ही अपनी आर्थिक नीतियों से पड़ोसी राष्ट्रों को अपने साथ मिलाना होगा। साथ ही सामरिक सुदृढ़ता व सैन्य तैयारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। अन्यथा चीनी ड्रेगन की जकड़न से भारत को बचाना दुश्कर होगा।

संदर्भ सूची

1. कर्नल पी0के0 वासुदेवा, यु0एस0आई0 जर्नल. अक्टूबर–दिसम्बर 2008
2. प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल 2008 पृष्ठ सं0 1625
3. सिविल सर्विसेज क्रांनिकल दिसम्बर 2009 पृष्ठ सं0 17
4. सिविल सर्विसेज, टाइम्स सितम्बर 2009 पृष्ठ सं0 30
5. दैनिक जागरण, जनवरी 12.2008
6. सिविल सर्विसेज, टाइम्स अगस्त 14, 2009 पृष्ठ सं0 38
7. अचिन विनायक, ईरान अमेरिका और भारत, अमनवार्ता खण्ड–4 अंक–1, पृष्ठ सं0 02
8. दैनिक जागरण, जनवरी 14. 2008
9. बाबू राम पाण्डेय, राम सूरत पाण्डेय, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 2008 पृष्ठ सं0 192
10. दैनिक जागरण, सितम्बर 22. 2008
11. अरिहन्त समसामायिक महासागर, जनवरी 2009 पृष्ठ सं0 50
12. दैनिक जागरण, सितम्बर 22. 2008
13. पी0के0एस0 नबूदरी, चाइना पाकिस्तान, न्यूक्लियर एम्सेल स्ट्रेटजिक एपालिसिस खण्ड–6 टिप्पणी सं0 7, अक्टूबर 1982 पृष्ठ सं0 426
14. अरिहन्त समसामायिक महासागर, जनवरी 2009 पृष्ठ सं0 56
15. सिविल सर्विसेज क्रांनिकल दिसम्बर 17. 2009
16. दैनिक जागरण, मई 11. 2011

वैश्विक तापवृद्धि एवं जलवायु–परिवर्तनः एक भौगोलिक विवेचन

श्रीमती राज किरन चौरसिया
डा0 आर0के0 चौरसिया
एसोसिएट प्रोफेसर
भूगोल विभाग, बी0एस0एस0डी0 कालेज
नवाबगंज, कानपुर

रोहित कुमार
प्रवक्ता, पर्यावरण अध्ययन
वी0एस0एस0डी0 कालेज, नवाबगंज
कानपुर

बदलते विश्व परिदृश्य में एक तरफ आर्थिक विकास की गति तीव्र हो रही है दूसरी ओर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन ने मानव के अस्तित्व को बनाये रखने हेतु सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज जहाँ एक ओर विध्वंसक हथियारों पर रोक लगाने के प्रयास जारी है, वही दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन में महाप्रलय की आहट ने हम सभी को भयभीत कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जलवायु परिवर्तन से अनेक सभ्यतायें विनिष्ट हो चुकी हैं। वर्तमान ईराक और सीरिया में चार हजार साल पूर्व की सभ्यता के विघटन का कारण तीन सौ वर्षों तक सूखा या अनावृष्टि ही था। सभ्यता के केन्द्र उत्तरी शहरों से बड़े पैमाने पर आबादी के चले जाना ही विघटन का कारण बना। लगभग 2200 ई0पूर्व मेसोपोटामिया में दबी सतहों की मिट्टी की जाँच कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार तीन शताब्दी तक चले सूखे की शुरुआत होते ही अत्यन्त समृद्ध और विकसित कृषि सभ्यता समाप्त हो गयी। येल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विद् हावेक्सि के अनुसार, ''वातावरण ने एक–एक अपने क्षेत्रीय बदलाव से मिश्र से लेकर अमरीका तक की कृषि और सभ्यता पर जबरदस्त प्रभाव डाला'' वातावरण में आये इस बदलाव को पूर्वी अफ्रीका एवं नील के पास एवं भारत (पाकिस्तान) के समीप सिन्धु घाटी और फिलीस्तीन में भी देखा गया अर्थात् सिन्धु घाटी सभ्यता का विनाश भी जलवायु परिवर्तन से ही हुआ था।[1]

पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि, प्रकृति तथा मानव जीवन पर उसके प्रभाव से वैश्विक तापमान प्रक्रिया का बोध होता है। सामान्यतः वैश्विक तापन का अभिप्राय ''मानव–क्रियाओं के फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बढ़ने पर पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि से है।'' सामान्यतः वैज्ञानिक मान्यता है कि औद्योगिक युग के प्रारम्भ से मानव क्रियाकलापों के प्रभाव से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों (कार्बनडाइआक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरा कार्बन) की वृद्धि की वैश्विक तापन का प्रमुख कारक है। वर्तमान में विश्व का औसत तापमान 15.8° सेल्सियस है, जिसमें प्रतिवर्श 0.7° से 1.4°C की वृद्धि हो रही है।

इक्कीसवी शताब्दी में 5° से 6°c तापमान में वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की जा रही है जबकि मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि ही विश्व में तबाही पैदा करने के लिये पर्याप्त है। वर्तमान समय तक वैश्विक तापन की समस्या के समाधान के लिये इण्टरनेशनल इंस्ट्यूट के नाम पर 55 देशों ने सामूहिक रूप से क्योटो सन्धि की है। क्योटो सन्धि के बाद भी कार्बन उत्सर्जन में कमी नही आयी है।

तापमान को जलवायु का आधारभूत कारक कहा जाता है। जलवायु के अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उससे प्रभावित होते हैं। विश्व भर में हो रहे जलवायु परिवर्तनों के मूल में भी तापमान ही है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसे ही वैश्विक तापन का नाम दिया गया है। वास्तव में वैश्विक तापन एक सार्वभौमिक समस्या है। इस समय विश्व का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। मोटे तौर पर या सामान्य शब्दों में कहे तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है। यह बढ़ता तापमान ही जलवायु परिवर्तन के लिये जिम्मेदार है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन से रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है तो सघन वर्षा के क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, इससे तटीय स्थानों एवं द्वीपों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है।

हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक तापन का अभिप्राय :–

सूर्य से आने वाली विकिरण का लगभग 40 प्रतिशत धरती के वातावरण तक पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाता है। 15 प्रतिशत वातावरण में अवशोषित हो जाता है एवं धरातल पर लगभग 45 प्रतिशत ही पहुँचता है। यह गर्मी (दीर्घ तरंगों) के रूप में पृथ्वी से परावर्तित होती है। वायुमण्डल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगे सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक अवशोषित कर लेती है। इस कारण वायुमण्डल में पृथ्वी का औसत तापमान 35° सेल्सियस के आस–पास बना रहता है। वस्तुतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत गैसे ऊपरी वायुमण्डल में एक ऐसी परत बना लेती हैं जिसका असर पौधों को बाहरी गर्मी–सर्दी से बचाने के लिये बनाये गये ग्रीन हाउस की छत जैसा होता है। इस प्रक्रिया को ही 'हरित गृह प्रभाव' कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के लिये उत्तरदायी प्रमुख गैसे है– कार्बनडाइआक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन, ओजोन, सल्फर डाईआक्साइड तथा जलवाष्प। उपर्युक्त गैसों में कार्बनडाइआक्साइड (CO_2) सबसे महत्वपूर्ण गैस हैं। प्रयोग, निर्वनीकरण एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन इसके प्रमुख स्रोत है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेंट चेंज (IPCC) के अनुसार 1880–1890 में इसकी मात्रा लगभग 290 पार्ट्स पर मिलियन (PPM) थी जो 1990 में बढ़कर 340 PPM एवं वर्श 2007 में 400 PPM हो गई। वायुमण्डल में मीथेन गैस की मात्रा भी चिन्ताजनक रूप में बढ़ रही है। पिछले 100 वर्षों में मीथेन गैस का संकेन्द्रण दो गुने से भी अधिक हो गया है। ग्रीन हाउस गैसों में हो रही इस वृद्धि में वायुमण्डल में विकिरणों

के अवशोषण करने की क्षमता निरन्तर बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे ही वैश्विक तापन कहा जाता है।

वैश्विक तापन के कारणः– वैश्विक तापन के कई कारण हैं जिनमें प्रमुख रूप से निम्नांकित महत्वपूर्ण हैं–

1. औद्योगिक उत्सर्जन, कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा में वृद्धिः– उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुँआ, फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलने वाला धुँआ, एवं दफ्तरों में विविध उपकरणों से निकलने वाली गर्म वाष्प आदि प्रतिदिन हमारे वातावरण में पर्याप्त गर्मी घोलती है। वातावरण में आवश्यक ताप घोलने में सबसे आगे ताप बिजलीघर हैं, इनमें कोयला जलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पिछले एक शताब्दी में पेट्रोलियम पदार्थो एवं अन्य जीवाश्म ईधनों के प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 600 वर्षों में वायुमण्डल में कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा 65 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई है, जो वैश्विक तापन का मूल कारण है।

चार देशों द्वारा CO_2 का सार्वधिक उत्सर्जन 2007

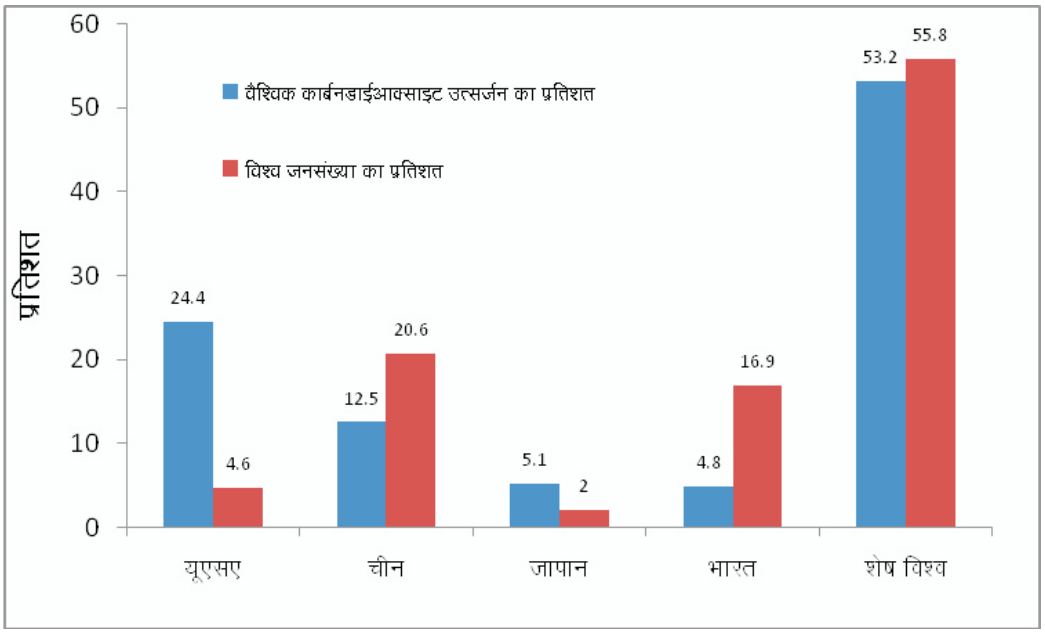

1. क्लोरो–फ्लोरो कार्बन की भूमिकाः– इस समय इस रासायनिक पदार्थों के एक वर्ग का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, जिन्हें क्लोरो–फ्लोरो कार्बन कहते हैं। ये पदार्थ वायुमण्डल के ऊपर जाते हैं और वायुमण्डल के ऊपरी भाग में स्थित 'ओजोन की परत' को क्षति पहुँचाते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल के अनुसार अंटार्कटिक क्षेत्र में ऊपर लगभग 3.50 वर्ग मील का एक 'ओजोन छिद्र' बन चुका है। ओजोन छिद्र के कारण तापमान पृथ्वी के सीधे धरातल पर पहुंचने के कारण पृथ्वी के वायुमण्डल के तापमान में काफी वृद्धि हो सकती है।

2. वैश्विक तापन में ओजोन गैस की भूमिकाः— पृथ्वी के वायुमण्डल के तापमान को बढ़ाने में एक दूसरी प्रकार की ओजोन का भी योगदान होता है। यह ओजोन वह है जो वायुमण्डल में निचले भाग में बनती है। इसका कारण मुख्य रूप से नाइट्रोजन के वे ऑक्साइड हैं जो वायुमण्डल के निचले भाग में आते हैं जिनके स्रोत हैं— पेट्रोल एवं कोयला जैसे ईधन। इसके अतिरिक्त मिथेन भी वायुमण्डल के निचले भाग में ओजोन के बनने में सहायक होती है।

3. वैश्विक तापन में परमाणु संयंत्रों की भूमिकाः— एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में परमाणु संयंत्रों से लगभग 10 लाख मेगावाट बिजली सम्पूर्ण विश्व में पैदा की जा रही है। आने वाले समय में इसमें व्यापक वृद्धि की सम्भावना है। सामान्यतः 500 मेगावाट के संयंत्र में प्रशीतन के रूप में प्रयोग होने वाले गर्म पानी को लगभग 3 सेमी0 मोटे और लम्बे घुमावदान पाइप से होकर ले जाया जाता है, तब अपेक्षाकृत ठंडा होने पर नदी या झील में चला जाता है। इससे आमतौर पर नदी या झील में 10—30° तक ताप में वृद्धि होती है।

4. व्यापक वन विनाश एवं वैश्विक तापनः— आधुनिक मानव द्वारा सम्पूर्ण विश्व में विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अविवेकपूर्ण ढंग से एवं अन्धाधुन्ध गति से वनों का विनाश किया जा रहा है। वर्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट के अनुसार 1950 से 1983 के मध्य अमेरिका के 38 प्रतिशत तथा अफ्रीका के 24 प्रतिशत वन समाप्त हो गये है। उष्णकटीबन्धीय सदाबहार वन, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, के विनाश से वायुमण्डल में CO_2 गैस की मात्रा में बड़ी वृद्धि हुई है।

5. वैश्विक तापन में सामान्य प्राकृतिक कारकों की भूमिकाः— बहुधा प्राकृतिक कारणों से भी पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होता है एवं इस परिवर्तन में उष्णता अथवा तापमान की स्थिति में परिवर्तन एवं वृद्धि भी सम्मिलित है। ज्वालामुखी उद्‌गार, वायुमण्डलीय वायु विसर्जन, संचयी वायुमण्डलीय प्राकृतिक दशायें, प्राकृतिक घटनायें, प्राकृतिक कारकों के अन्तर्गत आते हैं।[2]

वैश्विक ताप के संकेतः— निम्नांकित तथ्य वैश्विक ताप बढ़ने के संकेत देते हैं—

1. ऋतुओं का समय से पूर्व आगमन एवं फैलती बीमारियाँ।
2. जीवों और वनस्पति के क्रिया—कलापों में परिवर्तन।
3. पानी के ताप में वृद्धि, मूंगा भित्ति संकट में।
4. भारी वर्षा, बर्फबारी, चक्रवातीय तूफानों की बारम्बारता एवं अनावृष्टि।

जलवायु परिवर्तन के घातक दुष्परिणामः—

जलवायु के औसत तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु—बहाव आदि के दीर्घावधि के परिवर्तनों को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक कारको एवं मानव

जनित गतिविधियों से होता है। वायुमण्डलीय तापन वायुमण्डल के सबसे निचली परत जहाँ पर पृथ्वी की सभी मौसम सम्बन्धी घटनायें होती हैं, में औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक जलवायु पद्धति में परिवर्तन होते हैं।[3] जलवायु परिवर्तन के घातक दुष्परिणाम इस प्रकार हैं–

1. **पिघलते हिमनद एवं बढ़ता हुआ जल स्तरः–** वर्ड वाइड फंड फार नेचर (WWF) की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर प्रतिवर्ष 8 से 64 मीटर की दर से सिकुड रहे हैं। किलीमंजारों के ग्लेशियर 1910 से 2007 की अवधि के बीच लगभग 80 प्रतिशत पिघलकर गायब हो गये हैं। दक्षिणी एंडीज पर्वत में स्थित 'कटुलस्ख्या बर्फ टोपिया' 1960 के बाद 20 प्रतिशत पिघल चुकी है। IPCC के अनुसार 2005 की गर्मियों में आर्कटिक क्षेत्र में सबसे कम बर्फ पायी गयी। वास्तव में अब वैश्विक स्तर पर हिमनदों के अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है, जो वैश्विक स्तर पर चिन्ता एवं आशंकाओं को जन्म दे रही है।
2. सम्पूर्ण जैव जगत पर खतराः– सम्पूर्ण जैव जगत के अन्तर्गत वनीय परिस्थितिकी का विनाश, सागरीय जैव मण्डल का विनाश, मानव समुदाय पर खतरा, वैश्विक तापन के कारण मडराने लगा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का ठोस प्रमाण सन् 1988 से मिलना प्रारम्भ हुआ, विगत 40 वर्षों से पृथ्वी का औसत तापमान 0.5° सेल्सियस से 0. 7° सेल्सियस तक बढ़ा है, जबकि पिछले 30 वर्षों में कार्बन–डाईआक्साइड में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5° सेल्सियस से 4.05° सेल्सियस तक बढ़ने की सम्भावना है। बढ़ते तापमान के कारण सम्पूर्ण जैव जगत पर प्रभाव पड़ेगा। तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल गर्मी के कारण वाष्पित होगा, जिसके कारण वर्षा की मात्रा में 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी, वे क्षेत्र जो वर्तमान में शुष्क है, उनके हरे–भरे हो जाने की संभावना है, बाढ़ों की आवृति बढ़ेगी। कीट–पतंगों की नई प्रजातियां फसलों को रोगग्रस्त करेगी, उत्पादन घटेगा, अनेक प्रजातियां नष्ट हो जायेगी।[4]
3. वर्षण प्रतिरूप में परिवर्तनः– निरन्तर तापीय वृद्धि ने विश्व भर के वर्षण प्रतिरूप को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया है एवं भविष्य में इसके परिणाम निश्चित रूप से अत्यन्त कष्टप्रद हो सकते हैं। वैश्विक तापन के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में भी दिखने लगा है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि 2006–07 में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, एवं मुम्बई में हुई भारी वर्षा एवं कर्नाटक और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ा सूखा जलवायु परिवर्तन का ही दुष्परिणाम है। इसी प्रकार दक्षिण और मध्य अमेरिका में बारिश कम होने से जंगलों द्वारा कार्बन डाईआक्साइड

के आत्मसातीकरण की संभावना घटेगी। अटलांटिक समुद्र तट पर बाढ आयेगी, घास के मैदान छिन्न–भिन्न हो जायेंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, गल्फस्ट्रीम ज्यादा उग्र होगी। मछली उत्पादन एवं उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

4. वैश्विक ताप के कारण कृषि पर संकटः– विज्ञान पत्रिका नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व तापायन के कारण मृदा में कार्बन की मात्रा प्रतिवर्ष 0.6 प्रतिशत की दर से कम हो रही है। इंग्लैण्ड में किये गये एक अनुसंधान से पता चला है कि यहाँ कि मिट्टी से प्रतिवर्ष 40 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। दुनियां के सभी देश मिलकर लगभग 8 अरब मीट्रिक टन कार्बन सालाना छोड़ते हैं। बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी की नमी में कमी आ रही है। इन सबसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। साथ ही आने वाले समय में सिंचाई हेतु जल की अनुपलब्धता भी एक प्रमुख समस्या बनकर उभरेगी, क्योंकि सभी हिमनदों के पिघलकर विलुप्त होने के पश्चात नदियों का जल सूख जायेगा। प्रत्येक एक डिग्री सेग्रे0 तापमान बढ़ने पर गेहूँ का उत्पादन 4 से 5 करोड़ टन कम हो जाता हैं 2 डिग्री से0 तापमान वृद्धि से धान का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जायेगा। जलवायु परिवर्तन से केवल फसलों का उत्पादन ही नहीं उसकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अन्त में पोशक तत्वों और प्रोटीन की कमी पायी जायेगी, जिसके कारण संतुलित भोजन लेने पर भी मनुष्यों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।[5]

5. जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभावः– विश्व के तापमान में 0.7° सेल्सियस की दर से वृद्धि हो रही है। तापीय दबाव के कारण गरम हवा में तीव्र गति से वृद्धि एक खतरनाक प्रवृत्ति को संकेत दे सकी है। गर्म हवाओं से जो मृत्यु हो रही है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देशों में बाढ़ और सूखे की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है। इन देशों में पर्यावरण असन्तुलन के कारण, लोगों में बेचैनी और अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं। जिससे आत्महत्या और बच्चों के व्यवहार में असन्तुलन के मामलों में वृद्धि हो रही है। कैंसर एवं अल्सर जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। मच्छर, जूँ एवं मक्खियों की संख्या बढ़ रही है जिसके कारण विश्व के 10 देशों में मलेरिया रोगो का प्रकोप दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन रोगों के कारण प्रत्येक वर्ष एक से दो मिलियन लोगों की मृत्यु हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्वाइनफ्लू, डेंगू जैसे रोग महामारी का रूप धारण कर रहे है।[6]

जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण अवनयन की समस्या से निपटने के लिये किये गये अन्तराष्ट्रीय प्रयास

1.	1972	स्टाक होम सम्मेलन (UNEP) का गठन, 5 जून पर्यावरण दिवस घोषित।
2.	1985	ओजोन क्षरण पदार्थों पर वियना सम्मेलन।
3.	1988	आई0पी0सी0सी0 (IPCC) की स्थापना।
4.	1987	ओजोन परत संरक्षण के सन्दर्भ में मांट्रियल सन्धि।
5.	1990	(IPCC) की पहली रिपोर्ट – पिछली सदी में पृथ्वी का औसत तापमान 0.5 डिग्री. बढ़ा।
6.	1996	प्रदूषण कम करने पर पहली बार अमेरिका की सहमति।
7.	1997	क्योटो सन्धि, औद्योगिक देशों का 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5.4 प्रतिशत की कमी का वचन।
8.	1998	क्योटो सन्धि का पुनरावलोकन (ब्यूनस आयर्स में)।
9.	2001	अमेरिका द्वारा क्योटो सन्धि को मानने से साफ इंकार।
10.	2002	जोहान्सबर्ग में पर्यावरण एवं विकास पर पृथ्वी–10 सम्मेलन सम्पन्न।
11.	2002	यूरोपीय संघ एवं जापान समेत कई देशों ने क्योटो प्रोटोकाल की पुष्टि की लेकिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया शामिल नहीं।
12.	2004	रूस भी क्योटो प्रोटोकाल पर सहमत।
13.	2005	16 फरवरी, 2005 से क्योटो प्रोटोकाल प्रभावी। मांट्रियाल वार्ता जारी।
14.	2007	जून में जी–8 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गम्भीर वार्तालाप।
15.	2007	दिसम्बर 2007 में केविड रूड की नेतृत्त्व वाली आस्ट्रेलिया की सरकार ने भी क्योटो–प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये।
16.	2007	दिसम्बर 2007 में इण्डोनेशिया के बाली द्वीप स्थित नूसा–दुआ में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित।
17.	2009	डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में शिखर वार्ता से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं निकले। अगले 40 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयास होंगे। भारत एवं चीन आने वाले समय में बड़े कार्बन उत्सर्जक बनने जा रहे हैं ऐसे में सभी देशों को इस समस्या के हल पर विचार करना है। जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए अगले तीन वर्षों में करीब 30 अरब डालर विविध देशों को दिये जायेंगे।

वैश्विक तापन कम करने के उपायः–

1. सर्वप्रथम CO_2 का स्तर कम किया जाए।

2. बिजली के उपकरणों के अनावश्यक प्रयोग से बचा जाए।
3. ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता समुद्रों एवं वनों का बचाव आवश्यक है।
4. विभिन्न माध्यमों से कूड़ा–करकट आदि अपशिष्टों को कम किया जाए।
5. आम बल्बों के स्थान पर सीएफएल का प्रयोग किया जाए।
6. वनों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को विस्तृत पैमाने पर बढ़ाया जाये।
7. रासायनिक, नाभिकीय एवं अन्य औद्योगिक उत्सर्जन में कमी की जाये।
8. नागरिकों में जागरूकता बढ़ाई जाये।
9. समस्त राष्ट्र पर्यावरण बचाने हेतु सामूहिक प्रयास करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह–सविन्द्र (1991) पर्यावरण भूगोल, प्रकाशक, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, पृश्ठ 344।
2. परीक्षा मंथन : टैगोर टाउन इलाहाबाद, पृश्ठ 40।
3. डा0 रंजना दीक्षित एवं अभिषेक सारस्वत : (2009) वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रकाशित शोधपत्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, पृष्ठ 37।
4. सुनीता मेश्राम (2009) पृथ्वी का बढ़ता तापमान एक गंभीर समस्या–शोध प्रपत्र 31st इण्डिया ज्योग्राफी कांग्रेस, जबलपुर, पृष्ठ 40।
5. रमन प्रकाश, डा0 के0सी0 त्रिपाठी (2008) ''वैश्विक जलवायु परिवर्तन एवं उसका मानव जीवन पर प्रभाव'' एन्वायरमेंट इथिक्स एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट–डिपार्टमेन्ट आफ ज्योग्राफी डी0वी0एस0 कालेज, कानपुर, पृष्ठ 240।
6. नन्द किशोर राम (2009) ''जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव, एक समीक्षा''– बी0आर0सी0 न्यू मुजफ्फर नगर प्रकाशित शोध सारांश 315 इण्डियन ज्योग्राफी कांग्रेस, जबलपुर, पृष्ठ 37।

धीरे–धीरे के रास्ते पर चलकर मनुष्य, 'कभी नहीं' की मंजिल पर पहुँचता है।

परमाणु ऊर्जा और भारत की सुरक्षा

डॉ0 राम तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग,
वी0 एस0 एस0 डी0 कालेज, कानपुर

भारत के साथ अमेरिका का परमाणु करार करने का असली लक्ष्य भारत को विश्व के परमाणु क्लब देशों में शामिल करना था। इसके बदले में भारत अमेरिका सहित अन्य देशों के परमाणु हथियारों को वैधता प्रदान करेगा, यह अमेरिका की सोच थी। ''परमाणु करार विधेयक में दुर्घटना से क्षतिपूर्ति के लिए 1,500 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। जबकि विदेशों से आयातित 30,000 करोड़ रु0 की लागत वाले संयन्त्रों के हिसाब से यह राशि बेहद मामूली है।''[1] अगर परमाणु संयन्त्रों की दुर्घटना का आंकलन करें तो किसी भी परमाणु संस्थान का हाल सोवियत संघ के चेरनोबिल जैसा हो सकता है। चेरनोबिल की दुर्घटना में सैकड़ों लोग तो जहरीले विकिरण से ही मारे गये थे और दसों हजार लोगों ने कैंसर के अलावा प्रदूषित पर्यावरण के प्रभाव में आकर दम तोड़ दिया था। अनुमान है कि चेरनोबिल में 65 हजार से अधिक लोग परमाणु दुर्घटना के शिकार हुए थे।[2] यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत में यह नुकसान कम होगा।

अमेरिका और भारत के बीच अक्टूबर 2008 में असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। वास्तव में अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से भारत को तकनीक और परमाणु सामग्री की आपूर्ति तभी शुरू होने की बात थी, जब वही परमाणु दायित्व विधेयक के द्वारा एक कानून बना ले।

विवादित धारा[3] – 17 विधेयक की धारा 17 (बी) दुर्घटना में आपूर्तिकर्ता के दायित्व से जुड़ी है। यह विवाद परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को परिवहन के दौरान या इसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर था। विधेयक में आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदेह नहीं ठहराया गया था, लेकिन अब से संशोधित मसौदे के मुताबिक परमाणु संयन्त्र का संचालक आपूर्तिकर्ता से मुआवजा तब मांग सकेगा, जब (ए) उसके ऐसे अधिकारों का उल्लेख सौदे में लिखित रूप से हो, (बी) परमाणु दुर्घटना घटिया या खराब उपकरणों की आपूर्ति की वजह से हुई हो और (सी) परमाणु दुर्घटना किसी व्यक्ति या फर्म की मंशा या चूक के कारण हुई हो।

इस धारा की शब्दावली को लेकर भी विवाद उठा था। धारा 17 के उपबंध (अ) और (ब) के बीच 'और' शब्द को लेकर विवाद पैदा हुआ। विरोध के बाद सरकार ने 'और' शब्द को

निकाल दिया था, लेकिन 'इरादे' (Interest) शब्द को शामिल कर दिया। विपक्ष ने इस शब्द को यह कहकर विरोध किया कि परमाणु हादसे के सम्बन्ध में 'इरादा' शब्द के जिक्र से आपूर्तिकर्ता को उसकी जिम्मेदारी से बच निकलने का मार्ग मिल सकता है, क्योंकि इस तरह की किसी दुर्घटना में 'इरादा' साबित करना मुश्किल होगा। अब संशोधन के तहत 17 बी से यह शब्द भी हटा लिया गया है। यहाँ आपरेटर या संचालक 'न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया' होगी, जबकि अमेरिका की 'जीई' और 'वेस्टिंग हाउस' तथा फ्रांस की 'अरेवा' जैसी कम्पनियाँ आपूर्तिकर्ता होंगी।

इस विधेयक में परमाणु दुर्घटना हेतु मुआवजे की राशि भी विवादित रही, प्रारम्भ में इसके लिए विधेयक में संचालक को अधिकतम 500 करोड़ रु0 देने का प्रावधान था, लेकिन विपक्ष के आपत्ति के बाद इस राशि में वृद्धि कर इसे 1500 करोड़ रु0 कर दिया गया।

मुआवजे के लिए दावा करने की समय सीमा को लेकर भी सरकार और विपक्ष के बीच काफी मतभेद था। प्रारम्भ में यह समय सीमा 10 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा सी एस सी (कन्वेशन फॉर सप्लीमेंटरी कंपेनसेशन) भी एक विवादित विषय रहा। सी एस सी एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है। जिस पर हस्ताक्षर करने का तात्पर्य होगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दावाकर्ता सिर्फ अपने देश में मुआवजे का मुकदमा कर सकेगा। यानि दावाकर्ता को किसी अन्य देश की अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा।

अब तक भारत में हुई कुछ प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएँ [4] :

(1) 4 मई, 1987 – तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन भरते वक्त हादसा हुआ। इससे रिएक्टर का कोर क्षतिग्रस्त हुआ। दो वर्ष के लिए संयन्त्र को बन्द करना पड़ा।

(2) 10 सितम्बर 1989 – महाराष्ट्र के तारापुर में संयन्त्र से रेडियोधर्मी रिसाव हो गया। मरम्मत में एक वर्ष से ज्यादा समय लगा।

(3) 13 मई, 1992 – महाराष्ट्र के तारापुर में एक रिएक्टर में पाइप खराबी आने से 12 क्यूरी रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन हुआ था।

(4) 31 मार्च, 1993 – उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 'नरौरा' के रिएक्टर में विंड टरबाइन के पंखे आपस में टकराए और आग लग गयी थी। इसके बाद यह बिजलीघर साल भर बंद रहा।

(5) 13 मई, 1994 – कर्नाटक के कैगा में निर्माण कार्य के दौरान ही रिएक्टर का एक आंतरिक गुंबद गिर गया था, जिससे विकिरण का खतरा पैदा हुआ।

(6) 2 फरवरी, 1995 – रावतभाटा के परमाणु बिजलीघर से रेडियोधर्मी हीलियम और भारी जल रिसकर राणा प्रताप सागर नदी में पहुँच गया था।

(7) 26 दिसम्बर, 2004 – सुनामी की वजह से कलपक्कम के परमाणु बिजलीघर में पानी भर गया था। इसके बाद इसे बंद करना पड़ा था।

(8) 25 नवम्बर, 2009 – कैगा में अचानक परमाणु बिजलीघर के कर्मचारी बीमार पड़ने लगे। जाँच के दौरान पता लगा कि 92 लोगों के मूत्र में ट्रीटियम था। इन सभी लोगों ने पानी ठंडा करने वाले कूलर से पानी पी लिया था। बाद में पता चला कि किसी कर्मचारी ने इस कूलर में भारी जल भर दिया था।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बूते भारत अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट को आने वाले दो दशकों में 63,000 मेगावाट करेगा। हालांकि यह स्थिति सशंकित है। वैसे इन संयन्त्रों में से कुछ की संयुक्त उत्पादन क्षमता 10,000 मेगावाट की है, जो कि कुछ सौ मेगावाट क्षमता वाले पहले से कार्यरत संयन्त्रों से बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा भयानक स्थिति यह है कि परमाणु संयन्त्रों के लिए जिन जगहों का चयन हुआ है, वे सब भूकंप आशंकित क्षेत्रों में आते हैं। इनमें से कुछ तो सुनामी की जद में भी आ सकते हैं।

प्रश्न यह है कि हमारे परमाणु ऊर्जा संयन्त्र के सुरक्षा रिकार्ड अब तक क्या रहे हैं। वैसे अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन कई छोटे–छोटे हादसे भारत के परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा सयन्त्रों की जगह में एक महाराष्ट्र का तटीय इलाका जैतापुर भी है। फ्रांस की कम्पनी अरेवा की सहायता से यहाँ कई रिएक्टर लगेगें, जिसकी संयुक्त क्षमता 10,000 मेगावाट की होगी। लेकिन ''पिछले 20 वर्षों में इस क्षेत्र में 92 भूकंप के झटके महसूस किये गये हैं। सन् 1993 ई0 में भूकंप के झटके की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.2 के आस–पास रही।''[5] इस क्षेत्र को भूकंप के दृष्टिकोण से जोन – 3 से जोन – 5 के बीच चिह्नित किया गया है, जो कि खराब श्रेणी है। साथ ही पठार पर इस जगह के चुनाव के बावजूद सुनामी की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शायद इसी का ख्याल रखते हुए, इस परियोजना में निवेश कर रहे जर्मनी के कार्मस बैंक ने जापान में आए संकट से पहले ही इस योजना पर सवाल उठाते हुए हाथ खींच लिए।

दूसरी विवादास्पद जगह गुजरात के सौराष्ट्र तट पर मिथी विरदी है। यहाँ जीई की सहायता से अमेरिकी रिएक्टर स्थापित होगा और इसकी संयुक्त उत्पादन क्षमता 8,000 मेगावाट होगी। परन्तु यह बात सोचनीय है कि इस जगह का चुनाव क्यों किया गया। सौराष्ट्र का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र –3 में पड़ता है। इसके कुछ भागों ने वर्ष 2001 को भयंकर भूकंप को झेला था; जिसमें वृहत स्तर पर जन–धन की हानि हुई थी। लोगों ने इन दोनों जगहों का विरोध किया था। 'आंध्र प्रदेश' के श्री काकुलम तट से सटे कोवाड मत्स्यलेसम (जहाँ दस हजार मेगावाट की परियोजना प्रस्तावित है) की भी यही स्थिति है। आश्चर्य का विषय यह है कि गैर सामरिक ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम पर भी गोपनीयता दर्शायी जा रही है।

परमाणु निशस्त्रीकरण और शांति संधि के समन्वयक **'विल्फ्रेड डि–कोस्टा'** के अनुसार – ''भारत में परमाणु ऊर्जा को पर्यावरण सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। जबकि यह कानून दूसरे ऊर्जा उत्पादक संयन्त्रों पर लागू है। सूचना का अधिकार कानून भी इस पर लागू नहीं होता है। सबसे विषम यह है कि परमाणु मामलों में सरकारी गोपनीयता कानून लागू है।''[6] भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष 'पी0 के0 अयंगर' के अनुसार – ''भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक 400 मेगावाट के दायरे में भारी जल संयन्त्रों को बनाया और चलाया भी। लेकिन नये निर्यातित संयन्त्रों की अब तक जाँच नहीं हुई है और वे 1600 मेगावाट के बड़े स्केल में हैं।'' इसलिए सरकार को सलाह है कि एकाएक 400 मेगावाट से 1600 मेगावट की छलांग न लगाए और इस तरह के 6 रिएक्टरों को एक साथ एक जगह लगाने से भूकंप और सुनामी में वृहतस्तर पर जन हानि हो सकती है। उनके अनुसार इस तरह के कदम उठाने से पूर्व कई प्रकार के बुनियादी ढाँचों की सुरक्षा का मूल्यांकन जरूरी है।

विश्व के सभी बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत हैं कि परमाणु शक्ति को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना असम्भव है। यदि 'भूकम्प' और 'सुनामी' नहीं होंगे, तो आग हो सकती है। मानवीय लापरवाही हो सकती है, आतंकवाद हो सकता है तथा और कुछ नहीं तो किसी सत्तारूढ़ नेता का पागलपन हो सकता है। अतः हर परिस्थिति में परमाणु शक्ति 'जुआ' है। अगर हम इसके बिना काम चला सकते हैं, तो ऐसा भयानक 'जुआ' क्यों खेले? जिसका असर आने वाली पीढ़ियों (जनमानस) को भुगतना पड़े।

संदर्भ

1. www.SATP.org, website, 15 Feb, 2011.
2. इण्डिया टुडे – 15 दिसम्बर, 2010
3. द टाइम्स ऑफ इण्डिया – 3 जनवरी, 2011
4. राष्ट्रीय सहारा – 26 मार्च, 2011
5. आउटलुक – 1 अप्रैल, 2011
6. www.SATP.org. website - 4 April, 2011

मादक पदार्थ आधारित आतंकवाद में अफगानिस्तान की भूमिका

विशाल दुबे
शोध छात्र
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

भूमिकाः– आतंकवाद ने वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक ज्वलंत व मुख्य समस्या के रूप में उभर कर अपनी उपस्थिति प्रकट की है। वर्तमान समय में आतंकवाद का दंश कई राष्ट्रों ने महसूस किया है। भारत ने विगत कई वर्षों से राज्य प्रायोजित आतंकवाद तथा चीन की विद्वेषपूर्ण नीति से समर्थित माओवाद व उग्रवाद का सामना किया है। जबकि 11 सितम्बर 2001 की घटना को पश्चिमी राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता पर संकट मान कर, इसे आतंकवाद की अन्य घटनाओं से अलग व महत्वपूर्ण सिद्ध करते हुये, आतंक के विरूद्ध कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं।

आतंकवाद में मादक पदार्थ एक ऐसे आयाम के रूप में सामने आया है। जिसने आतंकवाद को पोषण देकर अर्न्तराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संकट पैदा किया है।

मादक पदार्थ आधारित आतंकवादः– मादक पदार्थ आधारित आतंकवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मादक पदार्थ की बिक्री कर प्राप्त धन से आतंकवाद या आतंकी गुटों की सहायता की जाती है। ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी गुटों से लेकर किसी भी शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री में अवैध रूप से संलग्न लोग शामिल रहते है, जिनके उपभोक्ता आम नागरिक होते है जिन्हें नशें की आदत लगी होती है। मादक पदार्थो की बिक्री में धीरे–धीरे शक्तिशाली व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप आरंभ हो जाता है जो लाभ की इच्छा से कार्य करते है। इसके अलावा मादक पदार्थों की बिक्री तथा उसके धन की व्यवस्था में हवाला या मनीलांड्रिग का भी आगमन हो जाता है। धीरे–धीरे वो गुट जो राष्ट्रों को आतंरिक रूप से कमजोर करना चाहते है पर्दे के पीछे रहकर अपना हित साधने में संलग्न रहते है।

अफगानिस्तान की भूमिकाः– अफगानिस्तान एक ऐसा इस्लामी राष्ट्र है जहां पर कबीलों व गुटों में जनता बंटी हुयी है। अफगानिस्तान एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास का साक्षी

रहा है, जहाँ पर शासन करना खतरों से खेलना है। वहाँ के निवासियों के लिये अपने कबीले या गुट ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जहीर शाह के बाद वहाँ कोई शासक स्थायी न रहा तथा सभी को विरोध का सामना करना पड़ा। 1979 में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ उससे इस देश के भाग्य का सितारा ही रूठ गया। सोवियत हस्तक्षेप के विरोध के लिए अमेरिका व पाकिस्तान ने युवाओं को तैयार किया जो कि अफगानिस्तान के ही निवासी थे तथा जिन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किया गया था तथा उन्हें अमेरिकी समर्थन प्राप्त था, जिन्हें मुजाहिदीन कहा गया था। युद्ध की खर्च प्राप्ति हेतु इन्हीं मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान में अफीम की कृषि शुरू की, जिसे पाकिस्तान के द्वारा सम्पूर्ण विश्व में भेजा जाता। आरंभ में ये एक ऐसा खेल था जो अत्यधिक धन लाभ देता रहा साथ ही ऐसी व्यवस्था से संघर्ष का खर्च निकलता रहा जिससे पाकिस्तान व अमेरिका पर भी अत्यधिक बोझ न पड़ा। सोवियत संघ की पराजय, उसके अफगानिस्तान से वापस जाने तथा शीत युद्ध की समाप्ति के उपरान्त, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को उसके हालात पर छोड़ दिया। जबकि अमेरिका इस तथ्य को भूल गया कि अफगानिस्तान को हथियार, मादक पदार्थ के द्वारा लंबा संघर्ष कर महाशक्ति को हराने का ज्ञान हो गया। अफगानिस्तान में कालांतर में तालिबान का अधिपत्य हो गया जिसे मात्र गिनती के राष्ट्रों की ही मान्यता थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिकार के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सहयोगी के रूप में सामने आया जो पाकिस्तान के लिये आतंक के लिये आवश्यक भंडार गृह की तरह था। अफगानिस्तान एक ऐसे रूप में सामने आया जो पाकिस्तान व मुल्ला उमर के इशारों पर चलता जो मादक पदार्थों का सुरक्षित केन्द्र था तथा जहाँ की नीति जेहाद तथा इस्लाम की वृद्धि थी।

इस्लाम की नीतियों की गलत विवेचना तथा उसके पालन के कारण धीरे–धीरे अफगानिस्तान के उद्योग धंधे तथा शैक्षिक वातावरण बर्बाद हो गया। कृषक किसी अन्य उपयोगी फसल की अनुपस्थिति के कारण अफीम की ओर ध्यान देने लगा उसका उन्हें अच्छा मूल्य भी मिलने लगा।''अपने कंधार शासन के प्रथम वर्ष के समय तालिबान ने एक पुस्तक के द्वारा ये बताया कि क्या–क्या प्रतिबंधित है, संगीत, टी0वी0, शराब आदि प्रतिबंधित थे। जबकि अफीम के उत्पाद का प्रयोग करने से रोका गया था जबकि आश्यर्यजनक तथ्य ये है कि अफीम का उत्पादन तथा व्यापार प्रतिबंधित नहीं था।'' इसका सामान्य कारण था कि इस्लाम में नशा करना प्रतिबंधित है और बिना इसकी कृषि के तालिबान का खर्च चल पाना मुश्किल था। ये एक उदाहरण था कि इस्लाम कि किस प्रकार विवेचना की गयी कि अफगानिस्तान में

उपयोग न हो तथा इस अवैध कार्य से धन लाभ भी होता रहे। ''मार्च 1995, में प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार तालिबान चमन सीमा की आवाजाही से ही प्रतिदिन +1,50,000 की धन वसूली कर लेता था।''

''बर्नाड फ्राही, जो कि यू0एन0ओ0डी0सी0 के अधिकारी थे, के अनुसार तालिबान उश्र के नाम पर 10 प्रतिशत कर अफीम व अन्य उत्पादकों से लेता था। उश्र कृषि के आधार पर लेकर बाद में स्थानीय जगह पर खर्च किया जाता था।'' इसके अलावा भी अन्य स्थानों से भी तालिबान द्वारा कर वसूला जाता जो बाद में आतंक को ही मदद करता था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अफीम की कृषि करने वालों से कर लिया जाता था, सीमा की आवाजाही पर भी कर लेते थे जबकि वो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस व्यापार द्वारा धन कमाते जिसका अंततः प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में होता था। इसके साथ साथ राज्य के जो भी आवश्यक अंग होते हैं वो भी आतंक को बढ़ावा देने में संलग्न थे। तालिबान की छत्रछाया के कारण ही लादेन ने अफगानिस्तान को अपने गतिविधि का केन्द्र बना लिया। अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिये अपने स्तर से हरसंभव सहायता प्रदान की। पाकिस्तान के प्रत्येक सहयोगी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान की सहायता की। ये भी महत्वपूर्ण है कि कई बार हमें ये तथ्य मिलता है कि किस प्रकार पाकिस्तानी सेना हिरोइन के द्वारा आतंकी गतिविधि की सहायता करना चाहती थी तथा इसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार था। वास्तव में ऐसा इसलिये था क्योंकि अफगानिस्तान में अनवरत अफीम की अच्छी पैदावार जारी थी। जबकि पाकिस्तान की पैदावार अत्यधिक कम थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आपको एक ऐसे मार्ग के रूप में स्थापित किया था जहां से हिरोइन की आवाजाही होती थी।

वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2007 व 2010 के अनुसार निम्न सारणी से अफगानिस्तान–पाकिस्तान की अफीम की पैदावार अधिक स्पष्ट हो जाती है–

उत्पादन (मीट्रिक टन में)

वर्ष	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
अफगानिस्तान	2335	2248	2804	2693	4565	3276	185	3400	3600	4200	4100	6100	8200	7700	6900
पाकिस्तान	112	34	24	26	9	8	5	5	52	40	36	39	43	48	44

अगर हम निम्न सारणी पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की अफीम उत्पादन काफी कम है जबकि उसकी तुलना में अफगानिस्तान का उत्पादन अधिक है। चूंकि 2011 में 2010 की ही रिपोर्ट आयी है इसलिये 2010 की वास्तविक स्थिति 2012 में प्रकाशित होने वाली 2011 की रिपोर्ट में आयेगी।

पाकिस्तान की अफीम निम्न श्रेणी की होती है जिसे वो अफगानी बता कर विक्रय करता हैं यही नहीं अफीम तथा हिरोइन को अफगानिस्तान व पाकिस्तान में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि उसी के द्वारा आतंक, हवाला, अफगानी गुटों की अर्थव्यवस्था पाकिस्तानी सेना का अधिकांश खर्च आदि निकलता है। जो कबीले के सरदार इस धंधे में सहयोग देते हैं उन्हें समय समय पर बहुमूल्य उपहार भी मिलते रहे। ''मीर वाइज यसीनी जो अफगानिस्तान के काउन्टर नारकोटिक्स डायरेक्टोरेट के प्रमुख थे, के अनुसार, तालिबान एवं उसके गठबंधन के संगठनों ने वर्ष 2003 में +1100 मिलियन कर के रूप में प्राप्त किये थे।'' ये भी सूचना थी कि ''पेशावर में अल–कायदा से सम्बन्धित लोग हर दो माह में हिरोइन की 4400 पौंड की आपूर्ति प्राप्त करते थे।'' जो उनके तथा उनके संगठन हेतु अमृत के समान थी।

भारत पर भी मादक पदार्थों का अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा, एक ओर तो भारत का युवा वर्ग मादक पदार्थों का सेवन करने लगा जिसके कारण भारत का धन बड़ी मात्रा में विदेश जाने लगा तथा इसके कारण एक ऐसा वर्ग आया जो इसका अवैध व्यापारी था तथा उसका सम्बन्ध कहीं न कहीं से विदेश से था। काला धन, हवाला आदि भी प्रभावी ढंग से अपनी छाप छोड़ने लगे। इसके साथ–साथ जैसे जैसे अफीम की अफगानिस्तान में पैदावार बढ़ती गयी तो उसके फलस्वरूप पाकिस्तान अफगानिस्तान को धन मिलने लगा, जिसके कारण भारत पर आतंकी संकट मंडराने लगा। तथ्य सिर्फ ये नहीं है कि अफीम या हिरोइन के प्रति अफगानिस्तान के गुटों तथा पाकिस्तान की निष्ठा है, बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इससे भारतीय सुरक्षा एवं वैश्विक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा।

अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति– वर्तमान में अफगानिस्तान की स्थिति अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रही है। विश्व समुदाय आज भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आने वाले समय में क्या होगा। जब तक हम सिर्फ अफगानिस्तान को अलग करके देखेंगे तो हमें समस्या का हल नहीं दिखेगा, वहां की समस्या का वास्तविक हल अमेरिका व पाकिस्तान की शुभेच्छा पर निर्भर करता है, जिनके कारण अफगानिस्तान के ये हालात बनें। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि एबटाबाद में अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गयी कार्यवाही में, ओसामा की हत्या ने ये तथ्य सामने ला दिया, कि दुनिया का ये दुर्दांत आतंकी पाकिस्तान में था। जबकि पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंक विरोधी होने का ढोल पीट रहा था। कथनी व करनी का क्या फर्क हो सकता है उसका उपयुक्त उदाहरण पाकिस्तान है। ओसामा का वहां कई वर्षों से निवास करना सिद्ध करता है कि ओसामा ने वहां से अपना संचालन कार्य भी किया होगा और पाकिस्तानी सेना व सत्ता प्रतिष्ठान का ये कथन कि उन्हें ओसामा का पता नहीं था मेरे अनुसार, सिर्फ विश्व समुदाय को उलझाना है।

ओसामा के अंत से अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने का बहाना मिल गया कि वो जिस उद्देश्य से आये थे उनमें अधिकांश पूरे हुये व ओसामा बिन लादेन भी मारा गया, परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अफगानिस्तानी सुरक्षा बल क्या अफगानिस्तान की सुरक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है। वास्तव में वहां की सेना अभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। अमेरिका ने इस बात की घोषणा कर दी है वो चरणबद्ध तरीके से अफगानिस्तान छोड़ देगा। इसके बावजूद अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले नहीं रुक रहे तथा आतंकी महत्वपूर्ण इमारतो या व्यक्तियों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे, अभी हाल में ही काबुल में होटल लैडमार्क इंटरकांटिनेंटल पर हमला किया गया, जब काबुल की ये हालत है तो कैसे ये आशा की जाये कि शेष अफगानिस्तान सुरक्षित होगा।

इसके अलावा अफगानिस्तान में अफीम की खेती में कोई अत्यधिक गिरावट नहीं आयी हैं विचार का विषय ये है कि 2001 में जो उत्पादन मात्र 185 टन था वो अमेरिकी आक्रमण के बाद बढ़ता गया, जबकि 2008 में व 2009 में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आयी फिर भी वो वर्ष 2000 के स्तर तक नहीं पहुँचा है। ये हालात नाटो सेना की उपस्थिति में है। इसके साथ पाकिस्तान को भी मादक पदार्थों की आवश्यकता है।

इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य ये है पाकिस्तान में भी लगभग आये दिन आतंकी हमले सुनाई पड़ रहे हैं। करांची में नौ सेना अड्डे पर हुये हमले ने वहां की सुरक्षा के हालात स्पष्ट कर दिये हैं। अब जबकि उक्त हालात हो तो प्रश्न ये है कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, निस्संदेह रूप से ये भविष्य के गर्भ में छिपा प्रश्न है परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत को मिलकर अफगानिस्तान को अपने पैर पर चलना सिखाना होगा वरना अमेरिका के वहां से जाने के बाद पाकिस्तान पुनः उसे अपना अघोषित उपनिवेश या आतंक की पाठशाला बनाना चाहेगा।

अफगानिस्तान के लिये अतिआवश्यक ये है कि उसे रोजगारोन्मुखी वातावरण देकर वहां के लोगों को आतंक से दूर करे, इसके साथ वहां की अफीम की खेती में कमी लायी जाये तथा ये कमी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में भी आनी चाहिये। इसके अलावा भारत को और अधिक सहायता देनी होगी वरना अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ने का खामियाजा भारत को भुगतना ही पड़ेगा। इसके साथ विश्व जगत को वहां पर सार्थक रूप से लोकतंत्र लाने का प्रयास करना होगा जिसमें एक मजबूत विपक्ष हो जिससे कि जनता की भागीदारी अधिक हो साथ ही विरोध बंदूक से नहीं बल्कि वोट के द्वारा स्पष्ट हो।

निष्कर्ष– निस्संदेह रूप से अफगानिस्तान की मादक पदार्थ आधारित आतंकवाद में स्पष्ट भूमिका रही है। अमेरिका के वहां से वापस जाने की घोषणा के बाद ये विचारणीय विषय है कि अब अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होगा व किस प्रकार वो पाकिस्तान की कुटिल चालों से अपने को बचायेगा। निस्संदेह रूप से वर्ष 2001 से अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान में स्थायित्व व सुरक्षा दो बड़े प्रश्न थे परंतु अब वहां शक्ति निर्वात आने की संभावना है उससे अफगानिस्तान को किस प्रकार निपटना है ये तो अफगानिस्तान को स्वतः विचार करना होगा परंतु इस कार्य में विश्व को, विशेष रूप से भारत को, अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी।

सन्दर्भ सूची

1. Peters, Gretchen., Seeds of Terrorism, Gopsons Papers Ltd. NOIDA 2009.
2. Peters, Gretchen., Seeds of Terrorism, Gopsons Papers Ltd. NOIDA 2009.
3. Peters, Gretchen., Seeds of Terrorism, Gopsons Papers Ltd. NOIDA 2009.
4. उपर्युक्त पीटर्स ग्रीचेन को मीर वाइज यसीनी द्वारा ई–मेल पर दिये गये 16 अक्टूबर 2007 के साक्षात्कार के आधार पर।
5. Sly, "Opium Cash Fuels Terror, Experts say." Price calculated from UNODC's world drug report, http;.//www. unodc.org/pdf/WDR_2006/wdr 2006_ chap5_ opium. pdf.

भय तभी तक व्यक्ति पर हावी रहता है, जब तक वह उससे डरता है, लेकिन जब वह जूझने के लिए कमर कस लेता है, तब भय स्वयं भयभीत हो जाता है।

मानवाधिकार : सतत संघर्षों से प्राप्त अधिकार

–डॉ0 शशि शेखर मिश्र (प्रवक्ता संस्कृत)
श्री जनता इण्टर कालेज, अजीतमल (औरैया)
E-mail : atinmishra.mishra@gmail.com
shashi.mishra29@yahoo.com

मानवाधिकार अर्थात मानव के नैसर्गिक अधिकार अथवा मनुष्य के ऐसे अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य को जन्मतः प्राप्त होते हैं। सामाजिक जीवन की वे दशाएँ जो मानव को समाज एवं विधिसम्मत कार्यों को निष्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें मानवाधिकार कहलाती हैं। मनुष्य प्रकृति की अनुपम कृति है प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है इस सम्बन्ध में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नितान्त अनुचित है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवनमूल्यों तथा आदर्शों का मूलाधार मानव ही है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम जीवन्त संस्कृति है। इस संस्कृति ने सदैव ही न केवल मानव अपितु प्राणिमात्र के कल्याण की कामना की है। वेदों में समस्त संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक कल्याण एवं समस्त प्राणिमात्र को अभय की कामना की गयी है–

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरू।
शं नः कुरू प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः।।[1]

'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसी विश्व मानवतावादी विचारधाराओं का उद्‌गम एवं विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ईशावास्योपनिशद् में सर्वप्रथम हमने ही विश्व के कण कण में व्याप्त परमात्मा का निरूपण किया।[2] इस प्रकार के विचारों से ही कालान्तर में सर्वात्मवादी दर्शन का विकास हुआ जिसमें संसार के समस्त पदार्थों में आत्मा का वास मानते हुये किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का निषेध किया गया। किसी को पीड़ित करने को महापाप की संज्ञा दी गई है–

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।[3]

जैन दर्शन परम अहिंसावादी था। इसमें जीवों के प्रति मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से अहिंसा का आचरण करने का निर्देश दिया गया है।[4] हापकिन्स महोदय का विचार है कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धान्त है कि ईश्वर के अस्तित्व को न मानकर, मानव की पूजा करो तथा जीवों का संरक्षण करो।[5] बौद्ध धर्म भी मानव मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। सम्राट

अशोक ने जीव हत्या निषेध की बात अपने प्रथम शिलालेख में की है। अशोक के पंचम शिलालेख में अधिकथित सर्वधर्मसमभाव, सभी वर्गों के लोगों की सहायता तथा बन्दियों के विमुक्तिकरण का जो वर्णन है वह वर्तमान कालीन प्रचलित मानवाधिकार की अवधारणाओं के सर्वथा अनुरूप है। उपर्युक्त विवेचन का आशय मात्र इतना है कि भारत में आदि काल से मानवाधिकार की स्वस्थ परम्परा विद्यमान रही है जो अद्यावधि अक्षुण्ण है।

पाश्चात्य देशों में मानवाधिकरों को लेकर आधुनिक युग के आरम्भ में चेतना का संचार हुआ। मध्यकालीन सामंतवादी युग में यूरोपीय देशों में व्यापक स्तर पर समाज में विभेद प्रचलित था। विशेषतः लघु कृषकों एवं अर्धदासों की स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय थी। अठारहवीं शताब्दी में विचारकों ने मानव की स्वतंत्रता पर बल देना आरम्भ कर दिया था। रूसो ने अपनी पुस्तक ''सोशल कान्ट्रेक्ट'' में स्पष्टतः लिखा है कि, ''मानव स्वतंत्र जन्मा है किन्तु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है।''[6] रूसो का यह वाक्य तत्कालीन यूरोप की सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध आधुनिक समाज का युद्धघोष बन गया। अमरीका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र (1776) में मनुष्य के जन्मजात् एवं अहस्तान्तरणीय अधिकारों का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। इन अधिकारों में जीवन की स्वतंत्रता तथा सुख शान्ति के अधिकार भी सम्मिलित हैं। फ्रांस में राज्यक्रान्ति के पश्चात् मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा (Declaration of the Right of Man) ने मानव की स्वतंत्रता समानता तथा बन्धुत्व का संदेश समग्र विश्व को दिया।

यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में सामंतवादी शोषण का स्थान पूँजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण ने ग्रहण कर लिया था। ऐसी परिस्थिति में समाजवाद का अभ्युदय हुआ। यद्यपि थॉमस मूर ने 1516 ई0 में यूटोपिया नाम पुस्तक में आदर्श काल्पनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जिसमें पूँजीवाद के दुष्परिणाम असमानता एवं शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया का स्वर मुखरित हुआ तथापि समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन द्वारा 1833 में पुअर मैन्स गार्जियन (लंदन) नामक पत्र में किया गया। ओवेन ने उत्पादन कार्यों में श्रमिकों के प्रति मानवतापूर्ण स्थितियाँ लागू करने पर बल दिया। अन्य आरम्भिक समाजवादी विचारकों में सेंट साइमन तथा चार्ल्स नेपियर प्रमुख थे इन्होंने भी पूँजीवादी शोषण का विरोध किया। कालान्तर में समाजवाद का विकास फेबियनवाद के रूप में हुआ। 1884 में इंग्लैण्ड में सिडनी वेब, जॉर्ज बर्नाड शॉ, एनी बीसेण्ट, एच.जी. वेल्स आदि ने फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। समाजवाद के अभ्युदय ने मानवाधिकार संघर्ष को नवीन आयाम प्रदान किये। समाजवादी चितन्क मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन था। जिससे समाज में विद्यमान असमानता का अन्तकर एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सके।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम समय में कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स की रचनाओं ने क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रवर्तन किया जो शोषणमुक्त आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखती थी। मार्क्स का विचार था कि मनुष्य का इतिहास प्रारम्भ से ही एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का इतिहास रहा है।[7] जिसमें सुविधाभोगी वर्ग और सुविधाविहीन वर्ग का संघर्ष उद्घोषित होता है। एक ओर श्रमिकों का निरन्तर शोषण होता है वहीं दूसरी ओर पूँजीपति वर्ग उसी शोषण पर निरन्तर फलता फूलता है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के आधार पर ही 1917 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ तथा 1949 में चीनी गणराज्य का उदय हुआ।

समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के विपरीत यूरोप में दक्षिणपंथी विचारधारा का विकास भी तीव्र गति से हुआ। इस विचारधारा का प्रयोग पूँजीपति शक्तियों ने विभिन्न देशों में पनप रहे समाजवाद एवं साम्यवाद के अंकुर को दबाने तथा अपने नियंत्रण को बनाये रखने हेतु किया। परिणामतः विभिन्न देशों में उग्र राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद का उदय हुआ। जिससे प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका उत्पन्न हुयी। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् आयी विश्वव्यापी मंदी से उत्पन्न भूख एवं बेरोजगारी तथा पराजित राष्ट्रों में व्याप्त क्षोभ ने जर्मनी में नाजीवाद तथा इटली में फांसीवाद के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। परिणामतः विश्व को अत्यन्त अल्पकाल में ही द्वितीय विश्वयुद्ध की त्रासदी झेलनी पड़ी। इस युद्ध ने जनसंहार के सभी पुराने रिकार्डों को ध्वस्त कर दिया। देशद्रोह का आरोप लगाकर अपने लाखों विरोधियों को जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी ने मौत के घाट उतार दिया। हिटलर ने प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण यहूदियों को बताकर लाखों की संख्या में उनका संहार करवा दिया। जापान ने जर्मनी की ओर से युद्ध करते हुये पूर्वी एशिया में अपना नियंत्रण स्थापित किया तथा इन स्थानों के निवासियों पर अभूतपूर्व अत्याचार किये।

भारत में भी मौर्य काल के पश्चात मुद्रा प्रसार तथा केन्द्रीय नियंत्रण के शिथिलीकरण ने सामन्तवाद के उत्पन्न किया जिससे कालान्तर में श्रेणी सामन्तवाद का उदय हुआ परिणामतः समाज में व्यापक स्तर पर विषमताओं का जन्म हुआ। जिस जाति प्रथा का जन्म व्यावसायिक दक्षता के लिये हुआ था वह सामन्तीयुग में शोषण का मूलाधार सिद्ध हुयी किन्तु जातिगत विषमताओं के पश्चात् भी समाज के सभी वर्ग शेष विश्व से उन्नत अवस्था में अपना जीवन यापन करते रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बंगाल विजय के पश्चात् इस स्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन आया। कम्पनी शासन ने भारत में ब्रिटिश संस्थाओं बिना किसी दूरगामी चिन्तन के थोपा[8] जिससे भारत में घोर सामाजिक असमानता एवं शोषण के युग का आरम्भ

हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त के बनारस खण्ड तथा उत्तरी कर्नाटक में स्थायी जमींदारी पद्धति अपनायी गयी जिसमें उन्होंने जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना परिणामतः कृषकों की स्थिति यूरोपीय अर्धदासों के समान हो गयी।[9] वे अपने स्वामी की कृपा पर आश्रित हो गये फलस्वरूप भारत में दीर्घावधिक वर्ग संघर्ष का उदय हुआ। महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी भू धृति पद्धतियाँ भी स्थानीय स्तर पर लागू करने वालों की न्यूनताओं से असफल सिद्ध हुयीं। इन भू धृति पद्धतियों के कारण भारतीय ग्रामीण कुटीर उद्योग धन्धों का पतन हो गया।[10] 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में भारतीय ग्राम्य समाज का असंतोष भी महत्वपूर्ण कारक था। बीसवीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी वैश्विक समाजवादी आन्दोलन से अस्पृष्ट नहीं रही। कांग्रेस के अनेक अधिवेशनों में नागरिक अधिकारों की मांग की गई। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में वयस्क मताधिकार तथा मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये गये। कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की भी मांग की। कालान्तर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन सभी मांगों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया। जिसमें नागरिकों को संविधान के भाग तीन के अन्तर्गत समता का अधिकार (अनु0 14–18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 19–22), जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 21), निरोध से संरक्षण (अनु0 22), मानव शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु0 23, 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 25–28), अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार (अनु0 29–30) तथा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार (अनु0 32) प्रदान किये गये। ये अधिकार अत्यन्त व्यापक थे परिणामतः इनका प्रभाव समग्र विश्व पर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र भी इनसे अप्रभावित नहीं रह सका।

द्वितीय विश्वयुद्ध की त्रासदी झेल रहे विश्व में 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा जारी की। उसी समय से प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मानवाधिकारों के इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। इसके अतिरिक्त आरम्भ में एक व्यापक प्रस्तावना है। प्रस्तावना में वैश्विक स्वतंत्रता न्याय तथा शांति की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अनुच्छेद 1 तथा 2 में मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुत्व की भावना पर बल दिया गया है। इनमें जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, सम्पत्ति, जन्म, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 3, 4 तथा 5 में प्राविधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का दास नहीं होगा तथा किसी के साथ क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं

किया जायेगा। अनुच्छेद 6–11 तक विधि के समक्ष समता, समान विधिक संरक्षण, बंदीकरण तथा निर्वासन से मुक्ति तथा किसी अभियोग के लगाये जाने हेतु उचित विधिक प्रक्रिया के अनुपालन जैसे विषयों का वर्णन है। अनुच्छेद 18–20 तक विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 22 से 27 तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 तथा 30 में समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया गया है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया यह घोषणापत्र कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है अपितु यह 'मानवता का मैग्नाकार्टा' है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने समय–समय पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी पारित कर मानवाधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन कानूनों में रंग भेद की समाप्ति, महिलाओं के अधिकार, शिशुओं के अधिकार आदि विषय सम्मिलित किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार संरक्षण हेतु पारित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कानून अधोलिखित हैं–

1. सामूहिक नरसंहार अपराध निवारण एवं दंड हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून 1951
2. समस्त प्रकार के भेद भाव समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून 1966
3. रंगभेद निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून 1973
4. महिला के प्रति भेदभाव समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून 1979
5. शिशु अधिकार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून 1989

उपर्युक्त कानूनों के अतिरिक्त वर्ष 1975 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की निन्दा करते हुये इसे अमानवीय माना गया। नस्लवाद का विरोध भी संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख लक्ष्य रहा है। वर्ष 1993 से 2003 तक के दशक को नस्लवाद विरोधी दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। महिला अधिकारों के संरक्षण पर बल देते हुये वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव महासभा ने पारित किया। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु भी महासभा ने अनेक प्रयास किये हैं। इससे सम्बन्धित देशज लोगों के अधिकारों हेतु 1990 में एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 1993 को देशज लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया।

भारत ने भी सदा मानवाधिकारों के संरक्षण का ही प्रयास नहीं किया है अपितु इस सन्दर्भ में उसने अग्रणी भूमिका का भी निर्वहन किया है। भारत सरकार ने सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति ने वर्ष 1993 में एक अध्यादेश जारी कर किया था। इसे वर्ष 1994 में अधिनियम पारित कर व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम में राज्यों तथा जनपद स्तर पर

मानवाधिकार न्यायालयों के गठन का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। महिलाओं से सम्बन्धित मामलों की उचित देखभाल हेतु केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर महिला आयोग का गठन भी किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति उत्पीड़न पर रोक लगाना है। अनसूचित जाति तथा जनजाति पर अत्याचार निरोध हेतु अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि मानवाधिकारों की प्राप्ति हेतु हम सदैव संघर्षरत रहे हैं। रूसो ने कहा था कि 'मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है पर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है।' वस्तुतः देखा जाये तो बेड़ियाँ वर्गभेद, वर्णभेद, जाति भेद, लिंगभेद आदि की हैं इनके समापन के लिये हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक तीनों स्तरों पर संघर्ष करना होगा तभी हम एक भेद मुक्त सुखी मानव समाज का निर्माण कर सकेंगे।

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।।

सन्दर्भ

1. शुक्ल यजुर्वेद 36/22
2. ईशावास्योपनिषद प्रथम मंत्र
3. पञ्चतंत्र 4/101
4. दसवैलिक सूत्र 6.9
5- A religion in which the chief points insited upon are that one should deny God, worship man and vermin. – Hopkins "the Religions of India" (p-297)
6- "Man is born free and everywhere he is in chains".
- Rousseau – Social Contkact
7- "The history of all histherto society is the history of class struggle".
- Communist Manifesto (Marx and Engels, selected works Vol.-I, P. 33)
8- Morris D. Morris : Indian Economy in the Nineteenth Century (A Symposium, Delhi 1969).
9. बी0एल0 ग्रोवर एवं यशपालः आधुनिक भारत का इतिहास (पृ–240)
10. तदैव (पृ–245)

SOCIAL CAPITAL, WATER COUNCILS AND COLLECTIVE ACTION

(A Study of Water Council in Hardoi District of U.P.)

-Dr. Anoop Kumar Singh
Assistant Professor (S.G.),
Department of Sociology,
DAV PG College, Kanpur

Most development plans do not succeed because for whom they are ostensibly meant are not at all involved in the planning and implementation process. If the goal of development is human development and not just material growth than the people must participate in the process of development. It is necessary to think of a means of generating self-sustaining efforts so that projects once initiated would go long and produce continuous benefits.

Sustainable development stresses that development must be participating. It must involve local people in the decision – making process that affects their lives. Participation assumed as commitment on the part of the individual towards all forms of actions by which the individual can 'take part' or 'play a role', in the operation without conscious of any socio-economic barriers to achieve certain common goals. The people of all strata should be involved in all stages of the plan process. The dream of participation will become a reality only when the 'top-down approach' which is still prevalent now, is replaced by the 'bottom-up approach'.

A plethora of policies and programmes have sought to accelerate the pace of coverage of drinking water supply and about the irrigation. But somehow the objective of safe drinking water has been met to some extent. But irrigation facilities are not quite enough. According to sources of irrigation dept. of Govt. of U.P. Sharda Canal is only source of irrigation in Hardoi district and 26 miners from Sharda Canal by which most of the agricultural land in being irrigated. But due to improper land reform, the concentration of land of every gramsabha is lies with dominant caste families. So according to rules the time allocated to per person for irrigation will be in proportion to irrigated land per capita viz: 1 Bigha = 1 Hour.

If the ¾ of the one day consisting 24 hours will be in account of one family then what will be for others particularly for the people concerned with lower strata of society (S.C. & S.T.).Some landless laborers attained a small pocket of land for their sustenance of life during the emergency in response to coercive vesectomy. If it will not be irrigated then the texture of soil became barren. That's why the Hardoi district of state is sharing 31% of entire wasteland in U.P. and much more became barrens (usar).

State intervention strategy about irrigation practices in every blocks Hardoi district

are based on roster system and farmers are getting water for irrigation in their turn called ("Osrabandi").

But as said earlier that more landholding means more timeholding and inequality of land lead to inequality of time sharing, result is obviously keep unirrigated land of small and marginal farmers. Despite of keeping attention on the problems of farmers it is unfortunate that state one imposing the inadequate taxes called "TAVAN, on the farmers.

The study framed in the light of some theoretical and empirical case studies.

Theoretical studies which are pertained with the proposed project are Putnam (1993), Coleman (1990) Woolcock (1997), Chopra (2002), Sen & Dreze (2002), Ahmad (2001), Hazare (1992), Santhanam (1990) and the empirical case study pertained with the project are pani Panchayat (water councils) of Naigaon near Pune in Maharashtra where the manifestation of collectivity seeing appropriate move for success watershed development of Ralegaon Siddhi, Maharashtra is another successful story and reflection of sustainable development by participation, the revival of Johad in Alwar, and third one is formation of Village Development Board based on the traditional village council in Nagaland, they are sole responsible for social and economic prospecting in Nagas.

Objectives of the Study :

The present proposed study as stated above to explore the relationship between sustainability and community participation. so these objectives has been set out.

1. To explore the social capital of the members of the water councils

Note : The concept of social capital means here as said J. Colemon that is "Trust, norms and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions. Coleman describes it as an important social structural resource or capital asset for the individual, which is productive, making possible the achievement of certain ends that would not attainable in its absence. There have been various attempts at quantifying and measuring social capital at various levels of aggregation. Social capital is being viewed as on essential component in generating cooperation and collective actions among individuals such as a joint irrigation system can raise agricultural productivity of individual farmers, as well as collective benefit through efficient management of common part resources. It can be instrumental in improving governance at macro-level through the establishment mutual trust.

The role of social capital as the missing link in the development has attracted considerable attention of researcher and policy – makers. Studies of Joyal (2001), Mahapatra (2001), Meyor (2001), Foor(1996), Evary (1996), Ahmad (2001) are the background of social capital researches.

2. To identify the role of weaker section in water councils :

The farmers coming from lower strata of society (especially S.C. & O.B.C. category) contributing at par in the formation and sustaining of water councils. Despite of India

as a country of hierarchies' people is doing relentless efforts across the barriers of caste, religion, and gender in the sustainability of water councils. Equality of rights and sharing of miseries these are also outcome of the water councils.

3. **To describe the relevance of people, participation in other development programmes.**

There is discernible shift towards people's participation and community based management. Firstly, it must be noted that the role of community is being stressed in a general framework of dismantling of the welfare state and rolling back of the state from provision of basic health care and educational facilities, often people's participation is used as a euphemism for shifting of the burden of providing these services from the state to the people. In short people are brought into make the withdrawal of the state more acceptable. Secondly, the community is conceptualized in a simplistic and artificial way with the effect that the intra-community heterogeneity of interests typically gets observed. The structural inequalities of the traditionalist orders continue to obstruct the democratic processes at the grassroots level. In such a context creation of community organization like water – user associations, in the absence of sensitive and imaginative policy designs, may in fact reinforce the existing inequalities across the different social strata.

4. To explore the state intervention strategy in water councils, Rationale of the study :

The study has developed the indicators of social capital to determine the extent of collective action in 05 blocks out of nineteen blocks while its presence could be varies in the presence of contextual and environmental variables in every gramsabha. The study has larger theoretical purpose; to identify the conditions under which social capital can be formed and sustained at the village level to enable collective action. Community participation and sustainable development correlation dealt with the social and economic planning for the upliftment of any society particularly to weaker sections.

This means study focuses on the planning from grass-root level. The organizational set up in councils may be instance for these communities want to develop on their own resources without state intervention.

Research Design & Methodology:

The present study has been formulated in the framework of purposive and explanatory research design. I will concentrate myself on the motivating factors for participation, that's why purposive research design in relevant and to seek micro-explanation explanatory research design in inevitable.

The universe of present study is Hardoi district of U.P., 110 km. from capital Lucknow and 135 Km. from Research Centre Comprises 5 tehsils (Hardoi, Shahabad, Bilgram Sandila, Sawaijpur) and 19 blocks and 1100 Gram Sabhas with the help of random sampling 05 blocks has been selected for study and 25 revenue

villages consisting 50 water councils were in the focus of study. Participation in watershed development programmes were also taken in consideration.

To measure the social capital as dependent variable nine indicators has been selected. The indicators are ranked on a scale of 1 (Short) to 6 (Highest).

a- Social Cohesion

a- Presence or absence of hierarchy, if present how rigid or flexible.
b- The more literate a society, the greater social capital built.
c- Women in leadership.
d- Facilitating role in establishing and supporting water councils.
e- Commitment of community to protect its public resource.
f- Willingness to sacrifice personal gains for greater community benefits.

Tools of the study :-

To get proper answers from respondents' interview schedule was constructed; because of field based nature of study participant observation is inevitable. After collection of data it examine for completeness and generalization by statistical techniques.

Due to village study P.R.A. (Participatory rural appraisal) was conducted.

P.R.A. Participatory rural appraisal comprises a set of techniques aimed at shared learning between local people and outsides P.R.A. is being used not only in rural setting and not only project appraisal but throughout the project cycle.

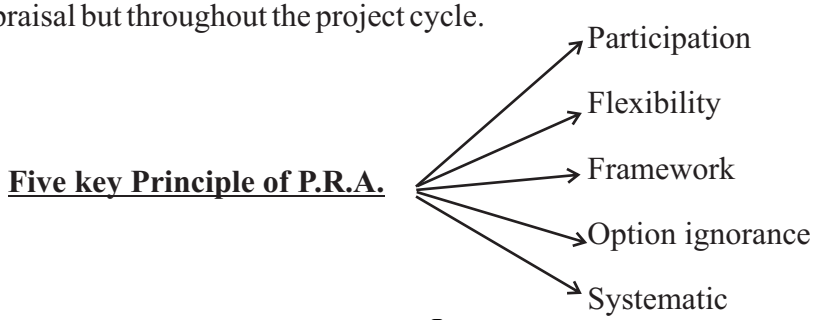

Social capital has been conceptualized as an input into the process by which institutions for development are created and which can determine the sustainability or otherwise of process aimed at achieving development at local levels. In our analysis social capital is the dependent variable – i.e. its presence and functioning depends on the presence of contextual and environmental variables existing in the selected water councils of villages. Thus the project has a larger theoretical purpose : to identify the conditions under which social capital can be formed and sustained at the village level to enable collective action.

A framework of social capital is useful for our study because evaluation of water councils/WUA's (water users association) and watershed programmes have shown that these cannot succeed without full participation of the local people and careful attention to issues of social organisation. In my study through non-participant observation and structured interview schedule water councils/WUA's of Madhoganj Blocks implies that a growing stock of social capital is a vital input, which needs to be accumulated and nurtured over time why there is need of water councils, while irrigation department of U.P. has responsibility to provide water for irrigation but state has been fail to provide facilities to farmers. So community management in form of water councils/WUA's is emerged in the study area.

Structural and Institutional aspect of water councils/WUA's :

In surface irrigation there is low level of water control. The first is on delivery and distributory system and the second is at the farm level. Generally, govt. is responsible for the former part of system. Responsibility of farmer is at the farm level. Therefore the participation of farmers in irrigation management at the farm level is logical. For instance while roster system of irrigation could get failed if irrigation officers make hurdle in the process.

Irrigation system tends to become more a social organization. The operation and maintenance of physical system and use of water on the field, a continuum of irrigation activities need an organizational framework of rules, roles and groups. Therefore, it has to be decided whether an operational unit takes.

(a) Spatial coverage of area irrigated

(b) Number of beneficiaries

(c) A section of water distribution network into account.

The former two segments mentioned above as units for forming a council, for they are likely to cut across outlets and distributaries. Then obvious choice is a distributory or outlet. outlet may not be viable unit. Because normally an outlet is expected to irrigate about 40 hectares of land covering 20-25 farm land-holding. So distributory is a ideal unit for forming a council.

TOP-DOWN APPROACH

Organizational Plan of Water Councils/WUA'S FUNCTIONING OF WATER COUNCILS SHARDA CANAL/OR COMMUNITY BASED PONDS

Organizational Plan of Water Councils / WUA's

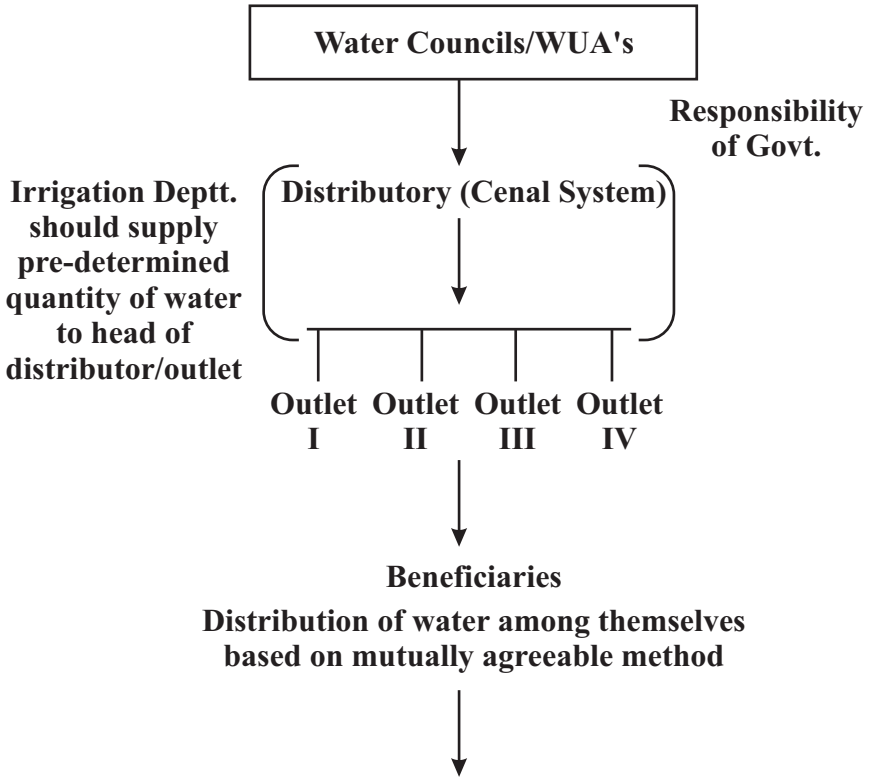

FUNCTIONING OF WATER COUNCILS SHARDRA CANAL/OR COMMUNITY BASED POND

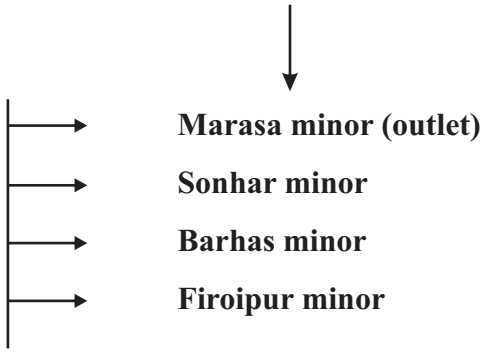

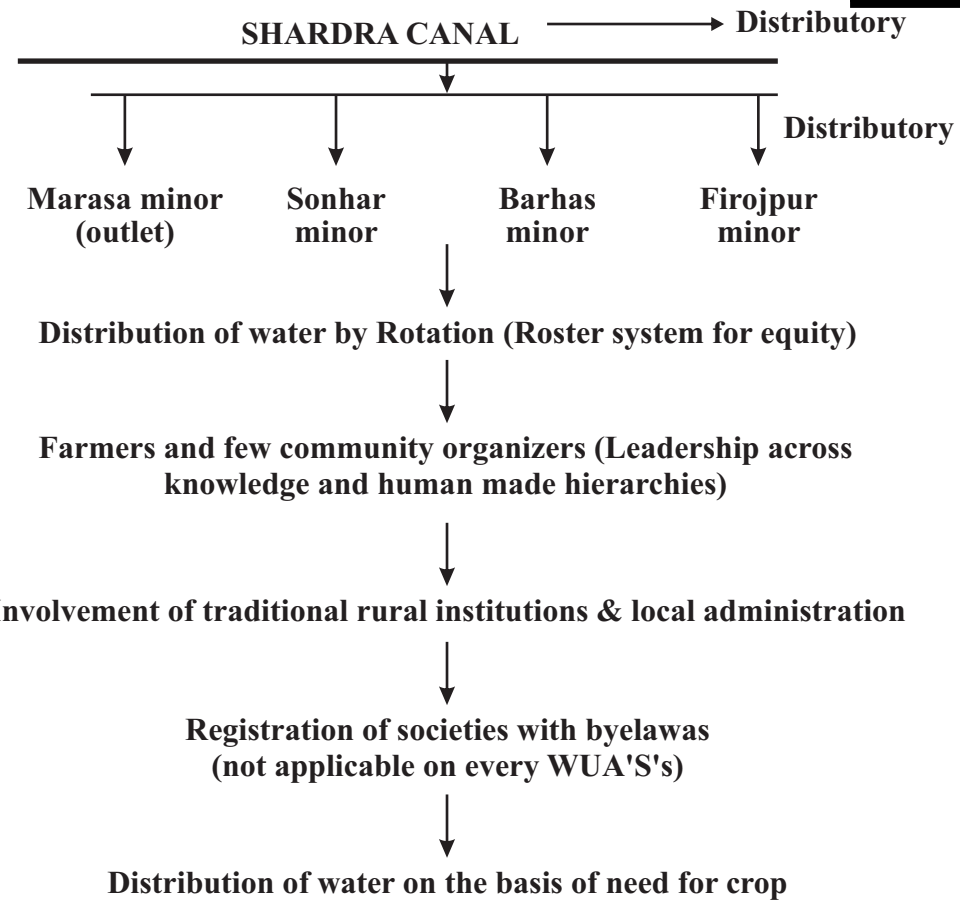

Social Capital in the sampled water councils of sampled villages :

Here we explain reasons for the success of water councils/WUA"s in Doulatyarpur, Shuklapur Bhagat and Khemipur relative to Daulatpur and Rudamau. It is obvious here that in every village there is two water councils. We have also discussed the indicators developed to explain the level of social capital and collective action or community participation.

(1) Social structure of sample villages

Village studies in India in the post-independence period have highlighted two significant features : traditional ascriptive hierarchies based upon caste and endemic factionalism. Much of the literature show that dominant caste/clan groups have been able to capture most of the benefit of Govt. Development Programmes. Studies have also shown that these features have destroyed trust and social capital in villages mapping collective action very difficult. In contrast, the social structure and features of the villages in which WUA's is existing have promoted social capital and collective action for sustainable development.

A number of traditional village institution and leaders promote this : Despite of PR and several faction of change traditional village council, (Panch), Headman (Mukhia), and

spiritual guardian of village (Hardevraja and Marhidevi) customary rules exist which are strictly followed under which villagers are obliged to attend the meetings of the Panch, respect its decisions, and help to implement them. Some how factionalism is absent in Daulatyarpur, Shuklapur Bhagat, and Khemipur while Daulatpur and Rudamau are not having to some extent the level of social capital. The absence of 'natural hierarchies' combined with little difference in land ownership education or life- style has helped in community participation based on trust between the villagers.

Local Leadership :

Strong and effective community leadership, along with a favourable social environment has been responsible for building social capital and ensuring collective action in sample villages.

Among the all five villages and Ten water councils traditional leader are respected and listened to carefully and their directions on request compiled with. The headman of water councils usually the person who initiate for the cause it could be from S.C. category, women on belongs to upper caste but mostly the aged person holds the post of president of council.

It was observed in my field study that these water councils are not registered formally, however it is based on mutual agreement and proper DAM (Distribution Allocation and Management) of water. The govt. mechanism is not properly providing adequate water to him.

Women's participation and collective action :

Existing literature shows that active participation of women encourage, communities to conserve natural resources including water. Women from every strata of society across natural and knowledge hierarchies are participating in the community based development programmes. It was amazing that out of ten councils four are leading by women, and they played an important role in its formative stage in 1993. So there is a marked increase in the level of involvement of the village women in the planning and execution of various works, which has led to their integration into the decision- making process with in community. There is also greater gender sensitivity.

Accountability and transparency in the bodies of water councils

Our study shows that accountability and transparency are necessary to create mutual trust among the councils and with the other villager in the voluntary programmes for villages such as Pond Construction, Watershed Development waste land development and community centers. Apart from this MOU between irrigation department and water councils when set-up is also signed which is kept in records.

Information about the working of water councils/other programmes among respondents

Awareness about	Daulatyarpur		Shuklapur Bhagat		Rudamau		Khemipur		Daulatapur	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1. Meeting held (Every Saturday & wednesday)	48	2	47	3	48	2	45	5	48	2
2. Are there any initiative taken for wrong 'TAVAN'	15	35	20	30	15	35	16	34	25	25
3. About community based Pond, and community centre activities	45	5	40	40	45	5	40	10	25	25

Notes :- TAVAN : Irrigation department imposes the tax on illegal irrigation of land except irrigation tax.

MEASURING SOCIAL CAPITAL IN FIFTY WATER COUNCILS OF TWENTY FIVE VILLAGES

Our study shows that the presence of social capital is crucial for the successful functioning of participatory programmes such as water councils /WUA's. The first reason is the shift from an earlier uniform, centralised and bureaucratic management of natural regencies by the state to joint management with village communities. This shift require, a partnership between community institutions such as water councils and local officials for sustainable management of water and other resources based upon trust, dialogue, and mutually defined rights and responsibilities. Clearly, a synergy between state and civil society is needed.

In my proposal of social capital I have taken in consideration nine indicators but after field study there were another important variable that must be there in measurement of social capital that is norms and values that facilitate exchanges.

MADHOGANJ – DEVELOPMENT BLOCK

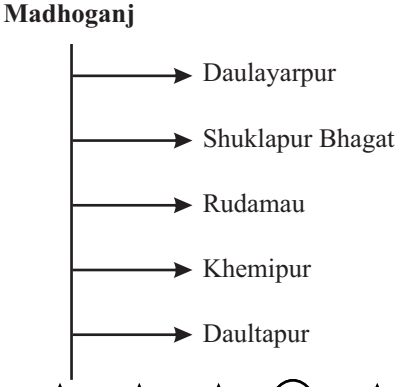

Then ten indications as dependent variable have been selected. The indicators are ramped on a scale of 1 (Lowest) to 6 (Highest).

Social Capital indications	Daulatyarpur	Shuklapur Bhagat	Rudamau	Khemipur	Daulatapur
1. Social cohesion	5.5	5.5	4.5	5.5	1.5
2. Education/Literacy level	5.0	4.0	3.5	5.0	2.5
3. Local Leadership	5.5	6.0	5.5	4.5	2.5
4. Active role of women	6.0	6.0	4.5	3.5	4.5
5. Accountability and transparency of local institution	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5
6. Collective action in conserving resource	6.0	5.0	4.1	4.3	4.0
7. Trust with in community	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0
8. Keeping long term interest of village	5.5	6.0	4.5	4.5	4.0
9. Democratic functioning of local institutions	4.0	6.0	4.5	4.5	6.0
10. Norms and values that facilitates the exchange	6.0	6.0	5.0	5.0	4.5
Total	54.5	54.0	45.1	45.1	40.0

BILGRAM – DEVELOPMENT BLOCK

Bil Gram

- Chacharapur (Thakurs) Dominant
- Pindars (S. C. Dominants)
- Jalalpur (O.B.C. Dominants)
- Parsola (Thakurs), Dominants
- Deewali (Pathans) Dominents

No. of water councils	Name of Village
03	Chachrapur
02	Pindars
03	Jalalpur
02	Parsola
03	Deewali

Social Capital indications	Chachrapur	Pindars	Jalalpur	Parsola	Deewali
1. Social cohesion	6.0	5.0	6.0	5.5	5.0
2. Education/Literacy level	5.5	6.0	5.0	6.0	5.0
3. Local Leadership	4.5	4.0	4.0	5.5	6.0
4. Active role of women	5.0	4.5	5.0	5.5	6.0
5. Accountability and transparency of local institution	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0
6. Collective action in conserving resource	5.5	5.5	5.0	6.0	5.5
7. Trust with in community	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0
8. Keeping long term interest of village	6.0	5.5	5.5	6.0	5.0
9. Democratic functioning of local institutions	5.5	4.5	5.0	5.0	5.5
10. Norms and values that facilitates the exchange	5.5	5.0	4.5	3.5	5.0
Total	54.5	50.5	51.0	53.0	43.0

Measuring Social Capital of Sandila Block

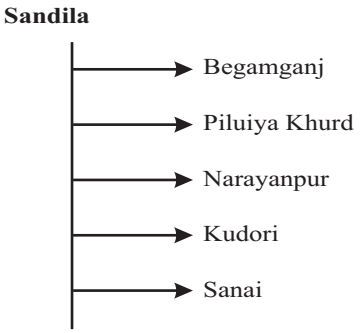

Social Capital indications	Begamganj	Piluiya Khurd	Narayanpur	Kudori	Sanai
1. Social cohesion	5.0	6.0	5.0	6.0	5.5
2. Education/Literacy level	4.5	5.0	4.5	4.0	4.5
3. Local Leadership	5.6	6.0	4.5	5.5	5.5
4. Active role of women	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0
5. Accountability and transparency of local institution	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5
6. Collective action in conserving resource	6.0	5.5	5.5	6.0	5.5
7. Trust with in community	5.5	5.5	6.0	5.0	5.0
8. Keeping long term interest of village	5.5	5.0	5.5	5.4	4.5
9. Democratic functioning of local institutions	6.0	5.5	4.0	4.5	5.0
10. Norms and values that facilitates the exchange	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0
Total	**55.6**	**54.5**	**51.5**	**52.9**	**52.0**

Measuring Social Capital of Mallanwa Block

Mallanwa

- Barsa
- Kanthani
- Purbama
- Raghavpur Thethia
- Goswan

Social Capital indications	Barsa	Kanthani	Purbama	Raghavpur Thethia	Goswan
1. Social cohesion	6.0	6.0	5.5	5.0	6.0
2. Education/Literacy level	5.0	5.5	5.0	5.5	4.5
3. Local Leadership	4.5	5.0	5.0	5.5	5.5
4. Active role of women	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5
5. Accountability and transparency of local institution	6.0	6.0	5.5	5.5	5.0
6. Collective action in conserving resource	5.5	5.5	6.0	5.5	5.0
7. Trust with in community	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0
8. Keeping long term interest of village	5.5	5.5	6.0	5.5	4.5
9. Democratic functioning of local institutions	5.5	6.0	5.5	4.0	6.0
10. Norms and values that facilitates the exchange	6.0	5.5	5.0	5.5	6.0
Total	**55.0**	**56.0**	**54.0**	**54.0**	**54.0**

Measuring Social Capital of Ahirori Block

Ahirori

- Kaimau
- Lokwapur
- Bheethadan
- Thokmadho
- Ahirori

Social Capital indications	Kaimau	Lokwapur	Bheethadan	Thokmadho	Ahirori
1. Social cohesion	6.0	5.5	5.0	5.5	6.0
2. Education/Literacy level	5.5	5.0	5.5	6.0	5.5
3. Local Leadership	6.0	5.0	5.0	5.0	4.5
4. Active role of women	5.5	5.0	4.5	4.5	5.5
5. Accountability and transparency of local institution	6.0	5.5	5.0	5.0	6.0
6. Collective action in conserving resource	5.0	5.5	5.5	6.0	5.5
7. Trust with in community	5.5	6.0	5.5	5.0	4.5
8. Keeping long term interest of village	6.0	5.5	5.5	5.0	5.5
9. Democratic functioning of local institutions	5.0	4.5	5.5	4.5	5.0
10. Norms and values that facilitates the exchange	5.5	5.0	5.0	4.5	6.0
Total	**56.0**	**52.5**	**52.0**	**52.0**	**54.0**

The idea that the farmers should participate in irrigation management has grown in India since 1980 through formally adopted in National Water Policy, 1987 and the eighth plan. Farmer's perspective in satisfaction of his genuine need for irrigating his fields. He wants equity in distribution of water if it is scarce specially at tail end. Hence, he wants Water Users Association (WUA's) or water councils. While none seem to object formation of water user association, the crux lies in its orientation. Whether water councils are formed to be used as tools by the govt. to fulfill its objectives or to develop them as a power base or to empower the community to take over management of water resources.

Study shows that the national water supply system locally called 'OSRABANDI' was implemented. It was found that there was an agreement among the formers that upstream farmers would draw water up to lunch and down stream farmers after lunch.

It either of them fail, the villagers of the other area repair the cut and nobody would object people were assumed of sufficient water.

Project study shows that the presence of social capital is crucial for the successful functioning of water councils. The first reason is the shift from an earlier uniform, centralized and bureaucratic management of natural resources by the state to joint management with village communities. This shift requires a partnership between community institutions and local officials for sustainable management of water and other resources based upon trust, dialogue and mutually defined rights and responsibilities. Clearly, a synergy between state and civil society needed. The new forms of management require a shift from “conflict to collaboration”. The presence of social capital helps to bring

about this shift. There is now growing acceptance that while officials can handle the technical aspects of resources management, the social relationships are for more challenging. As I told earlier that 10 indicators of social capital has been used.

In Madhoganj Block Daulatyarpur and Shuklapur Bhagat in the store of social capital with 54.5 point each or an average of 5.4, Rudamau and Daulatpur is way down with 45.1 and 40 point respectively indicating a low stock of capital. Participatory programmer such as water councils, watershed programme are being set in many part of country Similarly in Bilgram Block Chacharapur and Parsola having 54.5 and 53.5 points stock of social capital depicts 51 and 50.5 point stock of social capital but pathan dominant Deewali is way down having 43 point stock capital. Sandila Blocks consisting five revenue villages Begemganj, Piluiya Khurd, Narvanpur, Kudori, Sanai. In Begamganj and Piluiyakhurd the stock of social capital was 55.6 and 54.5 points respectively. While Kudori and Sanai his similar stock of social capital it is 52.5 Mallanwa is historical and significant block in terms of irrigation system, because community based several initiatives were going on in the studied village. Kanthani is model revenue village in the district for the social and economic development and community based tubewells, institution and self-help groups formed by local educated youths was because of maximum stock of social capital in all studied villages and it was 56.5 points.

In other four villages the status of social capital was almost same, and it was 54 points. In Ahirori Block the roaster system of irrigation is amazing that no one conflict has been recorded by police on water dispute issue Kaimau is well connected with Sharda Canal and social structure of village encourages people for collective action, that why the stock of social capital is high in the village and it is 56 points while in other villages it is average 5.2 points.

Some lessons drawn from the experiences of our sample villages may be relevance to other part of India. Three features – Social Cohesion, effective local leaderships and supportive role of local bureaucracy, play a crucial role in the success or failure of water councils or watershed programme.

Programmes in resource conservation have to function in diverse social situations. Own study suggests that collective action is successful where an underlying tendency for united action already exist in a community based on cultural values, common identity, a tradition of participation and shored historical experiences. Where social cohesion is week, effective village leadership and support of local officials can help in building community solidarity. The formation of a number of self-help group under the three blocks has helped in establishing a more broad based representative and participatory management system. In some others issues concerning with conservation of natural resources leads due to strong leadership in the villages.

The experience of Ahirori Block indicates that how, non-traditional community institutions break down when the majority loses its confidence in the leaders unable to find ways to redress their grievances, decide to withdraw from participation.

In conclusion, study shows that social capital exists in varying degrees in our sampled villages for the purpose of collective action. The term public has become a part of the lexicon and villagers are quick to assemble for meetings. A notion of collective village interest exists, even if largely in the economic sense building a democratic social capital which involves all individuals and all social groups particularly in villages such as ten to twelve villages in not easy; it requires much hard work : mobilisation on the part of leaders, support and advice from the local officials, and an understanding of the benefits of collective action on the part of the village community.

REFERENCES

1. Bamberger, M., & Cheema, G., Case Studies of Project Sustainability; implications for Policy and Operations from Asian Experiences, EDI, World Bank, Washington D.C. 1990.
2. Coleman, J.S. "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, 94 (1988).
3. Harington, A.H.; Report of the regular settlement of the Hardoi district (1980), P.P. 99.
4. Hazare, K.B. "Watershed Development – The only Alternative for Eradication of Drought" Abhigan, Autumn, 1992.
5. Neviee, H.R., Hardoi : A Gazetteers, 1904
6. Putnam, R. Making Democracy work : Civic tradition in modern Itly, Princeton, University Press, 1993.
7. Rahman, Md and Pangare V "Peoples Participation Micro Watershed Development : Ralegaon Siddhi Experiment, Watershed News, Aug-Oct. 1992.
8. Santhanam M.L. & Jahagirdhar, M.P. "Village Development Boards Nagaland Experiment in Community Participation. Journal of Rural Development, 4(3), 1985.
9. Santhanam M.L. & Namasivayam D. "Correlates of People's Participation". Social Change, 20(1), 1990.
10. Santhanam M.L. "Community Participation – Case Study", Social Change, 14(2), 1984.
11. Santhanam M.L. "Human and Social Factors in People's Participation, Journal of Rural Development, 1(5) 1982".
12. Santhanam M.L. Vikram Singh & Gulab Singh Azad "Rural Groups – A Study of Behavioral and international Patterns'. Journal of Rural Development 9(4), 703-717, 1, 1990.

सिद्धांत
DOCTRINE
त्रैमासिक शोध जर्नल

सदस्यता फार्म

नाम .....

पिता / पति का नाम .....

शैक्षिक योग्यता एवं पद .....

जन्मतिथि .....

पता : विद्यालय / यूनिवर्सिटी / संस्थान .....

.....

आवास .....

.....

फोन नं0 / मोबाइल नं0 .....

ई–मेल .....

सहयोग राशि (नकद / मनीआर्डर / ड्राफ्ट / चेक) .....

तिथि ..... हस्ताक्षर .....

(सदस्यता फार्म की छाया प्रति स्वीकार्य है)